हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17 मार्च 1983

खण्ड 1, अंक 9

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 17 मार्च 1983

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(9)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(9)25
विभिन्न विशयों का उठाया जाना–	
(1) सै ान का बढाने संबंधी	
(2) बिक्री कर बैरियर मुंडका (गुड़गांव) में पुलिस द्वारा ट्रक आपरेटरों को तंग करने संबंधी	(9)30
(3) चन्दों कलां के बारे में गुरनाम सिंह जांच आयोग संबंधी	(9)30
(4) सै ान का बढाना (पुनरारम्भ)	(9)30
	(9)31
गैर सरकार बिल (लीव टू इन्ट्रोडयूस रीफ्यूज्ड)–	(9)33
दी हरियाणा अर्बन (कंट्रोल आफ रैंट एंड इविक ान)	

अमैंडमैंट बिल 1983	
गैर सरकारी संकल्प– अम्बाला जिले की अम्बाला तहसील को औद्योगिक दृश्टि से पिछडा घोशित करने संबंधी (पुनरारम्भ)	(9)36
वाक आउट	(9)48
गैर सरकार संकल्प (पुनरारम्भ)	(9)48

हरियाणा विधानसभा

वीरवार, 17 मार्च 1983

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधानसभा हाल, विधान भवन, सैक्टर –1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Quesion Hour.

***106.. Shri Kitab Singh:** Will the Minister of State for Public Health be pleased to state-

(a) the number of water works constructed in ADampur and Gohana constituencies, separately, during the period forem 1-7-1979 to 30-10-1982 towgetherwith the expenditure incurrred thereon, separately;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to supply drinking water to such villages where the same is not available in the State; if so, the time by which the water if likely to eb supplied; and

(c) whether the Government proposes to provide flush system in the rural areas in the State ?

Mr. Speaker: Extension has been asked for to answer this question which has been granted. The communication recieved from the Hon'ble Minister in this connection reads as under-

***Interim Reply**

D.O. 25-MPH-83/1-16-3-83

Public Health and Development

& Panchayats.

Respected Sardar Sahib,

The information relating to Starred Question No. 106 is to be collected from the field which requires sufficient time.

I, therefore request you kindly to extend the time of its reply for 14 days more. As and when the information is collected. I shall supply the same to the Vidhan Sabha Secretariat.

With kindest regards,

Yours Sincerely,

Sd/-

(Lal Singh)

S. Tara Singh JI,

Hon'ble Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

श्री मंगल सैनः कब तक के लिए एक्सटैं ान दी है ?

श्री अध्यक्षः एक्सटैं ान दो हफ्ते की दी है। इसका उत्तर आपको पहुंच जाएगा।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इसा क्वै चन में आदमपुर और गोहाना कांस्टीच्युऐंसीज इन्वाल्ड हैं क्या अगले हफ्ते जवाब देने का मतलब यह है कि चालू सै ान के दौरान जवाब दे दिया जाएगा ? (व्यवधान)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): कोि ा ा करेंगे। एक्सटैं ान दो हफ्ते की मांगी है।

श्री मंगल सैनः नहीं जी, इसका जवाब इसी सै ान में आनाा चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैं इसको देख लूंगा।

S.K.L.

/108. Sh. Mangal Sein, Sh. Roshan Lal Aray, Sh. Fateh Chand Vij: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether any payment has been made to the Punjab Government for digging of the Satluj Yamuna Link Canal in Punjab area;

(b) if so, the total amount so far given togetherwityh the dated thereof;

(c) the total length of canal to be dug in Punjab area togetherwith the length of the canal which has been dug so far; and

(d) the time by which the construction of the said canal is required to be completed under the agreement ?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala):

(a) Yes.

(b) An amount of Rs. 20.50 crores has been deposted by the Haryana Government with Punjab Government as per details given below –

Sr. No.	Date of Payment	Amount in Crores
1	16.11.1976	1.00
2	31.3.1979	1.00
3	25.1.1982	2.00
4	4.3.1982	4.00
5	26.8.1982	7.50
6	20.101982	5.00
	Total	20.50

(c) The total length of the canal to be constructed in Punjab was originally 107.25 Kms. but due to the proposed revision in the alignment susbsequently the length is likely to be 112 Kms. Earthwork is in progress in the last 2 Kms. from Haryana Boarder and about 20 lacs cft has been dug.

(d) As per agreement signed on 31.12.1981 the work is to be completed within 2 years from the date of agreement by the Punjab Government.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इनके एग्रीमैंट के मुताबिक तीन महीने के बाद वक्र को रिव्यू करने का प्रोविजन है। क्या मंत्री महोदय बताने की तकलीफ करेंगे कि क्या उन्होंने वर्क को रिव्यू किया है तथा इस सिलसिल में गवर्नमैंट आफ इंडिया द्वारा बनाई गई कमेटीज की कितनी मीटिंग्ज हुई हैं ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, एग्रीमैंट के अनुसार एक मोनिरटरिंग कमेटी और दूसरी टैक्नीकल कमेटी बनी हुई है। मोनिटरिंग कमेटी वक्र की प्रोग्रैस को मोनिटर करती है, वर्क को वाच करती हैं टैक्नीकल कमेटी के चेयरमैन सैंट्रल वाटर एंड पावर कमी ान के चेयरमैंन हैं। दूसरी कमेटी के चेयरमैन गवर्नमैंट आफ इंडिया के इरीगे ान डिपार्टमैंट के सैक्रेटरी हैं। दूसरी कमेटी यानी मोनिटरिंग कमेटी की 5 मीटिंगज और दूसरी की दो मीटिंगज पिछले दिनों में हो चुकी हैं और यह कमेटी तकरीबन दो महीनें के बाद काम की प्रोग्रेस को रिव्यू करती है।

श्री फतेह चंद विजः मन्त्री महोदय ने बताया है कि इन दोनों कमेटियों की मीटिंग्ज अभी अभी हुई है। क्या आप बताएंगे कि ये कमेटियां किस तारीख को बनाई गई थी ?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब अभी अभी का लफ्ज मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने कहा है कि इन कमेटियों की इस दौरान कई मीटिंगज हो चुकी हैं। यह एग्रीमैंट 1981 में हुआ था और उस एग्रीमैंट में ही कमेटियां बनाने का प्रावधान है। उसी वक्त से ये कमेटियां बनी हुई हैं। इनकी मीटिंग्ज महीने डेढ महीने के वक्फे के बाद लगातार हो रही हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि अलाईनमैंट की जो चेंज की जा रही है, यह कब फाईनल हो जाएगी और नहर की जो खुदाई भाुरू की गई है यह किस तारखी को भाुरू की गई ?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय पंजाब के एरिया में 26 किलोमीटरि से 66 किलोमीटर तक चेंज आफ अलाईनमैंट है। चेंज आफ अलाईनमैंट इसलिए प्रपोज की गई है क्योंकि जो पहले अलाईनमैंट थी उसमें डीप कटिंग पडते थे। इसके इलावा इसके बदलने से कम से कम 30–40 करोड रूपए की खर्च में कमी हो सकती है। नहर को बनाने में भी कम टाईम लगेगा। हरियाणा सरकार ने चेंज आफ अलाईनमैंट की एप्रूवल दे दी है और इस पर भी कार्यवाही बहुत जल्दी ही भाुरू हो जाएगी।

श्री वीरेन्द्र सिंहः यह तो आपने बताया ही नहीं कि खुदाई किस तारीख से भुरू हुई थी ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः जो पो र्न पहले एक्वायर हो चुका था उस पर खुदाई भुरू हो गई थी और यह खुदाई उसी दिन से भुरू हुई थी जिस दिन प्राईम मिनिस्टिर महोदय ने इन्आउग्रे ान की थी।

डा0 भीम सिंह दहियाः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो टैक्नीकल ओर मौनिटरिंग कमेटीज हैं इनमें हरियाणा प्रान्त का क्या रिप्रेजैंटे ान है ? क्या इस काम की सुपरविजन के लिए हमारा को स्टाफ रहता है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, इन टैक्नीकल और नान टैक्नीकल कमेटियों में हरियाणा के इरीगे ान एंड पावर कमी ानर इंजीनियर इन चीफ और दूसरे भी कई आफिसर जाते हैं।

श्री मंगल सैन अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने फरमाया कि जब प्राईम मिनिस्टिर महोदय ने उदघाटन किया था तब से जोर भाोर से काम भुरू हो चुका हे।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः मैंने जोर भाोर से बिल्कुल नहीं कहा। जोर भाोर से तो कह रहें हैं (व्यवधान)

श्री मंगल सैन:जोर भाोर से न सही मैं यूं कह देता हूं कि जब सै प्राईम मिनिस्टिर महोदय ने इनआग्रे ान किया है, तब से यह काम बडी ढीला और लापरवाही से हो रहा है। (व्यवधान)

Mr. Speaker: The hon'ble Minister is very conscious about the words.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो इनकी फास्ट मूविंग प्रोग्रैस है, जो दो साल में पूरी होनी है, एग्रीमैंट के मुताबि 112 किलोमीटर नहर खोदनी है यहा कितने दिनों में बन जाएगी ? पंजाब से हरियाणा बार्डर तक यह नहर आनी है और 2 किलोमीटर नहर को खोदने के लिए 14 महीने 17 दिन लगे हैं। जिस तेजी के साथ खुदाई की रफतार चल रही है, क्या आपने इसके बारे में सैंट्रल गवर्नमैंट को कोई ि ाकायत की है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, ि ाकायत करने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि लैण्ड लैंथ यानी जमीन पहले ही एक्वायर हो चुकी थी, पोजै ान हो चुका था। अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस को बताना चाहूंगा कि जीरो से 26 किलोमीटर लैंथ का पोजै ान लिया जा चुका है। और 66 किलोमीटर से 107 किलो मीटर तक का जो पोजै ान है, वह जब सवाल पूछा गया था और गवर्नमैंट ने जवाब दिया था, उस वक्त तक it was about to be taken. अब तक पोजै ान हो चुका होगा। जहां तक इस काम में ज्यादा टाईम लगने का संबंध है। अध्यक्ष

महोदय, मैं आनरेबल मैम्बर को बताना चाहूंगा कि इतने बडे मेजर काम को करने के लिए डिवीजन वगैरा क्रिएट करने के लिए, स्टाफ की पोस्टिंग करने के लिए, मैटीरियल कुलैक्ट करने के लिए और म ाीनरी कुलैक्ट करने के लिए 7–8 महीने का टाईम तो नौर्मली जग जाता है। अगर यही काम हरियाणा गवर्नमैंट ने ही करना होता हो भी इतना टाईम जरूर लग जाता।

श्री नेकी रामः अध्यक्ष महोदय, एस0वाई0एल0 नहर की सुपरविजन के लिए क्या पंजाब और हरियाणा के एम0एल0ए0 साहिबान भी इन दो सैंट्रल कमेटियों में मैम्बर के तौर पर लिए जाएंगे। (व्यवधान)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, ये क्या पूछ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं लगा। (व्यवधान)

श्री नेकी रामः मैं यह पूछा रहा हूं कि क्या एम0एल0ए0 साहिबान को भी इन कमेटियों का मैम्बर बनाने का इरादा रखते हैं ? यह नहर दो साल में बननी थी, क्या अब भी दो ही साल लगेगे या पहले बन जाएगी ?

श्री भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैम्बर बनने का सवाल है, वे पहले ही इस हाउस के मैम्बर हैं और यह हाउस सबसे सुप्रीम होता है। इन्होंने पूछा है कि इसके बनने में कितना टाईम लगेगा। जैसा कि मैंने बताया है कि तकरीबन जमीन की एक्युजी ान हो गई है और वर्क अलाटमैंट का काम भी

पूरा हैं खुदाई भाुरू होने के बाद एक साल में काप पूरा हो जाएगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: मंत्री महोदय ने जवाब में बताया है कि साढे बीस करोड रूपया दिया जा चुका है। मैं मुत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिज कितने हुए और मिटटी की खुदाई पर कितना खर्च हुआ है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: इस साढे बीस करोड रूपए की डिटेल मेरे पास इस वक्त नहीं है। अगर इस बारे में सवाला होता तो मैं डिटेल लेकर आता। वैसे इस में स्टाफ की तन्खाह भी भाामिल है, म ाीनरी पर जो खर्च हुआ है वह भी है और जो जमीन इक्वायर कर ली गई है भाायद उसका भी कुछ पैसा भाामिल है।

श्री कंवल सिंह: क्या मंत्री महोदय के नालेज में है कि 34 लाख रूपये कारों और जीपें खरीदने के लिए खर्च किया गया है और इससे भी कहीं ज्यादा रूपया पो ा सैक्टर 17 पर खर्च किया है। जिसमें एक्सीयन, एस0ई0 वगैरह बैठते हैं ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: हमने अब तक पंजाब सरकार को साढ़े बीस करोड रूपया दिया है जबकि यह प्रोजैक्ट दौ सौ करोड रूपये का है। अगर उन्होंने 34 लाख रूपया जीप और कारें खरीदने पर लगा दिया है तो यह बहुत डिस

प्रोपोर ोनेट नहीं है। अगर आप कोई ि ाकायत नोटस में लायेंगे तो हम जरूर गौर करेंगे।

Smt. Chandravati: What about the posh office which has been opened in Sector 17.

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः हमने तो इसे देखा नहीं अगर आप में से किसी ने देखा है तो बता दें।

श्री भले रामः क्या मंत्री महोदय बताएंग कि जब यह नहर बन कर पूरी हो जाएगी तो इसको पानी सभी जिलों को मिलेगा या किसी खास एरिया को ही दिया जाएगा ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः खास तौर पर जहां लिफ्ट कैनाल स्कीम हैं, वहां दिया जाएगा और जो बाकी बचेगा वे दूसरे एरिया में भी दिया जाएगा जहां पानी की कमी है।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, जब इस नहर के बनने में इतनी डिले हो रही है कि सवा साल में केवल फारमैलिटी ही पूरी हुई है तो क्या हरियाणा गवर्नमैंट, केन्द्रीय सरकार से रिकवैस्ट करेगी कि यह काम पंजाब सरकार से लेकर अपने हाथ में ले ले या किसी और को सौंप दे ताकि यह काम जल्दी से पूरा हो सके ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः यह काफी सेंसटिव बात है। जैसा आप सबको मालूम है कि सरकार भी चाहती है और हरियाणा के लोग भी चाहते हैं कि यह नहर जल्दी बने। अगर

किसी इनडिपैंडैंट म ाीनरी की जरूरत समझी गई तो उसको भी दिया जा सकता है। गवर्नमैंट आफ इंडिया हरियाणा सरकार को भी दे सकती है हमारे मुख्य मंत्री इस बारे मैं कई बार कह चुके हैं कि काम में देरी हो रही है। यह काम बी0बी0एम0वी0 और बी0एम0वी0 को भी दे सकती है।

श्री मंगल सैनः क्या सरकार ने इस बारे में गवर्नमैंट आफ इंडिया से रिक्वैस्ट की है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः गवर्नमैंट आफ इंडिया हरियाणा सरकार को भी यह काम दे सकती है या किसी और को भी दे सकती है।

श्री फतेह चन्द विजः जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि उम्मीद है एक साल में काम मुकम्मल हो जाएगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक साल में काम भाुरू ही नहीं हुआ तो मुकम्मल कैसे हो जाएगा ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः इस चीज को कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि काम पूरा न हो।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब एस0वाईएल0 के लिए तीन करोड रूपये के स्टाफ क्वार्टर बनाए गए हैं। चार चीफ इंजीनियर, 16 एस0ई0 40 एक्सीयन और एक हजार दूसरे इंजीनियर्ज वहां पर लगाए हुए हैं तो मैं मंत्री महोदय

से जानना चाहता हूं कि जब वे काम ही नहीं कर रहे तो इन पर यह पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः आपका सवाल ही मेरी समझ में नहीं आया। जब भी कोई प्रोजैक्ट भुरू होता है तो उसके लिए स्टाफ क्वार्टरज की भी आव यकता होती है और स्टाफ की भी आव यकता होती है। वहां पर जल्दी से काम भुरू हो जाएगा।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब मंत्री महोदय को यही पता नहीं कि वहां पर कितना स्टाफ लगा हुआ है। स्टाफ के बारे में तो मिनिस्टर साहब को नालेज होना चाहिए।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, बहिन चन्द्रावती जी, डाक्टर मंगल सैन और चौधरी देवी लाल जी को पता है और वे भारत सरकार के साथ हुई मीटिंग में जाते रहे हैं। बहुत डिटेल्ज में सारी बातें हुई है।। पानी के मामले में जो भी बात हुई है उन्हें मालूम है और हमारा स्टैंड फर्म है। इस बारे में चौधरी भाम ोर सिंह जी ने भी हाउस के सामने सारी बातें डिटेल में बतायी हैं। आप जानते हैं कि जब जमीन इक्वायर न हो तो नहर पर काम कैसे भुरू होगा ? पंजाब सरकार ने जमीन इक्वायर करने का तकरीबन काम कम्पलीट कर लिया हैं भारत सरकार सारी बातों को खुद देखती है कि वहां पर कितना स्टाफ लगाना चाहिए और अब कितना लग रहा है। अगर वहां पर कोई कोताही हुई है

तो उस गलत बात का भारत सरकार मानने वाली नहीं। जहां तक इस बात का डर है कि पंजाब सरकार उसके बनाने में डिले करेगी और समय पर कम्पलीट नहीं करेगी उसके बारे मकें मेरी अर्ज यह है कि जिस टाईम पर वहां पत्थर रखा गया था तो उस टाईम पर यह कहा गया था कि दो साल के अंदर यह नहर बननी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पांच लाख लोगों की हाजिरी में यह कहा था कि दो साल में यह नहर बन कर पूरी हो जाएगी। हमारी प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि दो साल में बननी चाहिए। जहां तक इंतजाम का सवाल है कि हरियाणा के हाथ में होना चाहिए इसकै बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि इस बारे में चैंकिंग करें। हमें भारत सरकार पर पूरा भरोसा है कि किसी प्रकार की डिले नहीं होने देगी। डाक्टर मंगल सैन, चौंधरी दवी लाल और बहिन चन्द्रावती जी इस बात को जानती हैं कि हमने डट कर लिखा है कि इस बारे में चैकिंग होनी चाहिए। भारत सरकार की देख रेख में सवा साल के अंदर यह नहर तैयार हो जाएगी।

श्री मंगल सैनः क्या सरकार के नोटिस में ऐसी कोई ि ाकायत आई है कि खुदाई कै लिए जो टैंडर छोडे गए, उसमें पंजाब की किसी फर्म को जो कि महंगा टैंडर था दे दिया गया और हरियाणा की किसी फर्म को जिसका लोअर टैंडर था नहीं दिया गया ? ..... के दबाव के कारण पंजाब की फर्म को यह टैंडर दे दिया गया ?

चौधरी भजन लालः यह नाम कार्यवाही से एक्सपंज होना चाहिए।

श्री अध्यक्षः यह नाम कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया जाए।

श्रीमती चन्द्रावतीः जब उनका हर चीज से संबंध है तो उनका नाम कैसे नहीं आएगा। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः उनका नाम आप यहां हाउस में कैसे ले सकते हैं ? कल को हम आपके भाई का नाम ले सकते हैं (विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावतीः अगर वह एम0पी0 हो और वह एडमिनिस्ट्रे ान में दखलअंदाजी करे तो ले सकते हैं।

चौधरी भजन लालः आप कोई सबूत दें तभी तो कोई बात कह सकते हैं। कोई बात ऐसे ही तो नहीं कहनी चाहिए। जहां तक इस बात का संबंध है कि टैंडर नीचे वाले को नहीं दिया और ऊपर वाले का दे दिया, इसका फैसला तो पंजाब सरकार ही करती है। इस मामले में हमारी भारत सरकार के साथ मीटिंग होती रहती है। जैसा कि चौधरी भाम ोर सिंह जी ने बताया है कि पांच मीटिंग्ज एक दफा हुई और दो एक दफा हुई। हर तीसरे महीने इस बारे में मीटिंग होती रहती है कि नहर की क्या प्रोग्रैस हुई है। अगर किसी मैम्बर के नोटिस में कोई ि ाकायत है तो वह

ध्यान में लायें कि वह किस प्रकार की ि ाकायत है ताकि हरियाणा के पैसा का नुक्सान न हो।

तारांकित प्र न संख्या 123

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्या चौधरी कुंदन लाल सदन में उपस्थित नहीं थे।

Embezzlement of Air Craft Fuel in the Agro Industries Corporation

***215. Sh. Kanwal Singh:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether any case of embezzlement of air craft fuel in the Haryana Agro Industries Corporation during the years 1980-81 and 1981-82 has been detected;

(b) if so, the action taken in the matter;

(c) Whether it is a fact that during the last two spraying seasons the air craft of the Agor Industries Corporation has average3d swventeen thousand acres per season as compared to the earlior average of sixty five thousan areas; and

(d) if reply to part (c) is in the affirmative, the reasons for the decline in its performance ?

Agriculture Minister (Ch. Surender Singh):

a to d : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a)	(i) 1980-81	Yes
	(ii) 1981-82	No.
(b)	After the embezzlement of 3000 literes of aviation fuel came to notice the Store-Keeper was placed under suspenstion by the Corporation on 29.6.81 for making fictitious entries in the stock register. The matter was reported by the Corporation to S.S.P., Ambala who replied that the offence was committed in the jurisdiction of U.T., Chandigarh. The matter was reported to the S.S.P., Chandigarh for investigation and action against all the officials/officers suspected of involvement in the embezzlement of aviation fuel. Chandigarh Police intimated the Corporation that the offence seemed to have been commited at Pinjore and the Chandigarh Police did not come in the picture. The Store-Keeper has been reinstate w.e.f. 11.1.1983 and chargesheeted for departmental action. The State Govt. on a reference from the Corporation is seized of the matter for taking suitable action.	
(c)	No. The details of the acreage per aircraft during the years 1978-79 onwards, is as under :-	
Sr. No.	Year	Annaul Average per air craft

1	1978-79	64849
2	1979-80	16468
3	1980-81	30450
4	1981-82	13553
5	1982-83	37690
(d)	Variation/decline in the averages in the years referred to in reply to part (c) above, are due to various reasons, including -	
(i)	Serious drought conditions during the year 1979-80	
(ii)	Non-availability of adequate aviation fuel during the years 1979-80 and 1980-81	
(iii)	Non- Availability of agricultural air craft for full season due to unfortunate accidents during the years 1980-81 (one) and 1981-82 (two)	
(iv)	Additional spraying acreasge covered for sugarcane crop during the year 1978-79, which was not available in the subsequent years.	

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह बताया है कि पहले ये मामला अम्बाला पुलिस को सौंपा गया, फिर चण्डीगढ पुलिस के पास आया और फाईनली जब उसने यह कह दिया कि यह वारदत तो पिंजौर में हुई है जो कि उसकी जुरिस्डिक ान में नहीं है तो फिर दोबारा अम्बाला पुलिस

को रैफर कर दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह मामला एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरे ान द्वारा 8.12.1982 को सरकार के पास विचारधानी भेजा गया। हमने एल0आरे0 से इस मामले को एग्जामिन करवा कर रिपोर्ट मांगी। हमारे पास अब एल0आर0 की रिपोर्ट आ चुकी हैं हम यह देख रहे हैं कि इस मामले में क्या मुनासिब कार्यवाही की जा सकती है। हम जल्दी ही फैसल के मुताबिक कार्यवाही करेंगे।

प्रो0 सम्पत सिंहः मंत्री महोदय को भाायद इस बात का पता होगा कि यह जो चोरी हुई है यह इसलिए हुई है कि हवाई हजार जो ऐरोड्राम पर रूका था, उसका पंक्चर हो गया था। बाद में उसको बाहर ले जाया गया। पैट्रोल पम्प पर जाकर वहां इस का फ्यूल बेचा गया था, कया यह बात इनके नोटिस में हे ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः इस किस्म की कोई बात सरकार के नोटिस में नहीं है।

डा0 भीम सिंह दहियाः स्पीकर साहब, जिस तरह से यह केस पहले अम्बाला पुलिस ने, फिर चण्डीगढ पुलिस ने और फिर पिंजौर पुलिस ने हैंडल किया क्या यह पुलिस की इनएफी ाीऐंसी है या एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरे ान की है ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, 29.6.1981 को यह बात कारपोरे ान के नोटिस में आई कि एवीए ान फयूल की एम्बैजेलमैंट हुई है। जो फयूल एग्रा इंडस्ट्रीज के रजिस्टर में रिसीट हुआ है और उसके बाद जो फ्यूल सिविल एवीए ान क्लब्ज को अलाट किया गया था, उसके बारे में तत्प चात जनवरी 1982 में कार्पोरे ान के नोटिस में यह आया कि वह फ्यूल वास्तव मे हिसार और करनाल क क्लब्ज में नहीं पहुंचा है। उसके बाद तेजी से कार्पोरे ान द्वारा इस मामले के बारे में चाहे सिविल एवीए ान डिपार्टमैंट की गलती थी या एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरे ान की गलती थी, उसकी तफती ा बराबर लगातार चलती रही है।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, इस बार जो दवाई का फसलों पर छिडकाव किया गया है, उसका असर नहीं हुआ है, क्या उनके पास घटिया दवाई के बारे में कोई ि ाकायत आयी है या नहीं ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस किस्म की कोई ि ाकायत हमारे पास नहीं आयी। अगर इस किस्म की कोई ि ाकायत किसी सम्मानित सदस्य के नोटिस में हो तो वह हमें बतायें, हम जरूरज उस पर तहकीकात करेंगे और उसको इलाज करवायेंगे।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बी भाग के जवाब में यह बताया है कि स्टोरकीपर को 11.1.1983 से बहाल

कर दिया गया है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उसको री इन्स्टेट करने के कारण है ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने पहले सदन को सूचित किया था कि एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरे ान द्वारा इन्क्वायरी करने के बावजूद भी एस0एस0पी0 अम्बाला को लिखा गया। एस0एस0पी0 अम्बाला ने महज इसलिये कि यह मामला चण्डीगढ एयरपोट्र का है, इसलिये चण्डीगढ पुलिस को लिखने के लिये कह दिया। चण्डीगढ पुलिस ने यह कहा कि क्योंकि यह वाक्या पिंजौर का है, इसलिए यह अम्बाला पुलिस डील करेगी। इन सबब बतों को ध्यान में रखते हुए एल0आर0 से रिपोर्ट मांगी गयी। उसकी रिपार्ट आ गयी है। अध्यक्ष महोदय 29. 6.1981 को जल्दी से जल्दी स्टोरकीपर को सस्पैंड कर दिया गया। कुछ बाद सरकार के नोटिस में यह आया कि एक एन्ट्री जिसको सस्पैंस एन्ट्री कहते हैं रिकार्ड में मिली है जो कि 3000 लीटर की थी। जब से यह बात महकमा के नोटिस में आयी है, तब से हम आगे तहकीकात कर रहे हैं। जब तक इस बात के लिये अधिकारियों की जिम्मेवारी तय नहीं हो जाती, तब तक हमने इसको री इन्स्टेट कर दिया है।

चौधरी साहब सिंह सैनीः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह बताया है कि वार्शिक औसत प्रत्येक एयर क्राफअ 1980–81 में 30450 और 1981–82 में 13553 एकड है।

इसमें इतनी ज्यादा कमी होने के कारण मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः सर, उसकी वजह यह है कि उस साल काटन और मस्टर्ड का ज्यादा रकबा का त में आया था। स्पीकर साहब, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 1978–79 में 1979–80 के मुकाबले में ज्यादा रकबा काटन और मस्टर्ड की का त में आया। 1979–80 में सूखे की वजह से कम रकबा का त में आया। 1978–79 में64849 एकड, 1979–80 में 16468 एकड, 1980–81 में 30450 एकड, 1981–82 में 13553 एकड और 1982–83 में 37690 एकड रकबा प्रति एयरक्राफ्ट हमने कवर किया है। इसके अलावा जो एरिया कवर किया गया। वह 1979–80 में 17669 हैक्टेयर्ज रकबा काटन का और 7128 हैक्टेयर मस्टर्ड का था, 1980–81 में यह रकबा इंक्रीज होकर 30747 हैक्टेयर्ज काटन का और 14585 हैक्टेयर्ज मस्टर्ड का हो गया। इसी तरह से 1981–82 में काटन का रकबा बढकर 22940 हैक्टेयर्ज हो गया जबकि मस्टर्ड का 19478 हैक्टेयर्ज हो गया जबकि इसी साल की एवरेज पर एयरक्राफ्ट 13553 एकड थी। उस समय हमारे पास फ्यूल कंडी ांज खराब थी और इसके अलावा हमारे कुछ एयरक्राफ्टस का एक्सीडैंट भी हो चुका था। एक तो एक सीजन में हुआ और उससे अगले सीजन में दो एक्सीडैंट हुए।

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि जो इनकी एवरेज प्रति एयरक्राफ्टस स्प्रे की रही

है। वह 1978–79 मैं 64849 रही है जबकि यह 1981–82 में 13553 रह गयी थी। क्या यह कमी अन क्वालीफाईड पायलट या लैसर क्वालीफाईड पायलट की वजह से से तो नहीं हो गयी ? (व्यवधान व भाोर) स्पीकर साहब, मैं इनसे यही जानना चाहता हूं कि एक साल में ही दो एक्सीडैंट होने का कारण इनके अन क्वालीफाईड या लैसर क्वालीफाईड पायलट तो नहीं थे ?

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, 1978–79 में बम्पर क्राप थी। उस समय एवरेज 64849 एकड की थी। 1978–79 के बाद अध्यक्ष महोदय ड्राउट कंडी ांज की वजह से का म कम हुई। जब का त कही कम होगी तो किसान कम ही स्प्रे करने के लिये कहेगा या डिमान्ड करेगा। जहां तक कंवल सिंह जी के सवाल का सम्बंध है, हमारे सिविल एवीए ान विभाग के या एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरे ान के किसी भी हवाई जहाज को किसी भी अन क्वालीफाईड पायलट ने नहीं चलाया है।

Vacant posts for Engineers and Overseers

***249. Sh. Fateh Chand Vij:** Will the Minister of State for Public Works (B&R) be pleased to state –

(a) the total number of posts of Engineers and Overseers (Civil) lying vacant in P.W.D. (B&R) as on 31-1-1983;

(b) the time by which the said posts are likely to be fiiled up; and

(c) whether the Government proposes to absorb the Overseers (Civil) recently declared surplus ?

Minister of State for Public Works (Ch. Goverdhan Dass Chauhan):

(a)	Gazetted Enginners Junior Engineers (Civil) (Overseers)	15 50
(b)	Except the posts which will have been rendered surplus as a result of recent economy measures, the other posts are likely to be filled in three months.	
(c)	Yes.	

श्री फतेह चन्द विजः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये स्थान कब से खाली पडे हैं।

10.00 बजे।

चौधरी गोवधन दास चौहानः अध्यक्ष महोदय, चार पोस्टस सुररिन्टेंडिग इंजीनियर्ज की खाली थीं। इनमें से एक पोस्ट 2.9.1982 को खाली थी क्योंकि इंकमवैंअ चीफ इंजीनियर

बन गया था। उसके बाद इस पोस्ट को फिल अप नहीं किया गया। एक पोस्ट एस0ई0 की 12.8.1982 को खाली हुई। एक पोस्ट एक्सीयन की 31.7.1982 को खाली हुई और यह अब भी खाली है।

इसी तरह से एस0डी0ओज0 की पोस्टस थी। इनमें से कुछ हैड ओफिस की थी। इनमें से एक पोस्ट 4.11.1982 को खाली हुई और अब यह पोस्ट फिल अप कर ली गई है। कुछ पोस्टस फील्ड की थीं। इनमें से एक 7.9.1982 को खाली हुई दूसरी 15.1.1983 को खाली हुई और तीसरी पोस्ट 31.1.1983 को खाली हुई। ये अब भी खाली हैं

डा0 भीम सिंह दहिया: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने सवाल के पार्ट ए के जवाब में बताया है कि जूनियर इंजीनियर की पचास पोस्टस खाली हैं। और बी के जवाब में लिखा है कि जो सरप्लस डिक्लेयर की गई हैं उनको छोडकर बाकी पोस्टस फिल अप करने की कोि ा ा करेंगे। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये दोनों चीजें साइमलटेनिसयली कैसे करेंगे ?

चौधरी गोवर्धन दास चौहान : अध्यक्ष महोदय ये पोस्टस 31.1.1983 को खाली थीं। इसके बाद माननीय सदस्य ने पूछा था कि जो पास्टैस सरप्लस डिकलेयर हुई हैं उनका क्या बनेगा ? तो मैंने कहा है कि उनको एवजोर्ब करेंगे।

Allotment of land to Harijans in Ram Garh Dhani in Jind District.

***246. Smt. Kartar Devi:** With the Minister for Social Welfare be pleased to state-

(a) whether 5 acreas land was given to each of the 25 Harijan families in Ram Garh Dhani in District Jind by the Harijan welfare Department after purchasing it during the year 1962 and whether the said land has been declared as surplus now; and

(b) the steps being taken by the Government for retaining the possession of that land by those who are cultivating it for twenty years ?

Social Welfare Minister (Smt. Shakuntla Bhagwaria):

(a) 59 Harijan families were given 5 acres of land each in village Ram Garh Dhani. It is a fact that the said land has been declared as surplus on 9-4-1965.

(b) The matter is under consideration of the State Government.

श्री वीरेन्द्र सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगी कि जो लैंड सरप्लस डिक्लेयर कर दी है और वह पहले जिन लोगों के पोजै ान में थी क्या वह अब भी उनके पोजैं ान में है या उनको इजैक्ट कर दिया गया हे ?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: अध्यक्ष महोदय, 9.4.1965 को जो जमीन सरप्लस डिक्लेयर करके हरिजनों को दी गई थी वे आज भी वहीं पर बसे हुए हैं।

श्री भले राम: अध्यक्ष महोदय, जब यह जमीन हरिजनों को दी गई थी तो उस वक्त हरिजनों को कुछ रूपया सरकार ने दिया था और कुछ रूपया बैंकों से दिलवाया था और इस तरह से उस जमीन की कि त हरिजनों ने पूरी की थी। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि आज तक उस जमीन का उस जमीन का इंतकाल क्यों नहीं हुआ और उस जमीन को सरप्लस डिक्लेयर क्यों किया गया है ?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि जब ये जमीन दी गई थी उस समय दो हजार रूपया अनुदान के रूप में और पच्चीस सौ रूपया लैंड मौरगेज बैंक से दिलाया गया था और इस जमीन की रजिस्ट्री भी करवा दी गई थी और अब उस जमीन को सरप्लस डिक्लेयर नहीं करवाया गया है।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि हरिजनों के ऊपर काफी सालों से जो तलवार लटकी हुई है उनके कश्टों को कब तक दूर कर दिया जाएगा ?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: अध्यक्ष महोदय, यदि हम हरिजनों के हितैशी न होते तो जितने काम उनके हित में हमने

किए हैं वे कभी नहीं होते। हरिजनों को कोई दिक्कत नहीं है और न कोई तलवार उनके सिर पर लटकने वाली बात है।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, सिरसा जिले में एक गींदडा गांव हैं वहां पर पांच छः हरिजन पिछले बहुत सालों से का त करते आ रहे हैं। उनको जमीन भी अलाट कर दी गई थी और अब एक भाक्ति ाली आदमी से दबाव डलवाकर उनको उस जमीन से उखाडा जा रहा है क्या यह बात मंत्री महोदया के नोटिस में है और अगर है तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़ियाः अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बिल्कुल अलग है अगर माननीय सदस्य अलग से नोटिस देंगे तो जवाब दे दिया जाएगा।

श्री मनफूल सिंहः क्या मंत्री महोदया, बताने की कृपा करेंगी कि हरियाणा में कितनी सरप्लस जमीन हैं ? (ाोर एवं व्यवधान) अगर हरियाणा की नहीं बता सकती तो जिला करनाल की ही बता दें कि कितनी जमीन वहां पर सरप्लस है ?

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री भले रामः अध्यक्ष महोदय, पंजाब सिक्योरिटी आफ लैंड टैन्यार एक्ट, 1953 के अधीन पंजाब में जोतदारों को जमीन का मालिक बना दिया लेकिन जींद डिस्ट्रिक्ट पैप्सू लैंड टैनन्सी एक्ट में आता था इसलिए उनको मालिक नहीं बनाया गया। क्या

मंत्री महोदया, वहां पर भी जोतदारों को जमीन का मालिक बनाएंगी।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: यह सत्य है कि इस किस्म की जमीन पहले दी गई थी। अध्यक्ष महोदय, रामगढ धानी जिला जींद में है और जिला जींद संगरूर में आता था इसलिए वहां पर पैप्सू लैंड टैंन्नसी एक्ट, 1955 लागू होता था। पंजाब सिक्योरिटी आफ लैंड टैन्योर एक्ट में तो समय समय पर अमैंडमैंट होती रही लेकिन पैप्सू लैंड टैन्नैसी एक्ट में अमैंडमैंट नहीं हुई। अब राजस्व विभाग और समाज कल्याण विभाग इस काम में लगे हुए हैं और यह मामला सरकार के विचारधीन हैं।

Loss of Crops is Kiloi Constituency due to Hailstorms

***268. Sh. Hari Chand Hooda:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether it is a fact that Makrauli Khurd and Kalan Titoli, Sundarpur, Khadwali, Jasi Chamarian, Kiloi and Azad Garh Rohtak Pada Sramad Sisoli Villages of Kiloi constituency of district Rohtak suffered huge loss of crops due to hailstorm in 1982. and

(b) if so, wherher compensation to all the affected villages has been paid and if not, the time be which it is likely to be paid ?

Revenue Minister (Ch. Phool Chand):

(a) The 12 villages mentioned in the question suffered loss of crops due to hailstorms during Rabi 1981-82 in varying degrees.

(b) Out of these 12 villages compensations has been disbursed in 7 of them, namely Makroli Khurd, Sunder Pur, Chamarian, Kiloi, Sarai Ahmed, Sasroli and Khaidwali. In villages Jasi compensation has been partially disbursed. In the remaining 4 villages, namely, Makroli Kalan, Titoli, Azad Garh –Rohtak and Para, it is yet to be paid and the same will be done very shortly.

श्री हरिचन्द हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि बहुत जल्दी कम्पैनसे ान पे कर दिया जाएगा। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कब तक दे दिया जाएगा और इसके लिए क्या कोई टाईम फिक्स करने की कृपा करेंगे।

चौधरी फूल चन्दः अध्यक्ष महोदय 38 लाख रूपया अभी डी0सी0 रोहतक के पास बांटने के लिए बाकी है। वह करीब इस महीने में बंट जाएगा और बाकी पैसा अपने फाइनैंि ारूल ईयर में बांटा जाएगा।

डा0 भीम सिंह दहियाः अध्यक्ष महोदय यह जो 12 गांव बताये गये हैं, उन में ओला वृश्टि एक ही दिन में हुई है लेकिन उनमें से सात गांवों में सरकार की तरफ से मुआवजा दे दिया गया है और एक में आधा और बाकी चार गांवों में अभी मुआवजा

देना बाकी है। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि सरकार के मुआवजा देने के नार्मज क्या क्या हैं ?

चौधरी फूल चन्दः अध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम यह काम एक एस0डी0एम0 के जिम्मे लगाते हैं कि उसकी सुपरवीजन में यह पैसा बांटा जाए। 3 करोड 68 लाख के करीब रूपया किसानों में बांटा गया और फिर इस काम में कुछ समय तो लगता ही है। जो गांव रह गये हैं उनमें भी मुआवजे की रकत जल्दी से जल्दी बांटने की सरकार कोि ा ा कर रही है।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः स्पीकर साहब अब तक जो मुआवजे की रकम बांटी गयी है उसमें 64 लाख के करीब रकम आज भी बकाया है। क्या सरकार ने फण्डज की कमी की वजह से तो ऐसा नहीं किया है ?

चौधरी फूल चन्दः जो बकाया बांटने वाली रकम है, उसको रोकने का कोई ऐसा कारण नीं है नैक्सट फाइनेनि ायल ईयर में फण्डज एलोकेट होते ही बकाया रा ि ा किसानों में बांट दी जाएगी।

चौधरी साहब सिंह सैनीः स्पीकर साहब, 64 लाख रूपये की रकम किसानों में बांटनी बकाया है। अभी तक वह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। डिस्ट्रिक्ट अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास अभी पैसा ही नहीं आया और जब यहां सरकार से पूछते हैं तो सरकार कह देती है कि हमने पैसा जिला अधिकारियों को भेज दिया है।

क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि यह पैसा जिला अधिकारियों के पास कब तक चला जाएगा और कब तक यह बकाया रा ि ा किसानों में बांट दी जाएगी ?

चौधरी फूल चन्दः 64 लाख रूपया आपसी डिसप्यूट के कारण बकाया है। कलेम वगैरह के झगड़े हैं। अगले माली साल में पैसा एलोकेट होते ही किसानों में बांट दिया जाएगा लेकिन बांटने में समय तो लगना स्वाभाविक ही है।

श्री किताब सिंहः स्पीकर साहब, हरियाणा में ओला वृश्टि के कारण लगभग 70 करोड रूपये की फसलों का नुकसान हुआ है लेकिन मुआवजा केवल दिया गया है लगभग 14 करोड। क्या मंत्री महोदया बताएंगे कि पर एकड किस हिसाब से किसान को मुआवजा दिया गया है ?

चौधरी फूल चन्दः अध्यक्ष महोदय, जितना नुकसान इन्होंने बताया है, उतना हुआ नहीं है। पिछले साल 14 करोड रूपये की रा ि ा मुआवजे के तौर पर बांटी गई और मुआवजे की रकम देने के नार्मज वगैरह के बारे मैं मैं पहले भी बता चुका हूं कि जहां पर 75 प्रति ात से अधिक नुकसान हुआ है, वहां पर हमने 400 रूपये प्रति एकड जहां पर 50 से 75 के बीच में नुकसान हुआ है, वहां पर 300 रूपये प्रति एकड और जहां पर 25 से 50 प्रति ात तक नुकसान हुआ है, वहां पर 200 रूपये प्रति एकड के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया है।

चौधरी हुकम सिंहः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में कितने ही ऐसे गांव हैं जहां पर ओला वृश्टि के कारण किसानों की फसलों का काफी नुक्सान हुआ है और वहां के जिला अधिकारियों ने सरकार से पैसे की डिमांड भी नहीं की है जिसके कारण से वहां के किसानों में बडा भारी रोश है, और वे परे ाान भी हैं। दादरी के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर मुआवजा नहीं दिया गया है। क्या सरकार दादरी के उन बरबाद गांवों में जल्दी ही मुआवजा देने का विचार रखती है ?

चौधरी फूल चन्दः स्पीकर साहब, ऐसा कोई मामला सरकार के नोटिस में नहीं आया है। अगर कोई ऐसी रिपोर्ट सरकार के पास आयेगी तो उसका समाधान जल्दी ही किया जायेगां

डा0 भीम सिंह दहियाः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि इनका मुआवजा बांटने का नार्मज आफ प्रोसीजर क्या है ? यह तो कह दिया कि एस0डी0एम0 की सुपरविजन में हम पैसा बांटते हैं ?

चौधरी फूल चन्दः एस0डी0एम0 की सुपरविजन में पैसा बांटा जाता है। इसका दूसराच नार्मज यह है कि जिन इलाकों में 75 प्रति ात से ज्यादा नुकसान हुआ हो उन इलाकों में हम पहले मुआवजा बांटते हैं और जहां थोडा नुक्सान हुआ हो, वहां पर बाद में मुआवजे की रकम दी जाती है। एक में ओला वृश्टि से ज्यादा

नुकसान हुआ है। और एक में कम नुकसान हुआ है। अगर हम बार बार बांटने के लिए जाएंगे तो सरकार का खर्चा भी बढेंगा और सरकारी अधिकारियों को भी परे ाानी होगी। इसलिए बार बार हर गांव में नहीं जाते। एक गांव में पहले और दूसरे गांव में बाद में जाते हैं।

श्री हरी चन्द हुड्डाः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि हमारे वक्त में ऐसी ओला वृश्टि की हालत में पैसा तीन महीने के अंदर अंदर दे दिया जाता था। हमने टाईम लिमिट रखी हुई थी लेकिन इन्होंने कोई समय निर्धारित नहीं किया हुआ है। क्या सरकार कोई टाईम की फिक्से ान करेगी कि इतने समय के अंदर अंदर मुआवजे की रकम बांट दी जाएगी ताकि किसानों में किसी प्रकार की परे ाानी न हो और उन्हें भी यह पता हो कि हमें पैसा इस दिन तक मिलता है।

चौधरी फुल चन्दः स्पीकर साहब, यह टाईम लिमिट की बात करते हैं। इन्होंनें अपने समय में केवल 2 करोड रूपया बांटा और हमने 14 करोड रूपया बांटा आखिर इतनी बडी रकम बांटने में समय तो लगेगा ही।

चौधरी नर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जिन किसानों की फसलौं का ओलावृश्टि के कारण नुकसान हुआ है, उनको सरकार और अधिकारियों की गलती की वजह से आज तक मुआवजे की रा ि ा नहीं दी गई है जबकि गिरदावरी का काम भी तीन चार

महीने में पूरा हो गया था। सरकार ऐसे किसानों को कब तक मुआवजे की रा ि ा देने का प्रबंध करेगी ?

चौधरी फूल चन्दः मेरे भाई ने कहा कि सरकार की और अधिकारियेां की गलती की वजह से किसानों का मुआवजा नहीं दिया गया है, यह बात नहीं है। अगर ये कोई जानकारी हमारे नोटिस में लाएंगे तो हम अव य ही जल्दी कार्यवाही करेंगे और जिनका अभी तक फसलों के नुकसान का मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें जल्दी ही मुआवजा देंगे।

श्री फतेह चन्द विजः स्पीकर साहब, कई गांवों में अभी तक लोगों को मुआवजे की रकम नहीं दी गई है और इसके लिये किसान लोग काफी परे ाान हैं, दुःखी हैं। क्या सरकार इस काम के लिए कोई नि ि चत डेट फिक्स करने का विचार रखती है और साथ में यह करने का भी विचार रखती है कि हर जिला अधिकारियों को यह हिदायतें जारी कर दी जाएं कि जब भी किसानों को मुआवजा दिया जाना हो तो उससे पहले बाकायदा इस बात के लिए मुनादी वगैरह भी करवा दी जाए कि सरकार इस पर तारीख को मुआवजा की रकम तकसीम करने जा रही है ताकि गरीब किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पडें।

चौधरी फूल चन्दः अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी यह बताया कि पैसा बांटने में कुछ समय तो लगता ही है। कई बार

लोग नहीं मिलते फिर भी हम इनकी बात को मद्देनजर रखते हुए पहले मुनादी करवाने का हुक्म दे देंगे और नैक्सट फाईनैनि ायल ईयर में बजट की एलोके ान होतते ही मुआवजे की रकम किसानों में बांट दी जाएगी।

चौधरी धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, जिन चार गावों को सरकार ने छोड रखा है वहां पर 100 परसैंट फसल बरबाद हो गई हे लेकिन वहां पर आज तक किसानों को मुआवजे की रकम नहीं मिली है। क्या सरकार ऐसे लोगो ंको मुआवजे के साथ ब्याज भी देने का विचार रखती है ?

चौधरी फूल चन्दः ऐसा कोई सरकार का विचार नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जिल लोगां का हेल स्टार्म के कारण नुकसान हुआ है और उनके लिये सरकार ने जिला अधिकारियों को पैसा भी दिया है लेकिन उन अधिकारियों ने मुआवजे की रकम देते समय खालों का और कुछ कर्जे की रकम जो कि किसानों के जिम्मे थी, मुआवजे की रकम मैं से काटने की कोि ा ा की जिसके नतीजे के तौर पर यह हुआ कि किसानों ने वे पैसे लेने से इंकार कर दिया और फिर जिला अधिकारियेां ने वह किसानों का पैसा सरकार को वापिस कर दिया है। क्या सरकार उस पैसे को दोबारा किसानों में बांटने का विचार रखती है ?

चौधरी फूल चन्दः ऐसी बात स्पीकर साहब, सरकार के नोटिस में नहीं है। अगर मैम्बर सहब कोई ऐसी बात सरकार के नोटिस में लाएंगे तो हम अव य कार्यवाही करेंगे और किसानों को मुआवजे की रकम देंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, अगर मैं स्पेसीफिक मामला इनके नोटिस में ला दूं तो क्या किसानों को मुआवजे का पैसा देंगे ?

चौधरी फूल चन्दः स्पीकर साहब, जब ये इस बारे में लिखकर हमारे नोटिस में लाएंगे तो हम पहले उस मामले की जांच करवा लैंगे।

Land under Crops afftected by accumulated Rainy water

in district Kurukshetra

***243. Master Ram Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the Government is aware of the fact that about 21000 acres of agricultural land under crops in district Kurukshetra has been affected because of the lack of drainage of the accumulated rain water, during the month of January 1983; is so, the steps so far taken to drain out the said accumulated water ?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Due to unprecedented and heavy rain fall of five inches, accompanied by hailstroms, during last week of

January 1983, the crops in about 3200 acres were affected in low lying pockets in about 61 villages of the district and extent of damage was from 25% to 50% in about 2800 acres and more than 50% in 400 acres. The drains constructed over last few years worked quite efficiently. The Darinage Department with the help of District Administration got the obstructions across the natural drainage lines removed and the water was drained out from most of the area into the existing drains. Further improvement of the drainage system in these areas is being studied/planned.

चौधरी साहब सिंह सैनीः अध्यक्ष्य महोदय, मंत्री महोदन ने अपने उत्तर में यह कहा है कि असाधारण वर्शा व भारी वर्शा और ओला वृश्टि के कारण 61 गांवों के नीचान वाले लगभग 3200 एकड क्षेत्र की फसल खराब हो गई हैं वास्तव में ड्रेनेज का प्रोपर प्रबंध नहीं है। कहीं से सडकों ने रास्ता रोक रखा है, कहीं से सरकार ने बंद कर दिया है। राक्षी, सरस्वती और लिन्डा नदियों का पानी, मथाना, गोबिन्दगढ और सिरसिला गांवों से होता हुआ सनहेत तालाब कुरूक्षेत्र में डलता है। सनहेत के इन लैट को बंद कर दिया है और पानी का निकास बंद हो गया है इसलिये इन गांवों की फसलों को इस पानी के खडा हो जाने से काफी भारी नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जिन गांवों में लोगों की फसलें इस कारण से बरबाद हो गई हैं क्या सरकार इन इफैकटिड लोगों को मुआवजा देने की कोि ा ा करेगी या यह मामला सरकार के विचाराधीन हैं ताकि लोग कुछ राहत महसूस कर सकें ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, जो फसलें ओला वृश्टि की वजह से खराब होती हैं, मुआवजा तो सिर्फ उसके लिये ही मिलता है। फ्लड की वजह से जो नुकसान होता है, उसके लिये और राहत मिलती है जैसे तकावी पोस्टपोन कर दी जाती है और मालिया तथा आबियाना माफ कर दिया जाता है। जहां तक इस बात का सवाल है कि सरकार ने कई चीजें रोक दी उस वजह से नुकसान हो गया। मैं हाउस की जानकारी के लिये बताता हूं कि जनवरी के पहले हफ्ते में तीन दिन के अंदर कुरूक्षेत्र जिले में बहुत हैवी रेन हुई। उरलाना, पेहोवा, ज्यातिसर और रदौर में 131, 120, 70, 111 मिलीमीटर बरसात हुई। एक तो यह कारण था। दूसरा कारण यह था कि कुरूक्षेत्र जिले में जो छोटे छोटे नदी नाले हैं, उनके बैड की जमीन है। वह सरकार की मलकीयत नहीं बल्कि प्राइवेट आदमियों की है। ज्यों ज्यों जमीनों की कीमतें बढने लगी, लोगों ने जमीन को लैवल करके उस पर खेती करनी भाुरू कर दी। उन लोगों ने यह औबस्ट्रक ान खुद क्रीएट कर ली। फिर भी सरकार इस बारे में पूरी कोि ा ा कर रही है। जैसे राक्षी, लीगा और जोघा नाले हैं इनको कैनेलाइज करने के लिये स्कीमें बनाई हैं जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड के सामने लाई जा रही हैं।

मास्टर राम सिंहः स्पीकर साहब मेरे हलके में चार पांच गांव ऐसे हैं जहां अब भी पानी खडा है। क्या मंत्री जी उस पानी को निकलवाने का कोई इंतजाम करवाएंगे।

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, जहां कहीं भी फ्लड का पानी खडा है उसको निकालने के लिये ड्रेनेज डिपार्टमैंट तथा रैवेन्यू अथोरिटीज पूरा पूरा प्रयत्न करते हैं। मेरे दोस्त ने इस बारे में मेरे को पहले नहीं बताया। अगर अब वे स्पैसिफिकली वहां के बारे में लिख कर देंगे तो मैं अफसरों को डिप्यूट कर दूंगा और वहां से पानी निकालने का प्रबंध किया जाएगां

श्री अध्यक्षः इसमें प्रोब्लम यह है कि जो नैचुरल फलो की जगह है वह कंसोलिडे ान वालों ने जमीदारों को अलाट कर दी। अब वह उनकी मलकियत बन गई। इसकी वजह से सारे कुरूक्षेत्र जिले में बडी भारी प्रोब्लम आई हुई है। उसको चाहे तो आप एक्वायर करो या उनको आल्टरनेटिव जगह दो। इसको कोई न कोई हल जरूर निकालो।

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो नदी नालों के बैंड हैं, वह प्राइवेट आदमियों की मलकियत थी। उन्होंने उनको लैवल कर लिया। यह पानी पिछले 15–20 साल से चलता है। ला के मुताबिक हम बंद नहीं कर सकते थे लेकिन फिर भी हमने बंद कर दिया था। एक दो केसिज में लोगों ने कोर्ट से स्टे ले ली और बाद में वह स्टे वैकेट हो गई। जो प्राइवेट जमीन वाले लोग औबस्ट्रक ान क्रिएट कर रहे हैं इस आसपैक्ट पर भी डिपार्टमैंट विचार कर रहा है।

श्री अध्यक्षः इसके लिए आप ड्रेनेज एक्ट में अमैंडमैंट करें।

चौधरी सागर राम गुप्ताः स्पीकर साहब, हमारी स्टेट में कई जिले तो ऐसे हैं जहां हर साल फ्लड आता है और कई इलाके ऐसे हैं जैसे भिवानी और महेन्द्रगढ के जिले हैं, वहां हमे ाा सूखा रहता है। क्या मंत्री जी कोई ऐसी स्कीम बनाने का विचार रखते हैं कि फ्लड वाटर को जमा करके सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नहर के जरिये भेजा जाए।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः ऐसी स्कीमें इरीगे ान डिपार्टमैंट के पास हैं लेकिन इनकी एग्जीक्यूं ान की जो कास्ट है वह बहुत ज्यादा है। मु कल यह है कि वैनिफि ारीज वालांटरी तौर पर मदद नहीं करते। इनती बडी स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए लोगों को कोआप्रे ान की बहुत जरूरत हैं। स्कीमें हमारे पास हैं, जयों ज्यों फंडज अवेलेबल होंगे, इन पर काम चालू करवाने पर विचार किया जाएगा।

श्रीमती चन्द्रावतीः क्या मंत्री जी बताएंगे कि जब एसकोर्ट फैक्टरी के लिए दो सौ एकड जमीन एक्वायर हो सकती है तो लोगों को पानी देने के लिए बांध बनाने के लिए और रैजरवायर बनाने के लिए जमीन एक्वायर नहीं हो सकती ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः एसकोर्ट फैक्टरी हो या कोई और हो जो जमीन उन्होंने ली है उसका मुआवजा वहीं देंगे न कि सरकार देगी।

श्री हरि चन्द हुड्डाः स्पीकर साहब मेरे तथा चौधरी औम प्रका ा के हल्कों में जे0एल0एन0 कैनाल की सीपेज की वजह से 15 हजार एकड जमीन खराब हो गई है, उसके लिए सरकार क्या सोच रही है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, चौधरी औम प्रका ा के सवाल के जवाब में मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि हम अफसरों की मीटिंग कर रहे हैं। सीपेज के कारणों के लिये आलरेडी दो रिपोर्टस हमारे पास हैं, उस पर हमारे अफसरों ने कमैंटस दिए हैं। हमने चार अफसरों की डियूटी लगाई है कि 15 दिन के अंदर अंदर कोई ऐसी रिपोर्ट दी, जो कार्यान्वित हो सके और सीपेज को रोकरने का पूरा इलाज हो सके।

चौधरी कुन्दन लालः स्पीकर साहब, मेरे हल्के सफीदों में भंबेवा गांव के पास बहुत सारे एरिया में अब भी पानी खडा है, क्या उसको निकालने का कोई प्रबंध किया जाएगा ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, वहां आलरेडी भंबेवा ड्रेन है। फिर भी मैम्बर साहब कोई वि ोश बात

मेरे नोटिस में अलग से लाएंगे तो उस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि वर्शा और ओला वृश्टि की वजह से 3200 एकड जमीन को नुकसान हुआ हैं क्या यह सारा मुआवजा ओला वृश्टि के तहत नहीं दिया जा सकता ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः जो नुकसान ओला वृश्टि की वजह से हुआ है, मुआवजा तो उसी को मिलेगा।

श्री सागर राम गुप्ताः स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया कि कुछ स्कीमें उनके अंडर कंसिड्रे ान हैं लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने के लिये कास्ट बहुत आएगी। मैं कहना चाहता हूं कि लाखों एकड जमीन फलड की जवह से और सूखे की वजह से खराब होती है। अगर इन सारी बातों को ध्यान में रख कर सरकार स्कीम चालू करे तो मैं नहीं समझता कि कास्ट फैक्टर हैवी होंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन सी स्कीम है और उस पर कास्ट फैक्टर की डिटेल क्या है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, क्योंकि मेन सवाल में यह बात नहीं पूछी गई थी इसलिये मैं इसकी डिटेल तो इस वक्त नहीं बता सकता। जहां तक इस बात का सवाल है कि सरकार यह काम क्यों नहीं कर सकती, उसके लिये लैंड एक्वीजी ान की प्रोबलम है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, सरकार की तरफ से ओला वृश्टि से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को दिया जाता है। मैं मंत्री जी से यह जानता चाहता हूं कि क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि बाढ और सूखे से पीडित किसानों को भी मुआवजा दिया जाये ताकि उनको राहत मिल सके ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ सरकार की हमदर्दी बहुत ज्यादा है और उनको राहत देने के लिए भरसक प्रयत्न करती है लेकिन बाढ से और सूखे के कारण पीडित किसानों को मुआवजा दिया जाना मुमकिन नहीं है।

Amount obtained from the Marketings Committees for the Construction of Roads

***277. Ch. Nar Singh:** Will the Minister of State for Public Works (B&R) be pleased to state-

(a) whether any of the Market Committees in the State has paid any amount to the Government for the construction of roads, during the period from 1978 to date; if so, details thereof; and

(b) whether any of the roads for which the amount, as referred to in a part(a) above, if any paid, have been completed; if so, the detials of such roads ?

Minister of State for Public Works. (Ch. Goverdhan Dass Chauhan):

(a) Yes. The details are given in Annexure 'A' which is laid on the Table of the House.

(b) Yes. 16 roads have been completed. The details are given in Annexure 'B' which is laid on the Table of the House.

ANNEXURE 'A'

Sr. No.	Name of Market Committee	Amount Deposited
1	Assnnadh	597000
2	Taraori	80500
3	Indri	100000
4	Nissing	555097
5	Karnal	1426800
6	Gharaunda	1051000
7	Panipat	829000
8	Samalkha	6640000
9	Madlauda	514000
10	Kaithal	725392

11	Pundri	887800
12	Mullana	300000
13	Barara	433700
14	Pehowa	1954500
15	Ladwa	1593296
16	Shahbad	1693740
17	Gurgaon	419967
18	Taoru	250000
19	Palwal	722400
20	Hodel	923250
21	Safidon	1949000
22	Jind	595000
23	Sonepat	180000
24	Ganaur	277000
25	Hissar	1313400
26	Adampur	92700
27	Barwala	184000
28	Uklana	423000
29	Tohana	800000

30	Fatehabad	1763000
31	Bhuna	287000
32	Ratia	200000
33	Bhattu	300000
34	Kalanwali	1083900
35	Dabwali	150000
36	Sirsa	282800
	Total	25597242

ANNEXURE 'B'

List of Roads Complted

1	Barsat to Dera Sikligarh
2	Panipat Palheri road
3	Babail Kutani road
4	Ahar to atuoula
5	Dachara to Chor Karsa
6	Nankapur to Urnecha
7	Lakhmari to Bhowai
8	Lalheri to Larsoli
9	Balsamand to Sundawas

10	Dobhi to Bandhari
11	Balsamand to Bandahari
12	Ghursal to Telanwali Kutian Kheri road (Western side)
13	Barwala to Kharkare
14	Damkora to Jamalpur Sheikhan Railway Station
15	Dharsul Kalan to Salimpuri
16	Phoolu to Chitha

चौधरी धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने इस सवाल का जो जवाब दिया है वह मैंने सारा पढा हे। इस जवाब में रोहतक जिले में सडक बनाने के लिए कोई पैसा नहीं दिखाया गया है। यह सरकार रोहतक जिले के साथ राजनैतिक भावना से सौतेला व्यवहार कर रही है। सारे प्रांत में मार्किट कमेटियों का सारा पैसा पी0डब्ल्यू0डी0 को डाईवर्ट हो चुका है। उस पैसे में से इस सरकार ने रोहतक जिले में सडक बनाने के लिए एक भी पैसा नहीं दिया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वहां पर सडकें बनाने के पैसा क्यों नहीं दिया गया ?

चौधरी गोवर्धन दास चौहानः स्पीकर साहब, जिन जिन मार्किट कमेटियों ने पी0डब्ल्यू0डी0 के पास पैसाव जमा करवा दिया है, वहां वहां सडकें बनाई गई हैं।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब क्वै चन आवर समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के

लिखित उत्तर

Group A and B post of Doctors in the State

***280. Sh. Man Phool Singh:**Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) A and B goupwise total number of sanctioned permanent posts of doctors at presnet in the State; and

(b) whether any of the posts, referred to in part (a) above are lying vacant for purpose of confirmation; if so, groupwise number thereof togetherwith the reasons, if any, for not making confirmation against such posts of doctors ?

Health Minister (Smt. Parsanni Devi):

(a) Group 'A' 38

Group 'B' 215

(b) Pernamanent posts lying vacant :-

Group 'A' 30

Group 'B' 17

The reasons for not making confirmation against such vacant permanent posts so far are explained as under :-

Group 'A'

(1) Suitability of some officers promoted from Group B to this Group of Service has not been approved so far by Haryana Public Service Commission. In their cases confirmation can be made only after their suitability is approved.

(2) Certain members of this Group of Service had made representations against their seniority and their reprsentations were under consideration of the Government. Some representations have been decided and the remaining will be decided shortly.

Group 'B'

Confirmation 17 doctors in Group B could not be made so far because disciplinary proceedings etc. against these doctors are pending finalisation.

Subsidy to T.I.T. Mills Bhiwani

***143. Sh. Hira Nand Arya:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) whether any subsidy has been given to the T.I.T. Mills, Bhiwani during the last four years; if so, whether the same has been utilised properly;

(b) whether any looms were closed by the management during the last four years; and

(c) the names of Industries in the State to whom the subsidy of more than Rs. One Lakh has been given by the Haryana Governmnet as well as the Central Government during the period as referred to in part (a) above ?

Industries Minister (Sh. Lachhman Singh):

(a) Yes.

(b) Yes.

(c) The statement is laid on the Table of the House.

Statement

The names of Industries located in the Centrally notified backward areas of the State to whom Central Investment Subsidy of more than Rs. One Lakh has been distursed during the years 1979-80, 1980-81, 1981-82 & 1982-83.

Sr. No.	Name of the Unit	Amount (in Rs.)
1	M/s. Kumar Metal Rolling, Delhi Road, Rewari	120597

	(M.Garh)	
2	M/s. Ajay Metal, Delhi Road, Rewari (M.Garh)	104941
3	M/s. Bharat Rice Mills, Tohana (Hissar)	206760
4	M/s. Guar Gum India P.Ltd. Narnaul (M. Garh)	181797
5	M/s. Mohindra Metal Industries, Rewari (M.Garh)	110377
6	M/s. Rawalsia Oil & General Mills, Hissar	262914
7	M/s. ;Nav Bharat Steels (P) Ltd. Hissar	208615
8	M/s. Rajindera Oil Mills, Hissar	274342
9	M/s. Surei Papers & Chemicals Ltd. Dharuhera (M.Garh)	435213
10	M/s. Sehgal Papers Ltd. Dharuhera (M.Garh)	1500000
11	M/s. Vinex Inds. Estate, Dharuhera (M.Garh)	218100
12	M/s. Bansal Rice Mills, Toahan (Hissar)	174261
13	M/s. Kejriwal Industrial Corporation, Bhiwani	102441
14	M/s. Laxmi Ice and Cold Storgae, Jind	135575
15	M/s. Sunrays Rolling Mills, Rewari (M.Garh)	122760
16	M/s. Rwwari Textiles P. Ltd. Rewari (M.Garh)	116990
17	M/s. Sainik Tyres Ltd. Vill. Pandu Pindara, Jind	116278
18	M/s. Hissar Steel Fabricators, P. Ltd, Hissar	126750

19	M/s. East India Syntex Ltd. Dharuhera (M.Garh)	1500000
20	M/s. Orbit Steel & Argicultural Industries, Hissar	116422
21	M/s. Rajmoti Industries, Hissar	117866
22	M/s. Hindustan Gum & Chemicals, Bhiwani	455245
23	M/s. Nalwa Steel Ltd., Hissar	127909
24	M/s. Indian Guar Gum P.Ltd. Hissar	254496
25	M/s. Haryana Agro Cattle Feed Plant, Jind	566196
26	M/s. Century Tubes Ltd. Bhiwani	399877
27	M/s. Rawalwasia Oil Industries, Hissar	226400
28	M/s. National Co-opertaive Consumers Federation Ltd. Bhiwani	222540
29	M/s. Rawalwasia Oil & General Industries, Hissar	104330
30	M/s. Ram Partap Bansal & Sons Tohana (Hissar)	286693
31	M/s. Swastik Udyog, Hissar	237801
32	M/s. Minaxi Industries, Hissar	103051
33	M/s. Technological Institute of Textiles, Bhiwani	283809
34	M/s. Rajindera Oil Mills, Hissar	137181

35	M/s. Keeran Vegetable Products Ltd. Bhiwani	306866
36	M/s. Dharuhera Chemicals Ltd. Dharuhera (M.Garh)	1451245
37	M/s. Rama Fibres Ltd. Vill. Bhamra (Bhiwani)	1500000
38	M/s. United Chemicals Industries, Dharuhera (M.Garh)	131388
39	M/s. Mu9ltitech International Ltd. Dharuhera (M.Garh)	1500000
40	M/s. J.B. Papers Mills P. Ltd. Dharuhera (M.Garh)	936585
41	M/s. Janak Steel Tubes P. Ltd. Hissar	189908
42	M/s. G.R. Paper & Board Mills, M. Garh	161139
43	M/s. Pasupati Spinning & Weaving Mills Ltd. Dharuhera (M.Garh)	1500000
44	M/s. Mahabali Straw Board Udyog, Vill. Moth (Hissar)	161355
45	M/s. Parkash Piper & Industries Ltd. Vill Mayor (Hissar)	900000
46	M/s. Sidharath Papers Ltd. Dharuhera (M.Garh)	317175
47	M/s. Anjana Tiles, Vill. Kund, Tehsil Rewari (M.Garh)	118032
48	M/s. K.C. Textiles Ltd. Vill. Pandu Pindara, Jind	1500000

49	M/s. Bhanu Industries, Hissar	473944
50	M/s. Om Steel Tubes Ltd. Dharuhera (M.Garh)	981425
51	M/s. Jai Bharat Gum & Chemicals Siwani (Bhiwani)	174600
52	M/s. Vinex Industrial Estate, Dharuhera (M.Garh)	125800
53	M/s. Ajay Metals, Delhi Road, Rewari	199934
54	M/s. Rajindera Oil Mills, Hissar	118900
55	M/s. S.B. Oil Industries P. Ltd. Hissar	446000
56	M/s. Ram Partap Bansal & Sons P. Ltd., Tohana (Hissar)	288000
57	M/s. Minaxi Industries, Hissar	148000
58	M/s. Amar Industries, Hisar	211000
59	M/s. Bharat Metals, Hissar	132000
60	M/s. Aggarwal Paper Board Mills, Vill. Bishanpura, Jind	188186
61	M/s. Kamal Paper Board Mills, Jind	141082
62	M/s. Swadeshi Tubes P. Ltd., Hissar	290599
63	M/s. Franklin Ceramics P. Ltd. Hissar	214677

Subsidy given by Haryana State Govt.

Nil.

Discretionary Funds granted to the institutions in Ambala City by Ministers

***323. Master Shiv Parsad:** Will the Minister of State for Education be pleased to state –

(a) the number of the Ministers who attended the functions arranged by different Schools and Colleges at Ambala City from 1.1.80 to 28.2.83; and

(b) the institution wise amount of discretionary funds granted by the Ministers as referred to in part (a) above during the same period ?

Minister of State for Education (Sh. Jagdish Nehra):

(a) Nine

(b) The requisite information has been placed on the Table of the House as per Annexure 'A'

ANNEXURE 'A'

Sr. No.	Name of School/College	Amount	Name and Designation of the Minister
1	Sohan Lal Girls High School Ambala City	4000	Sh. Des Raj, the then E.M.

2	G.R.S.D. High School, Ambala City	5100	Sh. Phool Chand, R.M.
3	M.D.S.D. Girls College, Ambala City	i) 5000 ii) 5000	Sh. Sher Singh, the then RM. Sh. Goverdhan Dass PWM
4	Dev Samaj College, Ambala City	i) 5000 ii) 11000 iii) 1500	Sh. Phool Chand, RM Sh. Goverdhan Dass PWM Sh. Lal Singh, Dy. Min.
5	S.A. Jain College, Ambala City	5000	Sh. Sher Singh, the then RM
6	S.L. College of Education, Ambala City	11000	Sh. Goverdhan Dass PWM
7	DAV College, Ambala City	5100	Sh. Khurshid Ahmed the then FM

विभिन्न विशयों को उठाया जाना –

(1) सै ान को बढाने सम्बंधी

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि हरियाणा प्रान्त के डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से जगह जगह से टैलीग्राम आ रहे हैं। मुझे भी एक टेलीग्राम अभी अभी मिला है। उसमें लिखा हुआ है कि हमारे प्रांत में प्रस्तावित सेल टैक्स की दरें निकटवर्ती प्रांतों से बहुत अधिक हैं। इससे महंगाई बढेंगी, व्यापार कम होगा, कर की चोरी होगी और रि वत बढेगी। इसलिए कृपा करके इस पर दोबारा विचार करें। स्पीकर साहब, सरकार की प्रजैंट बजट पालिसी ने किसानों और व्यापारियों का भट्ठा बिठा दिया है। दूसरे हमें बजट पर डिसक ान करन के लिए बहुत थोडा टाईम दिया गया है इसलिए आप सै ान का टाईम 25 मार्च के बाद एक हफ्ते का और बढाएं ताकि हम लोग अपनी सारी बातें सदन के सामने रख सकें। (ाोर एवं विघ्न)

Mr.Speaker: Please take your seat.

(2) बिक्री सम्बंधी बैरियर मुंडका (गुडंगांव) में पुलिस द्वारा ट्रक आपरेटरों को तंग करने संबंधी

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने कल एक काल अटैं ान मो ान का नोटिस आपकी सेवा में दिया था कि गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में सवाय माधोरपुर और फरीदाबाद के रास्ते में एक मुण्डका मोड पडता हैं जहां पर पुलिस वाले हर ट्रक वाले से 25 रूपये वसूल करते हैं। मैंने इस बारे में आपसे कल भी पूछा था। आपने कल यह कहा कि मैं उस पर विचार कर रहा हूं।

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, मैं उसे कंसीडर कर रहा हूं। आपके पास उसका जवाब भेज दिया जाएगा। (ाोर)

3 चन्दोंकलां के बारे में गुरनाम सिंह जांच आयोग

चौधरी औम प्रका ाः स्पीकर साहब, चन्दोकलां इंसीडैंट पर जो गुरनाम सिंह कमी ान की रिपोर्ट आ चुकी है। मैंने उसके बारे में आज हाउस भाुरू होने से एक घंटा पहले आपकी सेवा में एक काल अटैं ान मो ान का नोटिस दिया था आपने उस पर क्या फैसला दिया है ?

श्री अध्यक्षः वह मुझे मिल गया है। मैं उसे कंसीडर कर रहा हूं

श्री किताब सिंहः स्पीकर साहब, आज की क्वै चंज लिस्ट में मेरा पहला ही सवाल था उसका सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वह प्र न बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए उसका जवाब इसी सै ान में आना चाहिए।

श्री अध्यक्षः सरकार ने उस क्वै चन का जवाब देने के लिए समय मांगा है। (ाोर)

(4) सै ान का बढाना (पुनरारम्भ)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मुझे भी डबवाली से एक टैलीग्राम मिला है। उसमें लिखा हुआ है कि हमारे प्रांत में प्रस्तावित सेल टैक्स की दरें निकटवर्ती प्रांतों से बहुत अधिक हैं,

इससे महंगाई बढेगी, व्यापार कम होगा, कर चोरी होगा और रि वत बढेगी इसलिए कृपा करके इस पर दोबारा विचार किया जाए। हमने आपसे बी0ए0सी0 की मीटिं में भी रिक्वैस्ट की थी कि इाउस का समय एक हफ्ते के लिए एक्सटैंड कर दें ताकि विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर हमें चर्चा के लिए और समय मिल सके। (ाोर एवं विघ्न)

श्रीमती चन्द्रवती : स्पीकर साहब, जिन टैलीग्राम के बारे में चौधरी वीरेन्द्र सिंह और डाक्टर मंगल सैन ने आपको बताया है उसी तरह का एक टैलीग्राम मुझे भी मिला है। यह टेलीग्राम मंडी डबवाली के राम प्रका ा सेठी, मंत्री, हरियाणा महा व्यापार मण्डल ने भेजा है। इस टेलीग्राम में लिखा हुआ है कि हमारी प्रस्तावित सेल टैक्स दरें निकटवर्ती प्रांतों से बहुत अधिक हैं, इसमें महंगाई बढेगी, व्यापार कम होगा, कर चोरी होंगी तथा रि वत बढेगी कृपा इन पर दोबारा विचार किए जाए। (ाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक मिनट के लिए बोलना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, कल लीडर आफ दि अपोजी ान बहन चन्द्रावती जी भी बोली, चौधरी वीरेन्द्र सिंह भी बोले और अपोजी ान के दूसरे भाई भी बोले लेकिन कल इन्होंने अपनी स्पीच में किसी भी स्टेज पर सेल टैक्स बढने की मुखालफित नहीं की। (ाोर एवं विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः हमें इस बारे में बोलने के लिए टाईम नहीं मिला इसलिए तो हम स्पीकर साहब से रिक्वैस्ट कर रहे हैं कि सै ान का टाईम एक हफ्ते के लिए और बढा दें। (ाोर)

चौधरी भजन लालः आप सुनने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, परसों ये लोग कुछ नहीं बोले और सै ान अपने टाईम से दो घंटे पहले उठ गया। इसका मतलब यह हुआ कि ये अपोजी ान के भाई कुछ नहीं बोलना चाहते। ये वाक आउट इसलिए करतें हैं ताकि इनका नाम अखबारों में आ जाए। (ाोर एवं विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, हम आपसे रिक्वैस्ट कर रहे हैं कि आप बी0ए0सी0 की मीटिंग दोबारा बुलाएं और सै ान का टाईम एक हफ्ते के लिए और एक्सटैंड करें। यह बहुत अरजैंट मैटर है। हम सेल टेक्स के बारे में अपने विचार सदन के सामने रखना चाहते हैं (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जिस दिन बी0ए0सी0 की मीटिंग हुई थी उस दिन हमने यह कहा था कि सै ान को एक्सटैंड करने की जरूरत नहीं है, आप इस भानिवार को और अगलग भानिकवार को सीटिंग कर लें लेकिन मेरे अपोजी ान के भाई इस बात को नहीं माने। इसके अलावा हमने इनसे यह भी कहा था कि आप वीरवार को भी बजट पर बोल लें और जो अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर करनै

के बारे में रैजोल्यू ान आया हुआ है वह हमारी पार्टी के मैम्बर की तरफ से आया है इसलिए हमारी तरफ से उस रैजोल्यू ान पर कोई भी मैम्बर नहीं बोलेगे। वीरवार के दिन हम बजट पर डिसक ान कर लेंगे लेकिन ये मेरे अपोजी ान के भाई नहीं माने। अध्यक्ष महोदय, इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। ये लोग परसों भी सै ान के टाईम से दो घंटे पहले ही सदन से उठ कर चले गए। इनके पास भाोर मचानै के सिवाये कुछ भी बात कहने के लिए नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हाउस का बहुत कीमती समय है। मेरे अपोजी ान के भाई डिबेट में जो भी बात कहेंगे हम उनका जवाब देंगे और इनकी तरफ से जितने भी अच्छे सुझाव आएंगे उन पर विचार किया जाएगा।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, जिस दिन बी0ए0सी0 की मीटिंग हुई थी उस दिन भी मैंने कहा था कि डैमोक्रेसी में तो डैलीबरे ान से बात होती है। स्पीकर साहब, आप समझते हैं कि बजट की 6 मोटी मोटी किताबें हैं अगर कोई मैम्बर बोलने के लिए फुली परिपेयर होकर आता है तो उसको इन किताबों को पढने के लिए दो तीन दिन का समय चाहिए। स्पीकर साहब, मैं आपको सच कहता हूं कि हमें इन किताबों को भााम के वक्त पढते पढते 12.00 बज जाते हैं तब जाकबर हम यहां हाउस में अपनी बात मु कल से कह पाते हैं। मुख्य मंत्री जी यह कहना सरासर गलत है कि हमारे पास बोलने के लिए कुछ भी बात नहीं है। स्पीकर साहब, मेरी रिक्वैस्ट है कि आप हाउस का समय कम से

कम एक हफ्ते के लिए और बढा दें। इतना र ा थ्रू करने की कोई बात नहीं है। यदि मैंने ऐसी कोई बात कह दी तो मुख्य मंत्री जी बुरा मान जाएंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके पास मैजोरिटी है और आपको कोई खतरा भी नहीं है। आप डिफैक ान के मामले में बहुत आगे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सै ान अपने हफ्ते भी चल जाएगा तो इसमें आपको क्या फर्क पडढता हैं हमने सुना है कि राश्ट्रपति जी का भी प्रोग्राम ढीला हो रहा है भाायद वे हरियाणा में आने वाले नहीं हैं। स्पीकर साहब, मेरी अर्ज है कि अपोजी ान को अपनी बात कहने के लिए हाउस में ही समय मिलता है इसलिए आप हाउस को एक हफ्ते के लिए और एक्सटैंड करें। (ाोर एवं विघ्न)

श्री हरि चन्द हुड्डाः स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से मुख्य मंत्री से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी ऐसी विचारधारा नहीं है कि हमारा नाम अखबारों में आए। अगर हम अपना नाम अखबारों में देना चाहें तो हम हाउस से बाहर भी अखबारों को कुछ बातें कह सकते हैं और वह अखबारों में आ सकती है। स्पीकर साहब, दे ा की और प्रांत की सबसे बडी अहम चीज आर्थिक द ाा होती है। हमारे दे ा और प्रांत की आर्थिक द ाा बहुत कमजोर है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट पर बोलने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा टाईम मिलना चाहिए। हमारे पास सरकार की बहुत सी गलत रिपोर्टें हैं और हम उनके बारे में यहां पर अपने विचार रखना चाहते हैं। स्पीकर साहब, यह

बजट इस बार ही पे ा नहीं किया गया है यह तो 30 साल से पे ा होता आ रहा है। यह सरकार इस बजट से किसानों और मजदूरों को तबाह कर रही है। यदि हम इस बजट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे और इस सरकार के गलत कामों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे तो किसान और मजदूर मर जाएंगे। इसलिए स्पीकर साहब, हाउस को एक हफ्ते के लिए एक्सटैंड किया जाए ताकि हम अपने पूरे विचार सदन के सामने रख सकें।

श्री अध्यक्षः आप बैठिये, मैं इसे देख लूंगा।

गैर सरकारी बिल

दि हरियाणा अर्बन (कंट्रोल आफ रैंट एंड इविक ान) अमैंडमैंट बिल, 1983

श्री अध्यक्षः अब श्री कंवल सिंह एम0एल0ए0 हरियाणा अर्बन (कंट्रोल आफ रैंट एंड इविक ान) अमैंडमैंट बिल, 1983 इन्ट्रोडयूस करने के लिए हाउस से परमि ान लेंगे।

Sh. Kanwal Singh: Mr. Speaker, Sir I beg to move-

That leave be granted to introduce the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendement Bill, 1983.

Mr. Speaker: Motion moved –

That leave be granted to introduce the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendement Bill, 1983.

श्री कंवल सिंह (घिरायेङः स्पीकर साहब, आजादी के बाद इस दे ा की राजनीति में परिवर्तन आया। सबसें पहले इस दे ा में चार सौ से ज्यादा रजवाडों को खत्म किया गया। इस दे ा में ज्यों ही कांग्रेस सरकार ने अपनी नीति लागू की तो भाहरों के बीच में एक करप्ट पोलिटि ायन और इंडस्ट्रीयलिस्ट की नई क्ला पैदा हो गई है। यह जो नई इंडस्ट्रीयलिस्टस क्लास पैदा हुई उसने एक पैरेलल इकानोमी पैदा की। इनकी वजह से दो नम्बर का पैसा बढ रहा है। और भाहरों के अंदर इनवैस्ट हो रहा है। लोग इस दो नंबर के पैसे से बडी बडी बिल्डिंगे तैयार कर रहे हैं। वे उनका नाजायज तौर पर इस्तेमला करते हैं। इमारत तैयार करके वे उसको किराये पर दे देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता। सरकार ने देहात के अंदर तो जमीन पर सीलिंग लगा दी है कि किसी भी व्यक्ति के पास 18 एकड से ज्यादा जमीन नहीं रहेगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि भाहरों में भी जायदाद पर इसी तरह की पाबंदी लगाई जाये। भाहरों के अंदर इस प्रकार की प्रोपर्टी अंधाधुंध बढती जा रही है। आप देखेंगे कि अकेले बिडला के पास 1100 करोड रूपये से भी अधिक की सम्पति है। यह सम्पति हिन्दुस्तान के गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले दो करोड परिवार के बराबर है। स्पीकर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पैसा भाहरों में नाजायज तौर पर लग रहा है उससे पैसे का दुरूपयोग ही हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा

है। स्पीकर साहब, मैं इस बिल में अमैंडमैंट तो पूरी देना चाहता था लेकिन पूरी इसलिए नहीं दी क्योंकि जो लोग सरकार सव्रिस में हैं, आर्मी में हैं या दूसरी जगह काम करते हैं और वे नौकरी में रहते हुए अपनी बिल्डिंग बनाते हैं यानी अपना मकान बना लेते हैं तो रिटायरमैंट के बाद वे चाहते हैं कि अपने घर में रहें। इसलिए मैंने रेजिडेंि ायल प्रौपर्टी पर जो 10 साल की छूट मिली हुई है, उसको रनहे दिया है क्योंकि कोई भी कर्मचारी अपने मकान को रिटायरमैंट के बाद खाली करवा कर उसमें खुद रहना चाहेगा। इसलिए मैंने अमैंडमैंट में रेजिडैि ायल बिल्डिग को नहीं लिया है। एक्ट में 10 साल की जो प्रोवीजन है उसको बहाल रखा है कि कोई भी कर्मचारी अपने मकान को रिटायरमैंट के बाद या उससे कुछ समय पहले खाली करवा सकता है। स्पीकर साहब, भाहरों में बेथाह लोग बडी बडी बिल्डिंग बनाकर किराये पर दे देते हैं। किसी को दो सौ रूपया महीना, किसी को 400 रूपये महीनाय या किसी को 2000 रूपये महीना या जिसकी जितना पैसा देने की क्षमता है, उस हिसाब से पैसा देकर दुकान को किराया पर ले लेता है लेकिन जिन लोगों की ये दुकानें होती हैं यानी मालिक लोग दो चार साल बाद या तो दुकान खाली करवा लेते हैं या फिर उसका किराया बढा देते हैं जिससे वहां पर काम करने वाले व्यक्ति को काफी परे ाानी होती है। मालिक लोग कई बार तो उनसे पगडी भी मांग बैठते हैं जिसका रिटन में कोई हिसाब किताब नहीं होता। इस संबंध में लोगों की तरफ से मुख्य मंत्री महोदय को एक दो दफा मैमोरैण्डम भी दिया गया है। सी0एम0

साहब ने पब्लिकली वायदा किया था कि हम इस पर विचार करेंगे और हाउस में भी भाायद पहले इस किस्म का एक बिल आया था। अब मैं फिर सी0एम0 साहब से अपील करता हूं जो वायदा इन्होंने किया था। उसको निभायें लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो लोग दुकानें किराये पर लेते हैं उन्हें दुकान मालिक साल या दो साल के बाद ही किराया बढाने के लिए कहता है और उसे परे ाान करता है। जब किरायेदार का बिजनेस जम जाता है तो मालिक उसे परे ाान करता है और उससे अनरिजनेबल डिमांड कर बैठता है जिसके कारण या तो किरायेदार किराया बढा देता है या फिर अपना बिजनैस छोड कर चला जाता है। अब यह सोचने की बात है कि जिस दुकान पर बैठकर उसने काम किया है उसका 10 साल के अंदर अच्छा बिजनैस जम जाता है तो एक्ट के हिसाब से मालिक अपनी दुकान को 10 साल के अंदर खाली करवा सकता है। जब कोई दुकानदार 8–10 साल एक जगह पर बैठकर कोई बिजनैस करता है तो नैचुरली उसका बिजनैस अच्छा. चलेगा। यदि उससे वह दुकान अनरिजनेबल डिमांडों के कारण खाली करवा ली जाती है तो उसका सारा बिजनैस फेल हो जाता है। उसका सारा परिवार तबाह हो जाता है। आपने गांवों के अंदर तो जमीन पर सीलिंग लगा दी है और आप समझाना चाहते हैं। ठीक बात है, हम भी चाहते हैं कि समानता आये। सीलिंग लगाने से कुछ हद तक देहात में समानता आई भी हैं स्पीकर साहब, इस असमानता को समाप्त करने के लिए ये गांधी जी का नाम ले रहे हैं। स्पीकर

साहब, जिस प्रकार से इस दे ा के अंदर डुप्लीकेट पैरेलल इकोनोमी खडी हो गई है उसी प्रकार से यहा ंपर डुप्लीकेट गांधी पैदा हो गए हैं। अभी दो चार रोज पहलें इन्होंने महात्मा गांधी जी फिल्म देखी होगी। उनकी लाईफ पर विचार करे सरकार को काम करना चाहिए। आप कहते हैं कि हमने यह कर लिया वह कर लिया और आप यह भी कहते हैं कि गुटनिरपेख सम्मेलन करके हममने बहुत बडा काम किया है आप इस तरह की बातेंं छोड कर अच्छे काम करें। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि आप अर्बन प्रोपर्टी पर सीलिंग लगायें। मैंने जो अमैंडमैंट दी है उसका मुद्दा यही है कि जो कमि र्यिल भाौप्स में बैठे हैं उनको यह राहत दी जाये। जो 10 साल की बेदखली का जो प्रावधान है वह खत्म किया जाये। अन्त में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो मेरी अमैंडमैंट है उसको स्वीकार किया जाये।

स्थानीय भाासन राज्य मंत्री (श्री ए0सी0 चौधरी): स्पीकर साहब, भाई कंवल सिंह जी ने अमैंडमैंट रखी है मैं उसका विरोध करने के लिए खडा हुआ हूं। सरकार जनहित कामों के लिए वचनबद्ध है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह किसी व्यक्ति वि ोश या किसी वर्ग वि ोश को न देख कर सामूहिक तौर पर अपने स्टेट के लोगोंं के हितों की रक्षा करें। जैसा कि भाई कंवल सिंह जी ने यह अमैंडमैंट रखी है इसका मैं विरोध करता हूं। इसमें कई किस्म की परे ाानियां हैं। लेकिन जहां तक सरकार के पार्ट का ताल्लुक है, जब यह एक्ट बनाया गया उस समय कई

बातें सरकार के सामने आई थी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के प्रधान उस वक्त मंगल सैन थे और वीरेन्द्र सिंह जी उस कमेटी के मैम्बर थे। इस कमेटी के अंदर व्यापारियों और अपने प्रदे ा के अच्छे अच्छे वकीलों को बुला कर इस मामले पर विचार विम र्ा किया गया था। उसी अधार पर हमने इस एक्ट को मोडिफाई किया। अगर प्रस्तावित अमैंडमैंट स्वीकार हो जाती है तो उसका बहुत बुरा पडेगा। एक तो जो पैसा कामर्ियल बिल्डिंगों पर लगा हुआ है उसको कोई सोल्यू ान नहीं होगा। तीसरे एक ऐसी बीमारी पैदा हो जाएगी जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं होगा क्योंकि किसी किस्म की खामी नहीं है तो मैं प्रस्ताव करूंगा कि इसे स्वीकार न किया जाये। मैं इस अमैंडमैंट की अपोज करते हुए भाई कंवल सिंह जी से कहूंगा कि वे इसे विदड्रा करें। सरकार ने इस एक्ट के जरिए जो अपने नियमित काम चलाये हुये हैं उन्हें चलते रहने देना चाहिए। अंत मे मैं इस अमैंडमैंट का विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

Mr. Speaker: Question is-

That leave be granted to introduce the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill, 1983.

The motion was lost.

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, थोडी देर पहले मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि मैंने सैल्ज टैक्स के खिलाफ कुछ नहीं

बोला है। जनाब, आप रिकार्ड देख लें, यह तो रिकार्ड की चीज है, मैंने सेल्ज टैक्स लगाने के खिलाफ बोला है, आप रिकार्ड देख लें।

श्री अध्यक्षः आप कृपया बैठिए।

गैर सरकारी संकल्प–

अम्बाला तहसील को औद्योगिम दृश्टि से पिछडा क्षेत्र घोशित करने संबंधी (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Now the House will resume discussion on the non official resolution moved by Seth Ram Dass Dhamija on the 10th March, 1983.

Thakur Bahadur Singh, Who was on his legs on that day, may please resume his speech.

ठाकुर बहादुर सिंह (दड़बा कलां): स्पीकर साहब, धमीजा साहब ने अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड घोशित करने के लिए जो रैजोल्यु ान दिया था, उस दिन इस पर मैं बोल रहा था। मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि सारे हरियाणा में सिर्फ अम्बाला तहसील ही ऐसी तहसील नहीं है जो इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड है, इस किस्म के और भी इलाके हैं जो इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड हैं। हरियाणा के बहुत से इलाके ऐसे हैं जो सिर्फ खेती पर ही निर्भर करते हैं और खेती से उनको बहुम कम

मुनाफा है। इंडस्ट्रीज के मुकाबले में इन इलाकों को बहुत ही कम रिटर्न है। मैं हाउस के मैम्बरान से अर्ज करूंगा और मैंने उस दिन भी आपके माध्यम से प्रार्थना की थी कि जिला सिरसा भी बहुत बैकवर्ड है और यह हरियाणा के एक कौने में पडता है। यह सारे का सारा जिला खेती पर निर्भर करता है। खेती से बहुत अच्छी प्रोडक ान होती है और यहां पर चावल, कपास, आयल सीड पैदा होता है। लेकिन जैसे सारे हाउस के मैम्बरान खास तौर पर अपोजी ान के भाई कहते हैं कि सिरसा जिले में ओला वृश्टि से और मौसम खराब होने से बहुत नुकसान होता है। ठंडी गर्म हवा चलने से फसल का नुकसावन होता है बारि ा न होने की वजह से नुकसान होता है और मौके पर स्प्रे न होने की वजह से काटन की फसल खराब हो जाती है। ऐसे इलाके जहां पर सब लोग खेती पर निर्भर करते हैं, इनकी फसल पर कुदरती आफतें आप जाएं तो खेती एक किस्म से घाटे का काम हो जाती है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि इन इलाकों के लोगों को सहारा दिया जाए ताकि वे मुनाफाबख्भा काम कर सकें। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी ई वर सिंह पदासीन हुए।) इनको एक ऐसा सहारा दिया जाए जो एक इंडस्ट्रीज कौ मिलता है। मैं समझता हूं कि कोई भी इंडस्ट्री 25 परसैंट से कम मुनाफे पर काम नहीं करती। कोई भी बिजनैसमैन 25 परसैंट से कम मुनाफ पर इंडस्ट्री नहीं चलाता। लेकिन किसान इस मामले में भोला है, वह घाटे में खेती किये जा रहा है। सिरसा जिला बार्डर का जिला है। पंजाब के एरिया से जब सिरसा

जिले में दाखिल होते हैं तो बिजली को देखकर ऐसा मालूम होता है कि दीवाली मनाई जा रही है। जब सडकों को देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि हम किसी दूसरे इलाके में आ गये हैं लेकिन इंडस्ट्रीज के लिहाज से सिरसा में कुछ नहीं पंजाब स्टेट एक इंडस्ट्रीज स्टैट है और हरियाणा के मुकाबले में काफी आगे हैं। जब पंजाब से हरियाणा में दाखिल होते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि यहां पर इंडस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं है। चेयरमैन साहब, सिरसा जिले में लैंड सीलिंग हुई। लैंड सीलिंग करते समय लोगों को जमीन का मुआवजा मिला लेकिन लोगों के पास ऐसे जरिये नहीं जहां इस पैसे का सही इस्तेमाल कर सकें। लोगों का दिमाग इंडस्ट्रीज की तरफ लगा हुआ है लेकिन इस दिमाग को इस्तेमाल के लिए कोई साधन नहीं हैं। क्या सिरसा जिले में इंडस्ट्रीयली बैकवर्डनैस पक्के तौर पर लिखी हुई है ? सैंट्रल सबसिडी इस जिले को नहीं मिलती। यहां के लोग काम करने के लिए दूसरे जिलों में जाते हैं, जहां इनको मौका मिलता है वहां काम करते हैं, लेकिन अपने जिले में इन्हें कोई काम नहीं मिलता। सारे के सारे लोग खेती पर ही गुजारा करते हैं लेकिन कुदरती कहत की वजह से खेती की पैदावार से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों के निर्वाह के लिए क्या रास्ता है, क्या यह हाउस इस बात की तरु ध्यान नहीं देगा ? जहां तक सिरसा जिले में डिवैल्पमैंट का ताल्लुक है, सरकार खेती की हिफाजत के लिए हवाई जहाज से स्प्रे करना चाहती है लेकिन जब हवाई जहाज जाता है तो जगह जगह पर लगी हुई बिजली की तारे रूकावट बन जाती हैं।

क्योंकि हवाई जहाज से एक्सीडैंट होने का खतरा रहता है। हवाई जहाज टूट जाते हैं। पिछले दिनों स्प्रे करने के लिए हैलीकाप्टर भेज दिया था ताकि सारे इलाके में पूरे तौर पर स्प्रे किया जा सके लेकिन स्प्रे हो नहीं पाया। खैर यह मजबूरी है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। चेयरमैन साहब, सिरसा जिले का किसान एक मेहनती किसान है, इसने ऐसे इलाके को आबाद किया है जो बिल्कुल डैजर्टिड एरिया था। इसने डैजर्टिड एरिया को आबाद किया है। जाहं तक पानी के साध्न का ताल्लुक है, यह एक फतेहाबाद ब्रांच है। यह तीन प्रोसैस में चलती है। इसकी लाइनिंग होने के कारण चार हफ्ते बंद रही और जब लाइनिंग हुई तो फिर दोबारा टूट गई। यह चार महीनें लगातार बंद रही। इससे पानी न मिलने के कारण सारा इलाका कहत की लपेट में आ गया। लोगों ने पानी की कमी को महसूस करते हुए टयूबवैल्ज लगाये लेकिन ये टयूबवैल्ज 110 फुट तक गहरे हैं। चेयरमैन साहब, हरियाणा प्रांत में कुछ इलाके ऐसे हैं जिन में टयूबवैल की 80 फुट तक की गहराई तक रियायत दे रखी है, लेकिन सिरसा जिला जहां केवल 1300 गांव हैं, यह रियायत नहीं दी गई।

चेयरमैन साहब, जहां तक होस्पिटल का ताल्लुक है, हरियाणा के हर जिले में नये होस्पिटल बनाये गये हैं, लेकिन सिरसा के होस्पिटल की बिल्डिंग काफी अर्सा से अंडर कंस्ट्रक ान पडी है। एक होस्पिटल चौधरी देवी लाल ने मुकम्मल करवाया था लेकिन उसको बनाते वक्त न तो सारे जिले को लोगों का ख्याल

किया और न उस इलाके के लोगों का ख्याल किया। इसको सिरसा जिले के एक कोने पर ले गये। यह होस्पिटल राजस्थान के बार्डर पर है। इस लिहाज से भी सिरसा जिला बहुत पिछडा हुआ है।

चेयरमैन साहब, तालीम के लिहाज से भी सिरसा जिला बहुत पीछे रह गया है। तालीम भी नहीं, खेती भी नहीं और इंडस्ट्री भी नहीं, लोग जायें तो जायें कहां। जहां तक पंचायतों का ताल्लुक है, सिरसा जिला में ऐसे ब्लाक हैं जिनमें सबसे ज्यादा पंचायते हैं। एक एक ब्लाक में दो दो ब्लाक बनाये जा सकते हैं। इन लोगों को तरक्की देने के लिए मेरी आपसे दुर्ख्वास्त है कि इन बातों की तरफ ध्यान दिया जाए। ये चीजें हो नहीं पा रही, हमें यकीन है कि ये हो जाएंगी लेकिन होंगे तब जब सरकार के पास साधन होंगे। जहां तक इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, यह मामला बडा गंभीर है। जो कहतजदा इलाके हैं यानी जिन इलाकों को कहतजदा घोशित किया जाता है, उस इलाके में खराबा का इंदराज पटवारी के कागजों में होता है।

11.00 बजे।

चेयरमैन साह, अगर एक खेत बारि ा न होने के कारण बीजा ही नही ंगया और दूसरी ओर किसी एरिया में थोडी बहुत बारि ा हो गई तो वह बीज दिया गया। अब जिस एरिया को बीजा गया था उसे तो कहतजदा एरिया घोशित कर दिया गया

लेकिन जिसका बीजा ही नहीं गया उसे कहतजदा घोशित नहीं किया गया। सिरसे का डेजर्ट एरिया है। वहां बारि ा भी कम होती है और बारि ा कम होने के कारण बीज भी नहीं डाला जाता लेकिन उसे कहतजदा डिक्लेयर नहीं किया जाता है। नुकसान हो सभी को हुआ है। इसलिए सबके साथ बराबर का व्यवहार होना चाहिये। जिनका बीज का नुकसान हुआ है उनको फायदा हो सकता है तो जिनके यहां बीज डाला ही नहीं गया उनको भी होना चाहिये।

एक मैम्बरः यह प्रस्ताव अम्बाला तहसील के बारे में है लेकिन यह सिरसा जिले की बात कर रहे हैं।

ठाकुर बहादुर सिंहः ये कह रहे हैं कि ये बातें नहीं करनी चाहिएं। मैं किसानों के बारे में कह रहा हूं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि ये बातें नहीं करनी चाहिय दूसरी ओर आप हाउस को एक्सटैंड कराने की बात करते हैं किसानों की भलाई की बातें हाउस में आनी चाहिएं। (विघ्न)

Sh. Hira Nand Arya: Sir, he is not speaking on the resolution.

Mr. Chairman: He can state his view points. He can stretch his view points by co relating these facts (Noise & Interruptions)

Sh. Hira Nand Arya: But, Sir, hie is not speaking about industrial backwardness. This is not the cental point of the resolution under discussion.

Mr. Chairman: Backwardness of the area is the central Point. Please let him speak. Arya Sahib, you will also get enough time to speak. Please do not interrupt him. (Noise and interruptiosn).

श्री हीरा नन्द आर्यः चेयरमैन साहब, अम्बाला तहसील के बारे में प्रस्ताव है, उसी के बारे में बोलना चाहिए। आप इन्हें कहें कि ये रेलेवेन्ट बोलें। (विघ्न)

श्री सभापतिः आप कृपया बैठिए।

ठाकुर बहादुर सिंहः चेयरमैन साहब, मैं सरकार के समर्थन की बात नहीं कर रहा हूं। सब चीजों के लिए सरकार आल्टरनेटिव तैयार कर रही है तो किसानों के लिए भी कोई आल्टरनेटिव प्रोवाइड क्यों नहीं कर रही ताकि वे भी अपनी तरक्की कर सकें। (विघ्न)

श्री हीरा नन्द आर्यः चेयरमैन साहब, अगर ये सारे हरियाणा को ही बैकवर्ड डिक्लेयर करवा लें तो हमें इसमें कों ऐतराज नहीं। लेकिन जो बातें ये कह रहे हैं उससे तो हाउस का टाईम ही वेस्ट कर रहे हैं।

Mr. Chairman: Arya Sahib, kindly do not interrupt. You will also get enough time to speak. (Noise & Interrupsion)

ठाकुर बहादुर सिंहः चेयरमैन साहब, मैं यही अर्ज कर रहा था कि हर आदमी को हर हालत में सुविधायें दी जानी चाहिएं। जहां पर नहर नहीं हैं, वहां पर पानी दिया जाये। जहा

पर नहर का पानी नहीं लगता है। वहां टयूबवैल्ज लगाये जायें। चेयरमैन साहब, आज हरियाणा में यह हालत हैं कि दस बीघे और 10 एकड जमीन पर बीस आदमी बैठे हुए हैं, इतनी थोडी जमीन में उनका गुजारा कैसे हो सकता है ? आज के दिन खेती फेल हो गई है। वे बेचारे गरीब किसान और मजदूर कहां जायें ? आईटीआई या पोलिटैक्निकल कालेजिज से लडकों ने ट्रेनिंग भी ली है लेकिन वे आज रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। वहां पर उनके लिए कोई इंडस्ट्रीद नहीं है वे लोग तो वही काम सीखेंगे जो उन्हें सिखाया जाता है। वे लोगों क पीछे पीछे भागे फिरते हैं कि उन्हें नौकरी दिला दे। आज के दिन दूसरे भाहरेां में तो इंडस्ट्री हैं लेकिन हमारे यहां इंडस्ट्री का कोई प्रबंध नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज किसान बडी भारी मुसीबत में फंसा हुआ है। उसे आज क्यों नहीं मौका दिया जता है कि वह भी इंडस्ट्री की ओर आये। जब इस इलाके को बैकवर्ड घोशित किया जाए तो वहां भी सारे धान और सुविधाएं प्रदान की जाएं। आज के दिन ये लोग दल दल में फंसे हुए हैं। इस गंदगी से इन लोगों को बाहर निकाला जाए ताकि वे अपना अच्छा जीवन बिता सकें और खु ाहाल होकर रह सकें। (विघ्न)

चेयरमैन साहब, यह भाई चाहे कुछ भी कहें लेकिन मैं यह कहने से नहीं चुकूंगा कि हमारी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आज वहां पर प्रोब्लम ही प्रोब्लम हैं। भाायद कई

भाईयों के दिमाग्र में यह बात हो कि पहला मुख्य मंत्री सिरसा जिले का रहने वाला था इसलिए वहां डिवैल्पमैंट हो गई होगी। वे उस इलाके को डिवैल्प करना चाहते थे लेकिन वे नहीं कर सके। अपने जिले पर तो उनकी नजर थी लेकिन वे अधिक समय तक नहीं रह सके। वहां आज पानी की प्रोब्लम हैं। घग्गर का पानी उस इलाके में जात है। उस पानी से वहां बिजली जनरेट की जा सकती है। बिजली पैदा करके वहां पर इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। वहां पर जो लो वाटरिंग है उसे भी दूर किया जा सकता है। वहां पर कोई प्रोजैक्ट बनाया जा सकता है। घग्गर के पानी को इरीगे ान के लिए भी यूटेलाइज किया जा सकता है। राजस्थान वाले कह रहे हैं कि यह पानी हमारे को बहुत नुक्सान पहुंचा रहा है। अगर नुक्सान करता है तो उसे क्यों नहीं इस्तेमला किया जाता है ?

खेती तो हम मजबूरी के कारण करते हैं। हमारे बुजुर्ग भी पहले से खेती करते थ। दूसरा काम न होने के कारण और कहां जा सकते हैं ? पहले यह कहा जाता था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार लेकिन वह बात नहीं है। खेती के लिए इतनी जमीन नहीं है। हमें अब दूसरी ओर जाना पडेगा तभी किसानों की उन्नति हो सकती है। आज जब हम यह देखते हैं कि सब लोग हमारे से आगे निकल गये हैं और हमारे इलाके से तो दूसरे इलाके के लोग भी बहुत ज्यादा आगे निकल गये हैं। हमारे इलाके के लोग खेती के कारण एक प्रकार से दलदल में फंसे हुए है।

एक घर में दस बीस आदमी होते हैं और जमीन थोडी होती है तो वे किस प्रकार से अपना गुजारा कर सकते हैं। विरोधी दल के भाईयौं को भी इस बात का समर्थन करना चाहिए कि किसान दूसरे साधन अपनायें ताकि वह भी दूसरे लोगों की तरह आगे बढ सकें। जब फाईनैंस मिनिस्टिर साहब ने अपने बजट में प्रोविजन किया है तो हमें किसानों को इंडस्ट्री की ओर ले जाजना चाहिए। मैं अपने काबिल आनरेबल मैम्बरान से रिक्वैस्ट करूंगा कि यह बहुत ही इम्पोर्टैंट इ ू है। इस पर हमें बडी संजीदगी से विचार करना चाहिए। जब हम जीत कर आये तो लोगों से यह बादा करके आये हैं कि आप लोगों को सुविधायें देंगे। आपकी तरक्की के साधन जुटायेंगे, तरक्की के साधन आपके घरों और दरवाजों तक पहुंचायेंगे। आज वह वक्त है। हमें गलत बात की मुखालफत करनी चाहिए लेकिन जो जायज बातें हैं उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। (विघ्न) अगर आप समझते हैं कि मैं टाईम जाया कर रहा हूं तो यह बहुत गलत बात है। मैं हाउस का टाईम बरबाद नहीं कर रहा बल्कि हाउस के सामने अच्दी सुजै ांज दे रहा हूं। कि इस तरीके से लोगों का भला हो सकता है। हम लोग यहां किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं आज के दिपन किसान खेती पर गुजारा नही कर सकतां उसके पास खेती के लिए जमीन नही रही। जब साधन ही नहीं रहेंगे तो वह खेती पर कैसे गुजारा कर सकता है। आज के दिन ईल्ड कम है और कन्जैम्प ान ज्यादा है इसलिए खेती से दस आदमियों के परिवार का दस बीघे में गुजारा नहीं हो सकता। पहले पांच आदमी का परिवार 34 एकड पर

गुजारा कर सकता था लेकिन आज कि दिन तीस आदमियों का परिवार दस एकड जमीन पर गुजारा कर रहा है। आज के दिन तो एक एक आदमी के गुजारे के लायक भी जमीन नहीं रही। पहले जमीन के काम पर मजदूर लगा लिये जाते थे लेकिन आज वह मजदूर कहां से लगागये, उसकी अपनी ही फैमिली के मैंबर बहुत हैं। उन्हें ही काम नहीं मिलता है। आज किसान और मजदूर भटक रहे हैं। जिसके पास जमीन थी उसके ही मैंबर बहुत ज्यादा हो गये हैं। आज किसानों को मौका दिया है। सरकार ने साधन जुटाये हैं भेड बकरियां पालने के लिए पैसा दिया है, भैंसे और ऊंट गाडियां खरीदने के लिए पैसा दिया ताकि वह अपना काम कर सकें। (विघ्न) चेयरमेन साहब यह किसानों का इ I है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। (विघ्न)

चेयरमैन साहब मैं हाउस का टाईम जाया नहीं कर रहा हूं।

Sh. Hira Nand Arya: Mr. Chairman, Sir, is there any time limit ?

Mr. Chairman: There is not time limit, please let him speak.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री अमर सिंह): आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। रेज्योयू ान पर बोलते समय टाईम की कोई लिमिट नहीं होती। (Noise & Interruptions)

Sh. Hira Nand Arya: Sir, he is wasting the time of House.

Mr. Chairman: I have already said that there is not time limit. Arya Sahib, you may also speak as much as you like when your turn comes. Please take you seat and let hime continue.

(श्री भागी राम की आरे से विघ्न)

ठाकुर बहादुर सिंहः भागी राम जी, मैं आपके इलाके की भी बात कर रहा हूं। मुझे अफसोस यह है कि आप अपोजी ान में बैठे हुए ऐसी बाते ंकर रहे हों।

श्री भागी रामः आप अपना ख्याल रखो।

श्री ठाकुर बहादुर सिंहः आप बीच में इंट्रप्ट क्यों कर रहे हैं ? आप मेरी बात तो सुनें। मैं यह अर्ज कर रहा था कि किसान का जमीन पर अब गु जारा नहीं होता।

Mr. Chairman: You may try to cut short your speech.

ठाकुर बहादुर सिंहः मैं तो पहले ही कट भाोर्ट कर रहा हूं। वैसे तो यह एक ऐसा मसला है जिस पर बहुत सी बातें कही जा सकती है। लेकिन मुसीबत यह है कि अपोजी ान वाले भाई हमारी बातों को सुनना पसंद नहीं करते। मैं किसान के लिये बोल रहा हूं। ये किसान के मुफ्त में नेता बने फिरते हैं और अपने आपको किसानों के नेता कहलाते हैं। मैं किसान के हितों की बात

कर रहा हूं आप सुनने की कोि ा ा कीजिये। (व्यवधान व भाोर) आज के दिन खेत पर किसान का गुजारा नहीं होता। तो उसके लिये कोई दूसरा साधन ढूंढना पडेगा ताकि किसान अपना गुजारा कर सके। अपना जीवन खुद निर्वाह कर सकें। किसी दूसरे पर उसे डिपैंड न करना पडे।

श्रीमती चन्द्रावतीः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। चेयरमैन साहब, अभी दूसरे लोगों ने भी बोलना है। आपको पता ही है कि ये काफी देर से बोल रहे हैं। इनको आधा पौना घंटा हो गया है। आखिर कोई समय तो नि चत होगा कि यह कितनी देर और बोलेंगे। (व्यवधान व भाोर)

Mr. Chairman: I have already asked him to cut short his speech.

ठाकुर बहादुर सिंहः चेयरमैन साहब, मैं अपनी स्पीच को कट भाार्ट ही कर रहा हूं। यह तो सबके इलाके की बात है। आप सुनने की कोि ा ा तो कीजिये मैं सारे हरियाणा की बात कर रहा हूं। मैं अकेले एक गांव की बात नहीं कर रहा हूं कि फलां जगह सहूलियत दी जाये क्योंकि वहां पर ओला वृश्टि हो गयी है। मैं कोई फालतू बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो यही बात कह रहा हूं कि किसान को साधन प्रोबाईड किये जायें और वे धान तभी प्रोवाईड हो सकते हैं जब सारे हरियाणा को ही इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर किया जाये। जब तक सारे हरियाणा को इंडस्ट्रीयली बैकर्वा डिक्लूयर नहीं किया जाता तब तक किसानों

का भला नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास जमीन के अलावा और कोई साधन नहीं है और आज जमीन प्रति परिवार बहुत कम रह गयी हैं। मैं चाहता हूं कि सिरसा जिला को भी इसमें इन्कल्यूड किया जाये। अगर सिरसा जिले को बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो जिस तरह से सिरसा जिला ने खेती के मामले में एक रिकार्ड कायु किया है उसी तरह से सिरसा जिला इंडस्ट्री में भी रिकार्ड कायम करेगा। यह हरियाणा का दूसरा फरीदाबाद बन जायेगा और सारे हरियाणा को मालामाल कर देगा और इससे सारे हरियाणा की तरक्की होगी। अंत में यही कहना चाहता कि सारे हरियाणा की बेहतरी इसी में है और किसानों की तो वि ोशकर है कि सिरसा जिले को इस रैज्योलू ान में एड कर लिया जाये। (विघ्न) चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिये इनसे यह विनती कर रहा हूं। आप इनको समझाइये। ये भाई अपने आपको किसान का बहुत बडा हितैशी मानते हैं (व्यवधान व भाोर)

श्री सभापतिः आप दो मिनट में समाप्त कीजिये।

ठाकुर बहादुर सिंहः बहुत अच्छा जी। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि आज किसान जिस दल दल में फंसा हुआ है,उसमें से उसे निकालने का एक ही उपाय है कि हरियाणा में इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिये। उसके लिये यह उचित ही है कि सारे हरियाणा को बैकवर्ड डिक्लेयर किया जाये। आपको पता ही है किसान को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिये कर्जा लेना पडता है। कई बार कुदरत भी उसका साथ नहीं देती। अभी

ओला वृश्टि की वजह से, तो कई बार सूखे की वजह से उसको सरकार की ओर देखना पडता है। वह अपना काम कर्जा ले लेकर चलाता है। चेयरमैन साहब, ऐसा प्रावधान इसलिये भी जरूरी है ताकि वह कुदरती आपदाओं से लड सकें और अपने पैरों पर खडा हो सके। यह तभी हो सकता है जब इंडस्ट्री हमारे हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा लगे। छोटी इंडस्ट्री से कोई ज्यादा फायदा उसको पहुंचने वाला नहीं है। इसलिये जब तक बडी इंडस्ट्री नहीं लगेगी तब तक किसान को फायदा नहीं पहुंचेगा। अंत में मेरी प्रार्थना है कि सिरसा जिले को भी इस रैज्योलू ान में भाामिल किया जाये। मैं यह इसलिये चाहता हूं कि हमारे जिले के किसान भी अपने पैरों पर खडे हो सके। दूसरे सरकार से जो रोज रोज पैसा मांगने वाली बात है, वह भी समाप्त हो जायेगी। चेयरमैन साहब, अंत में आपको भाुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री हरि चन्द हुड्डा (किलोई): चेयरमैन साहब, मैं आपका भाुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ठाकुर साहब के प चात बोलने का मौका दिया है। मैं सबसे पहले एक ही बात कहूंगा कि हरियाणा में इंडस्ट्रियल सैक्टर होना चाहिये क्योंकि इंडस्ट्री एक धन की कुंजी है। जब तक हरियाणा में यह धन की पूंजी नहीं लगेगी तब तक हरियाणा में डिवैल्पमैंट नहीं हो पायेंगी। इस धन की पूंजी को तला ा करने के लिए हमें यह देखना पडेगा। जिस तरह से ताले की ताली से खोला जा सकता है, उसी तरह से इस

धन की पूंजी को खोलने के लिए पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे प्रदे ा का किसान मजबूत है या नहीं। जब यहां का हाली मजबूत हो तो फिर हमें यह देखना होगा कि यहां का बैल भी मजबूत हो। जब हमारे हाली और बैल दोनों मजबूत होंगे तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कृशि भी मजबूत हो। अगर हमारी कृशि मजबूत होगी तो हमारी इंडस्ट्री भी मजबूत होगी। अगर इंडस्ट्री मजबूत होगी तो हमारे यहां रोजी रोटी की स्थिति भी मजबूत होगी। अगर रोजी रोटी की स्थिति मजबूत होगी तो हमारा प्रदे ा भी खु ाहाल होगा। अगर प्रदे ा खु ाहाल होगा तो दे ा भी खु ाहाल होगा। अगर दे ा खु ाहाल होगा तो वाहं पर गौड का या परमात्मका का वास होगा। मगर जहां पर किसान मजबूत नहीं है बैल मजबूत नहीं है, कृशि मजबूत नहीं है, इंडस्ट्री मजबूत नहीं है, रोजी रोटी की स्थिति मजबूत नहीं है वहां पर परमात्मा का काप होगा है। वह कोप क्या होता है ? इंडस्ट्री न होने से दे ा में रोजी रोटी नहीं मिलती, अन एम्पलायमैंट ज्यादा होती है, स्मगलिंग होती है, हेरा फेरा होती है, डिफैक ान होती है, बीमारी आती है और वह दे ा या प्रदे ा या वह इलाका उजड जाता है। अगर हमारे हिन्दुस्तान में आज किसान मजबूत होगा तो सब चीजें खुद ब खुद मजबूत हो जायेंगी। रोजी रोटी मजबूत होगी, इंडस्ट्री मजबूत होगी, कृशि मजबूत होगी और वहां पर परमात्मा का वास होगा मगर दरअसल बात यह है कि जितने भी 17–19–20 डिवैल्पड कंट्रीज दुनिया में हैं, वहा ंपर किसान को परमात्मका मान कर चला जाता है। वहां पर किसान की पूजा की जाती है।

मगर यहां पर हिन्दुस्तान में तो किसानों को वहां पर किसान की पूजा की जाती है। मगर यहां पर हिन्दुस्तान में तो किसानों को जाहिल बेवकूफ गधे और कुत्ते समझा जाता हो, या इस किस्म की चीज समझा जोय वहां पर परमात्मा का वास कभी नहीं हो सकता। आज 35 वर्श हो गये हैं। इस दे ा को आजाद हुए लेकिन इस दे ा के अंदर हर प्रकार की हेराफेरी होती है, स्मगलिंग होती है, डिफैक ान होती है और पता नहीं क्या क्या होता है। मैं यह इसलिये कहता हूं कि हरियाणा वालों ने जो किसान के साथ पाप किया है और उसकी बेइज्जती की है, उस वजह से आज सारे हिन्दुस्तान में गिरावट आ रही है। किसान को इन्होंने पैर की जूती समझा है और खुद हेराफेरी की है। इसलिये मेरा कहना यह है कि कोई भी देश तब तक ऊंचा उठ सकता, जब तक कि वह किसान को सरताज नहीं मानेगा। जब वह उसको अपना सरताज मानेगा, वह दे ा ऊपर उठता चला जायेगा। जो भी दे ा किसान को नीचा मानेगा, वह नीचे चलता चला जायेगा। आज आप ही देखिए कि दे ा में कितनी हेरा फेरी हो गयी है, कितनी स्मगलिंग हो रही है, कितनी डिफैक ान हो रही है, यह सब इसी वजह से हैं मैं यह मानता हूं कि सारे हरियाणा में इंडस्ट्रीज होनी चाहिये लेकिन वह कैसे होंगी ? आप हैंडलूम को ही ले लें जिस काम को वीवर या धानक को करना होता है, अगर उसमें से हैंडलूम का जो काम पानीपत में होता है, उसको निकाल दें तो सारे हरियणा में हैंडलूम नाम की कोई इंडस्ट्री नहीं है। चेयरमैन साहब, हरियाणा का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर पंद्रह घर से लेकर पचास घर

तक धानकों या बीवर्ज के न हों। चेयरमैन साहब, सारे हरियाणा के धानक या वीवर्ज रहते हैं लेकिन जहां तक हैंडलूम इंडस्ट्री का सवाल है अगर हम पानीपत को निकाल दें तो हरियाणा में हैंडलूम नाम की कोई इंडस्ट्री नहीं रहती। अगर मैं चमार की इंडस्ट्री लूं जो जूते बनाने का काम करते हैं तो मैं देखता हूं कि जूते बनाने की इंडस्ट्री भी नहीं है। आज सब जगह बाटा के जूतों का बोलबाला है। सब जगह चाहे कस्बा है या भाहर है वही बाटा के जूते बिक रहे हैं। बाटा ने चमार का सारा धंधा छीन लिया है। आज कितने लागे हैं जो चमार के हाथ की बनी हुई जूती पहनते हैं। चेयरमैन साहब, मेरा ख्याल है कि एक परसैंट लोग भी नहीं पहनते तो फिर चमार की इंडस्ट्री कैसे पनपेगी। मैं कहता हूं कि वीवर की इंडस्ट्री होनी चाहिए। चमार की इंडस्ट्री होनी चाहिये। इंडस्ट्री तभी होगी जब सरकार किसान को ऊंचा दर्जा देगी। जब सरकार किसान को ऊंचा दर्जा देगी तो जमीन धन देगी और जब धन ज्यादा आएगा तो इंडस्ट्री बढेगी और रोजी और रोटी का सवाल नहीं रहेगा। किसान मां के बराबर है और किसान ही साधन दे सकता है। जैसे घर में मां होती है उसको पता होता है कि घर में क्या क्या रखा है। किसी को भ्सी एक रूपए की जरूरत होती है तो मां से जाकर रूपया मांगता है। चेयरमैन साहब, रूपया ही क्यों किसी को भी अगर किसी चीज की आव यकता होती है तो वह मां से जाकर मांगता है। इसी तरह से जो साधन होता है वह बजट होता है। अच्छी सरकार मां के बराबर होती है। जिस तरह से मां चीजों का डिस्ट्रीब्यू ान करती है उसी तरह से अच्छी

सरकार अपने बटुए या हम उसको बजट भी कह सकते हैं का बंटवारा करीती है। डैमोक्रेसी में कोई भी सरकार हो वह मां के बराबर होती है। अगर सरकार ठीक तरीके से बजट का बंटवारा कर दे तो सारे दे ा में इंडस्ट्री दी है। चेयरमैन साहब इस दे ा में बडे बडे इकौनोमिस्ट हुए हैं उन्होंने कई रिपोर्टस दी हैं। एक रिपोर्ट आर0के0 हजारी ने दी है। एक रिपोर्ट मौनोपली कमेटी की है और तीसरी रिपोर्ट ने ानल सैम्पल सर्वे कमेटी की है। चेयरमैन साहब, इंडस्ट्री के बारे में बडे बडे इकोनोमिस्ट ने रिपोर्ट दी है। रिपोटर्स से साबित होता है कि हमारा प्लान इंडस्ट्री है। इन रिपोर्टस से साबित होता है कि हिन्दुसतान को इकोनोमी जो है। that has become a tug of war between the rich and the poor. Bureacucratic machinery and the rich men are on the side of the Government. The national income has never been distrubuted equally in the country. Only 10% of the population has got the whole budget of this country. यह जो बजट का बंटवारा है यह ठीक नहीं हुआ। अगर बजट का बंटवारा ठीक हो जाता तो आज यह हाल दे ा का नहीं होता। दे ा की दस प्रति ात जनता के साथ में सारा बजट चला गया। बजट का आधा हिस्सा दे ा के जो अमीर आदमी हैं वे सरकार से मिलकर खा गए। चेयरमैन साहब, आधा हिस्सा टाटा, बाटा और बिरला जैसे लोग खा गए ..... । हमें हिन्दुस्तान में ऐसे लोगों को खत्म करना पडेगा। चेयरमैन साहब, अगर इस दे ा में इंडस्ट्री लानी है। इस दे ा से बेरोजगारी खत्म करनी है तो ऐसे लोगों को खत्म करना पड़ेगा। जब तक सरकार ने इनको पाल रखा है

तब तक दे ा से न गरीबी दूर हो सकती है और न ही बेरोजगारी दूर हो सकती है। न किसान का भला हो सकता है और न ही हरिजन और धानका का भला हो सकता है और न ही इस दे ा में कोई इंडस्ट्री पनपेंगी। चेयरमैन साहब, मैं इस बात को साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि इस दे ा के अंदर इंडस्ट्री का डिवैल्पमैंट तब तक नहीं होगा जब तक ..... की नाकाबंदी न कर ली जाएगी और नाकाबंदी के लिए हमें सारी व्यवस्था बदलनी पडेगी। पिछले 35 साल में यह सरकार इस व्यवस्था को नहीं बदल सकी क्योंकि यह सरकार ऐ ापरस्त हो गई। चेयरमैन साहब, ऐ ापरस्त होने का भी कारण है कि यहां की आबोहवा गर्म है। जिस जगह की आबोहवा गर्म होती है वहां पर लोग कामचोर हो जाते हैं, जाहिल हो जाते हैं और जब आदमी कामचारे हो जाते हैं तो लोग धोखा देते हैं। चालाक आदमी और ज्यादा पढा लिखा आदमी चक्कर देकर निकलता है। चेयरमैन साहब, इस गर्म मुल्क का हमें यह नुकसान रहा है कि इस दे ा के अंदर जो भी देवता बनकर आया उसने हमको मरवा दिया जैसे कि सोमनाथ पर हमले के वक्त हुआ। हम पूरा पाठ में लगे रहे और मोहम्मद गौरी हमको लूटा और मारता रहा। चेयरमैन साहब, इस दे ा के अंदर जो नेता बनकर आया उसने पहले तो अपनी झोली भर ली और फिर लोगों को धोखा दिया। चेयरमैन साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिसको भी हम कुछ मानकर चले उसने हमको धोखा दिया। आज दे ा में कोई किसान को ऊपर उठने नहीं देता। उसको खत्मक करने की कोि ा ा की जाती है। जो बडे बडे

पूंजीपति हैं और मैं तो यह कहता हूं कि यह सरकार भी पूंजीपतियों की है और यह सरकार किसान के नौजवान बच्चों को ऊपर उठने नहीं देती उनको बीच में ही रोक लेती है क्योंकि सरकार जानती है कि इस दे ा में किसान का बच्चा ही अच्छी सूझबूझ से काम कर सकता है। चेयरमैन साहब, अभी मद्रास के अंदर वहां के चीफ मिनिस्टर ने एलान किया कि एम0एल0एज0 की तनख्वाह बंद कर दूंगा। मैंने कह कि अगर तनख्वाह बंद कर दी तो सरकार कैसे चलेगी। चेयरमैन साहब, अगर दे ा में इंडस्ट्री को बढाना है तो हमें व्यवस्था को बदलना पडेगा और दूसरे सरकार में ऐ ापस्त आदमी आ गए हैं उनको निकालना पडेगा। जब तक इस ढांचे में तबदीली नहीं की जाएगी। तब तक दे ा की उन्नति नहीं हो पाएगी।

चेयरमैन साहब, सरदार लछमन सिंह इस वक्त करोडों की आसामी हैं। जब हमारी मिनिस्ट्री बनने की बात थी तो ये हमारे साथ परवानु में थे। (व्यवधान व भाोर) श्री अमर सिंह जी भी कुछ बोल रहे हैं, इनके साथ तो मेरे काफी फैमिली रिले ान्ज हैं। उस वक्त हमारी बात बिगड गई नहीं तो हम इंडस्ट्री को हरियाणा में चार चांद लगा देते। (भाोर) मेरा कहने का मतलब यह है कि हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री का होना बहुत जरूरी है। और मैं तो हिन्दुस्तान में घूम चुका हूं, दूसरी स्टेटस की इंडस्ट्रीज को भी मैंने देखा है। केरल में मैं गया वहा ंपर सुपारी और केले की बडी भारी खेती है, उससे वे लोग काफी लाभ उठा रहे हैं, इसी तरह

से हमारे हरियाणा में भी इन बातों की कमी नहीं है। अगर इस तरफ सरकार ध्यान दे तो हमारे हरियाणा की इंडस्ट्रीज सारे हिन्दुस्तान से आगे निकल सकती है। यहां पर दूध और दही का घर है, सब्जी का घर है, एग्रीकल्चर में काफी उन्नति हुई है लेकिन जब मैं बम्बई तो मैंने वहां पर देखा कि हमारे हरियाणा की सारी भैंसे वहां पर बांध रखी हैं और लोगोंने वहां पर बडी बडी डेयरी खोल रखी हैं। मुझे देखकर बडा ही दुःख हुआ कि अगर हम अच्छी अच्छी भैंसे हरियाणा से बाहर भेज देंगे तो हमारे हरियाणा का कल्याण कैसे होगा, हरियाणा से उन्नति कैसे होगी ? इसलिये इन बातों के ऊपर सरकार को रोक लगानी चाहिए।

उद्योग मंत्री (श्री लछमन सिंह): हुड्डा साहब, रोहतक की बात तो आप करें।

श्री हरि चन्द हुड्डा: लछमन सिंह जी की बात ठीक है कि इंडस्ट्रीज को अगर रोहतक से भुरू किया जाये तो यह काफी पनप सकती है क्योंकि रोहतक में ऐजुके ान बहुत है, जिसका इंडस्ट्रीज के साथ काफी संबंध होता है। चेयरमैन साहब, ये हमारे साथी हैं, सुरजेवाला साहब बैठे नहीं, वे भी मेरे मित्र हैं। भजन लाल जी भी नहीं बैठे, उनको मैं बताता वैसे मेरे उनसे भी अच्छे संबंध है, बिगडे नहीं पता नहीं उन्होंन रोहतक को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर रखा है पता नहीं रोहतक को ये अपनी सौंकन समझते हैं। (ाोर एवं हंसी) सरकार वहां पर इंडस्ट्रीज लगाने से डरती है। पता नहीं कि क्या बात है ? चेयरमैन साहब आपके द्वारा इनसे

रिक्वैस्ट है कि खुदा के लिये कुछ तो रोहतक में करो। चेयरमैन साहब, रोहतक ऐजुके ान के लिहाज से भारत में सबसे आगे है। केरल में भी 80 परसैंट ऐजुके ान है तभी वहां पर इंडस्ट्रीज पनप रही हैं और इंडस्ट्रीज लगाने के लिीए ऐजुके ान का होना बडा जरूरी है। मेरा तो यह विचार है कि सरकार रोहतक से ही इंडस्ट्रीज का श्री गणे ा करें और सारे हरियाणा में इसको फैला दें तभी इंडस्ट्रीज पनप सकती है। जो पहले ऊपर उठे हुए हैं उनको और न उठाओ कि वे आपके सिरों तक चढ जाएं जो नीचे हैं, उनको उठाओ ताकि हरियाणा तरक्की करें।

चेयरमैन साहब, आजकल हालात बहुत बिगडते जा रहे हैं। बगैर इंडस्ट्रीज के काम नहीं चलेगा। यह ड्रामा ऐसा है, कहीं 1985 से पहले पहले खत्म न हो जाए तो फिर हमें रोना पडे। क्योंकि इंडस्ट्रीज न होने की वजह से बेरोजगारी बढेगी और बेरोजगारी बढने से रोटी नहीं मिलेगी।

चेयरमैन साहब, साऊथ में रैवोल्यू ान है और असाम, पंजाब, क मीर में रिबेलियन हैं और आज इन बडे बडे नेताओं की अक्ल को पता नहीं क्या हो गया है, वे इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं मैं यह कहता हूं कि सरकार रैवोल्यू ान और रिबेलियन को रोके और इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान दें और जब तक किसासन को सरकार डयू पलेस नहीं देगी तब तक यह इंडस्ट्रीज पनपने वाली नहीं है क्योंकि किसान दे ा की रीढ की हड्डी है।

श्री लछमन सिंहः मुल्क में कोई रिबेलियन वाली बात नहीं है, इसलिये इस लफ्ज को एक्सपंज करवा दिया जाये। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री हरि चन्द हुड्डाः आसाम में क्या, पंजाब में क्या, क मीर में क्या है ? पंजाब में कोई जात पात का मामला नहीं हैं यही झगडें हैं। चेयरमैन साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी आवाज इस सरकार तक पहुंचा दें कि बगैर इंडस्ट्रीज के बात नहीं बनेगी। मेरा कहना यह है कि इस बजट में कुछ नहीं रखा जब तक कि आप इंडस्ट्रीज को बढावा नहीं देतें अगर किसान की हल की अनी में इस बजट को जोतें तो क्या इस हरियाणा में खु ाहाली आ सकती है ? जब तक कि हम किसान को लैवी के जरिये सबसिडी के जरिये कुछ नहीं देते, सारी सबसिडी तो हांसी और भिवानी के सेठ खा गये। जब तक हम किसानों की खुलकर मदद नहीं करते तब तक हमारी इंडस्ट्रीज भी नहीं पनप सकती। इसलिये मेरा कहना है कि आप इंडस्ट्रीज को उभारो। केवल कागजों में ही कुछ करने से किसान का पेट नहीं भरेगा। प्रोपेगंडा से काम नहीं चलेगा। इसी कारण से तो आसाम, पंजाब और का मीर में रिबेलियन है और कोई दूसरा जात पात का कोई झगडा नहीं है। यहां पर झगडा सिर्फ रोजी रोटी का है। आपको एड्रैस इस लिहाज से बिल्कुल खोखला है। मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि इंडस्ट्रीज के बारे में सरकार अपना रूझान बदले और थोडी से व्यवस्था भी बदले। पुराने जमाने से जो हमारे

हिन्दुस्तान में इंडस्ट्रीज आ रही है, उसको फिर से बहाल करो। दोबारा बहाल करना इसलिये जरूरी है क्योंकि इस बजट को एक तरह से खराब किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसा काम कर दो जिससे लोग सुख से बसें। आपका बजट खाने वाले 50 प्रति ात लोग हैं यह तो पेट के लिये बजट है। मैं चाहता हूं कि उनको सजा दो, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। चेयरमैन साहब, मैं गलत बात नहीं कहता। अगर मैं यह कहूं कि यह लोकतन्त्र नहीं बल्कि लूट तंत्र है तो यह बात भी गलत नहीं है। चेयरमैन साहब अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर सारे हरियाणा में इंडस्ट्री लग जाए तो सारे हरियाणा का भला होगा।

श्री सभापतिः इंडस्ट्रियलिस्ट के लिये जो नावाजिव लफ्ज इस्तेमाल किया गया था वह रिकार्ड न किया जाये।

मास्टर ि ाव प्रसाद (अम्बाला भाहर): सभापति महोदय, श्री राम दास धमीजा ने अम्बाला तहसील को औद्योगिक दृश्टि से पिछडा घोशित करने के लिए जो प्रस्ताव दिया है, मैं भी उसके समर्थन में कुछ विचार व्यक्त करने के लिये खडा हुआ हूं।

वाक आउट

श्री भागी रामः चेयरमैन साहब, मुझे बोलने का समय नहीं दिया गया है। इसलिये मैं प्रोटैंस्ट के तौर पर वाक आउट करता हूं।

(इस समय श्री भागी राम सदन से वाक आउट कर गये ।)

गैर सरकार संकल्प (पुनरारम्भ)

मास्टर ि ाव प्रसादः चेयरमैन साहब, इसमें कोई भाक नहीं कि अम्बाला हिन्दुस्तान के नक ो में बहुत अहमियत रखता था। यहां पर हिन्दुस्तान की बहुत बडी छावनी है और उसके अलावा यह रेलवे का जंक ान भी है लेकिन इतना होते हुए भी इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। हिन्दुस्तान की तकसीम से पहले भी जो सरकार इस दे ा में थी उसने भी अम्बाला जिले की और ध्यान नहीं दिया। 15 अगस्त 1947 को जब दे ा आजाद हुआ और इस दे ा की हकूमत अपने ही लोगों के हाथ में आई तो उस समय यह सोचा गया था कि भाायद अब अम्बाला की किस्मत जाग जाये। अम्बाला का भी कुछ उन्नति की दृश्टि से सरकार को ध्यान आ जाए लेकिन 1947 से लेकर 1966 तक 19 साल के अरसे में अम्बाला की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया इसे इग्नोर किया गया। उसके मुकाबले में पंजाब के अंदर राजपुरा, सरहंद, गोबिंदगढ, लुधियाना, फगवाडा, जालंधर, अमृतसर यानी आप जी0टी0 रोड के साथ चले जाएं वहां पर किसी टाईम जो गांव थे वे बहुत बडे भाहर की भाक्ल में बन गये उस समय की सरकार ने अम्बाला की ओर ध्यान नहीं दिया। यह तो सबको पता है कि दे ा की तकसीम के बाद दे ा की सरकार एक ही पार्टी के हाथ में रही है। केवल बीच में अढाई वर्श हमारी जनता पार्टी की सरकार रही है। चेयरमैन साहब, एक नवम्बर, 1966 को

पंजाब की भी तकसीम हो गई और हरियाणा प्रांत हिन्दुस्तान के नक ो में वजूद में आया। उस समय यह ख्याल बना कि अब अम्बाला जो किसी समय सारे पंजाब में कमि ानरी था अब छोटा सा इलाका रह गया है। भाायद अब अम्बाला का नाम तरक्की की लिस्ट में कहीं न कहीं जरूर आ जायेगा। सभापति महोदय, जब हरियाणा बना तो केवल एक ही ऐसा भाहर था सारे हरियाणा में जिसकी आबादी एक लाख से ऊपर हो। एक ही तो ऐसा भाहर था जिसके साि भाहर का नाम जुडा हुआ है। अम्बाला भाहर के साथ अम्बाला छावनी भी है। अब तक जिन भाहरों ने तरक्की की है उनमें अम्बाला का नाम सबसे बाद में आता है। हरियाणा के अंदर जिस समय भगवत दयाल जी चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार थी। अम्बाला भाहर की म्यूनिसिपल कमेटी पर उस समय विपक्ष यानी जनसंघ का कब्जा था। एक बात कह कर वहां की म्यूनिसिपल कमेटी को तोडा गया कि हिन्दुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा गंदी कोई म्यूनिसिपल कमेटी है तो वह अम्बाला की है। उस कमेटी को 11 या 12 जनवरी 1967 में तोडा गया था और आज तक उसके चुनाव नहीं हुए। उस समय कांग्रेस की हकूमत ने ही वहां की म्यूनिसिपल कमेटी के लिये ये भाब्द इस्तेमाल किये थे लेकिन फिर भी तब से अब तक अम्बाला भाहर की ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया। अगर चण्डीगढ या हिमाचल से हरियाणा में प्रवे ा किया जाए तो अम्बाला हरियाणा का दरवाजा है। चाहिए तो यह कि दरवाजे से ही पता लगाना चाहिए कि हरियाणा कि कितनी डिवैल्पमैंट हुई है।

1966 से लेकर अब तक सरकार को अम्बाला की तरफ ध्यान रखना चाहिए था लेकिन रखा नहीं। वहां के लोगों ने अपने प्रयास से कुछेक इंडस्ट्रीज खोली हैं। जैसे अम्बाला छावन में साइंस का सामान बनता है जो कि सारे दे ा में ही नहीं बल्कि विदे ाों में भी भेजा जाता है। वहां पर दरियों का भी बहुत बडा सैंटर है। वहां पर कई फैक्ट्रीज हैं जो बिना गवर्नमैंट की सहायता से किसी न किसी तरह चल रही हैं। इसलिये अम्बाला को औद्योगिक दृश्टि से पिछडा हुआ जरूर घोशित किया जाना चाहिये। मैं तो सारे अम्बाला जिले को ही बैकवर्ड घोशित करवाने के हक में हूं जैसे मैंने गवर्नर ऐड्रैस पर बोलते हुए भी कहा था। यह बात ठीक है कि खेती को `उत्तम माना गया है। इसमें दो राय नहीं हैं। मैं तो यह चाहता हूं कि कालका, नारायणगढ, छछरौली से लेकर सिरसा तक जहां हरियाणा का बार्डर राजस्थान और यू0पी0 के साथ लगता है। वहां तक का सारा इलाका इंडस्ट्रियली बैकवर्ड होना चाहिए। लेकिन आजकल यह हो रहा है कि अगर मुख्यमंत्री भिवानी का बन गया तो सारे हरियाणा की धन दौलत वह भिवानी में ले जाएगा। अगर मुख्यमंत्री हिसार का बन गया तो हिसार में ले जाएगा। लेकिन अम्बाला की किस्मत में ऐसा नहीं लिखा। हरियाणा में सब से ज्यादा रैवेन्यू अम्बाला देता है। लेकिन वह सारा धन अम्बाला में खर्च नहीं होता। बारि ा का जितना भी पानी अम्बाला में इकट्ठा होता है उसको नहरों के जरिये आगे भेज दिया जाता है। और अम्बाला एक बूंद पानी भी इस्तेमाल नहीं करता। लोग आका ा की ओर देखते रहते हैं कि बारि ा हो लेकिन जब

बारि ा होती है तो उसका पानी आगे बहा दिया जाात है। इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि खेती की दृश्टि से भी अम्बाला जिले का ध्यान रखा जाए। उत्तम खेती से ही हरियाणा के अंदरव अधिक पैदावार होगी और अधिक पैदावार में लगा हुआ है, उस मिल में अम्बाला के सारे एरिया का गन्ना जाता है। यानी एक इंडस्ट्री की वजह से सारे इलाके के लोगों को राहत मिलती है। उस इलाके में मूंगफल पैदा होती है, इसलिए वहां पर घी का मिल लगाना बहुत जरूरी है। जहां पर गेहूं की पैदावार होती है, वहां पर मैदे का मिल लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए चेयरमैन साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि बडी इंडस्ट्रीज लगेगीं तो उसके साथ साथ छोटी इंडस्ट्रीज भी लगेगीं। बरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री महोदय ने भी यह कहा है कि हरियाणा प्रांत में प्रति वर्श लगभग एक लाख लडके लडकियां पढ लिख कर तैयार हो जाते हैं लेकिन उन सबको रोजगार देना बहुत मु कल है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सेठ राम धमीजा ने जो अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर करने के बारे में रैजौल्यू ान पे ा किया है उस पर श्री भाग मल ने यह अमैंडमैंट दी हैं कि उसके साथ यह भी जोड दिया जाए कि अम्बाला तहसील के साथ साथ सारे अम्बाला जिले की इंडस्ट्रीयल बैकवर्ड डिक्लेयर किया जाए। इस तहर करने से बेरोजगाार लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे प्रांत में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी तथा बेरोजगारी की समस्या भी काफी हल हो जाएगी। चेयरमैन साहब, अम्बाला भाहर मेरा हल्का है वहां पर मेरे ख्याल में

लगभग सभी मिनिस्टर जाते हैं। जो भी मिनिस्टिर महोदय, जाते हैं उनको बस स्टैंड के पास एक पार्क बना हुआ है। वहा ंपर ले जाया जाता है। अम्बाला भाहर के अंदर नहीं ले जाया जाता। इसलिए मिनिस्टिर महोदय अम्बाला भाहर की अन्दरूनी हालत को नहीं देख पाते हैं। भाहर के अंदर सफाई न होने के कारण आफिसर लोग भी मिनिस्टर्ज को भाहर के अंदरूनी एरिया में नहीं ले जाते। चेयरमैन साहब, जनता पार्टी के समय में जब चौधरी देवी लाल जी चीफ मिनिस्टर थे तो वे अम्बाला भाहर में गए थे। उस समय मैंने उनके सामने अम्बाला भाहर की हालत बनाई थी। उस समय सरदार लछमन सिंह जैसे मिनिस्टरों ने मेरी बात को कैंडैम किया था। इन्होंने पब्लिक मीटिंग में मेरी बात की मुखालफित की थी। इन्होंने स्टेज पर खडे हो कर यह कहा था कि आप अम्बाला की खराब हालत के बारे में चण्डीगढ में आकर बातें करे। चेयरमैन साहब चौधरी देवी लाल जी अम्बाला भाहर की हालत सुधारने के लिए उस 10 लाख रूपये देकर आना चाहते थे, यदि ये मेरी मुखालफिर नहीं करते। अम्बाला भाहर की हालत इनसे छिपी हुई नहीं है। चेयरमैन साहब, अम्बाला जिले से सरकार में चार मिनिस्टर हैं लेकिन उसके बावजूद भी वहां की बहुत दुर्द ाा है। वहां के चार मिनिस्टिर होते होते हुए उनके दिल में अम्बाला की तकलीफों के बारे में कोई दर्द नहीं है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): चार मिनिस्टरों की बजाये पांच हो जाएं तो क्या वहां का सारा काम हो जाएगा ? (ाोर एवं विघ्न)

मास्टर ि ाव प्रसाद: ये मिनिस्टर कहां हैं ? यदि ऊपर से कोई झण्डी हिलती है तो काम करते हैं वरना कुछ नहीं करते। (हंसी) वहां का एक ही मंत्री काफी था यदि वह काम करने वाला होता। सुरजेवाला साहब यदि आप जैसा मंत्री अम्बाला जिले का मिला हुआ होता तो हमारे सारे काम हो जाते। जब आप वहां पर ग्रीवैंसिज कमेटी की मीटिंग में जाते हैं तो वहां का थोडा बहुत भला हो जाता है। चेयरमैन साहब, अम्बाला जिले के चार मंत्री होते हुए जितनी वहां की तरक्की होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अम्बाला भाहर की इतनी बुरी हालत है यदि बारि ा की दो बूंद पड जाएं तो वहां सडकों पर चुलना मु ि कल हो जाता और जो साइकिल, मोटर साइकिल, और कारों वाले हैं उनको यदि कहीं जाना पडे तो उन सडकों को छोड कर चक्कर काट कर जाना पडता है। अम्बाला भाहर के अंदर सडकों की बहुत बुरी द ाा हैं अम्बाला भाहर की म्यूनिसिपल कमेटी की बहुत बुरी हालत है। वह एक भी सडक को ठीक नहीं करवा सकती है। चेयरमैन साहब, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे हरिजन भाई केवल गांवों में ही नहीं रहते भाहरों में भी रहते हैं। अम्बाला भाहर में हरिजन भाईयों की बस्तियां देखी जाएं तो उनकी बहुत बुरी

हालत मिलेगी। अगर बारि ा में चार बूंद पानी की पड जाती है तो उन बस्तियों की गलियों से गुजरना मु कल हो जाता है। जब चौधरी भजन लाल जनता पार्टी के भाासन काल में मुख्यमंत्री थी उस समय ये अम्बाला गए थे। उस समय मैंने जान बूड कर इनका तीन जगह पर प्रोग्राम रखा था एक जगह पर सुबह प्रोग्राम रखा था, एक जगह पर इन्होंने जनता पार्टी के वर्करज के साथ मीटिंग की थी और एक जगह पब्लिक मीटिंग की थी। इस तरह से मैंने इनका प्रोग्राम सुबह एक जगह, दोपहर दूसरी जगह और भााम को तीसरी जगह पर रखा था। लेकिन फिर भी ये अम्बाला भाहर की सही हालत को नहीं देख पाये। जब मैं इनके साथ कार में बैठा था तो इन्होंनें उस समय मुझे कहा कि अम्बाला भाहर की की बहुत बुरी हालत है। फिर मैंनें इनसे कहा था कि मैं आपको भाहर के अच्छे अच्छे रास्तों से यहां लेकर आया हूं। यदि मैं आपको दूसरे रास्तों से लाता तो आपको अम्बाला भाहर की हालत देख कर बहुत हैरानी होती। उस समय चौधरी भजन लाल जी ने अम्बाला भाहर की दुर्द ाा देख कर सड़कों की मरम्मत के लिए पांच लाख रूपये दिये थे। चेयरमैन साहब, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि उन सडकों की मुरम्मत पांच लाख रूपये में नहीं हो सकती उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है। अम्बाला जिले को डिवैल्प करना बहुत ही जरूरी है। ज्वायंट पंजाब में अम्बाला भाहर की एक लाख की आबादी थी लेनि इस समय वहां की आबादी बहुत बढ गई है। हरियाणा प्रान्त के अनेकों भाहर ऐसे है जिनकी आबादी एक लाख से भी ज्यादा है। मैं यह नहीं कहता कि गांवों की

उन्नति नहीं होनी चाहिए जरूर होनी चाहिए। कल का गांव कस्बा बनना चाहिए कल का कस्ब आज भाहर बनना चहिए। चेयरमैन साहब, गांव के लोग नौकरी के लिए या अपने दूसरेम काम धंधों के लिए भाहरों में आकर बसते हैं, इसलिए हरियाणा ऐसा सूबा है जहां पर भाहरों और गांवों को अलग नहीं किया जा सकता। हम तो राजनैतिक आदमी हैं हमें भाहरी और देहाती लोगों से वोट लेने पडते हैं उनमें हरिजन, व्यापारी, दुकानदार और सर्विस मैन सभी तरह के लोग होते हैं इसलिए हम यह चाते हैं कि देहातों के साथ साथ भाहरों की भी तरक्की होनी चाहिए। मैं यह चाहता हूं कि हरियाणा में खेती बाडी बढनी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज भी बढनी चाहिए। सेठ रामदास धमीजा ने अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर करने के बारे में जो रैजोल्यू ान पे ा किया है उसमें श्री भागमल ने यह अमैंडमैंट दी है कि अम्बाला तहसील के साथ साथ सारे अम्बाला जिले को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर किया जाए इस बारे मैं मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तो कटटे के साथ कटटा बांधने वाली बात है। यदि इस रैजोल्यू ान के साथ सारे हरियाणा प्रांत को जोड दिया जाएगा तो कोई भी काम नहीं बनेगा। न सरकार के पास इतना पैसा होगा और न सारा हरियाणा इंडीस्ट्रीयली बैकर्ड डिक्लेयरे किया जाएगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले आप अम्बाला तहसील को ही इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर करवायें। इसके बाद दूसरे जिलो के बारे में कहें। यदि अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो हरियाणा में

इंस्ट्रीज पनपेंगी और बेरोजगेारों को रोजगार मिलेगा। सरकारी बैंचिज पर बैठे माननीय सदस्यों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अपोजी ान के बैंचिज पर बैठे हैं इसलिए वे हरियाणा की उन्नति के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। यहां पर जो भीसदस्य बन कर आये हैं उनका हरियाणा प्रदे ा पर बराकर हिस्सा है। इसलिए हरियाणा प्रांत में जो उन्नति का काम होगा उसके लिए हम सरकार को साथ देंगे। चेयरमैन साहब, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अम्बाला भाहर और अम्बाला छावनी के साथ एक इंडस्ट्रीयल एरिया बनाया गया है। लेकिन जिस जगह पर इंडस्ट्रीयल एरिया बनाया गया है वह सडक से बहुत नीची जगह है। वह जगह मौके पर जाकर नहीं देखी गई कि वह इंडस्ट्रीज के लिए उचित भी है या नहीं। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां पर इंडस्ट्रीयल एरिया बनाया गया है वहां पर पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अम्बाला पानी की कमी के कारण सारे हिन्दुस्तान में बदनाम हैं अगर अम्बाला में पानी की दिक्कत न होती तो सरकार को इंडस्ट्रीज लगाने के लिए इतना जोर नहीं लगाना पडता और अपने आप ही वहां पर इंडस्ट्रीज पनप जाती और अम्बाला पंजाब और हरियाणा की राजधानी होती। चेयरमैन साहब, आज जहां पर कुर्सी पर बैठे हैं आज आप अम्बाला में इस कुर्सी पर बैठे होते। वहां पर सरकार को इतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है लोग अपने आप ही इंडस्ट्रीज लगा लेते। लेकिन अब इंडस्ट्रीज लगाने वाले यह सोचते हैं कि वहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि हम वहां पर इंडस्ट्री लगांएगे तो पीने

के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, फिर इंडस्ट्रीज का काम कैसे चल सकता है। चेयरमैन साहब, अम्बाला भाहर में पानी की इतनी समस्या है कि नलकों पर सुबह चार बजे पानी के लिए लोगौं की लाईन लग जाती हैं। चेयरमैन साहब इस सरकार के मिनिस्टरों की फौज अम्बाला भाहर की तरफ यदि जाने अनजाने में कभी चक्कर लगाये तो वे एक बार उन नलकों पर लोगों की हालत को देखें तो पता चलेगा कि वहां पर पीने के पानी की कितनी समस्या है। लोग वहां पर पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि 10 साल पहले अम्बाला भाहर में एक सीवरेज की स्कीम चालू की थी उसके लिए वहां की म्यूनिसिपल कमेटी ने लोन की भाक्ल में लाखो रूपये ले लिए लेकिन अभी तक उस स्कीम पर काम चालू नहीं हुआ है। आज वहां की म्यूनिसिपल कमेटी को उस लोन का इन्ट्रैस्ट देना मु कल हो रहा है। जिस समय वह स्कीम चालू की थी उसी समय से बंद पडी है वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। चेयरमैन साहब, 30 अक्तूबर 1979 की बात है उस समय जनता पार्टी के भाासन काल में चौधरी भजन लाल जी मुख्य मंत्री थी। इन्होंने अम्बाला भाहर में पीने के पानी की योजना चालू की थी वह स्कीम इतनी धीमी गति से बन रही है कि वह काफी समय तक भी पूरी नहीं हो सकती। एक सवालस के जवाब में बताया गया है कि वह स्कीम चार साल में पूरी हो जाएगी लेकिन मुझे यह नजर आता है कि 10 साल में भी पूरी होने वाली नहीं है।

12.00 बजे।

इसलिए मैं चाहूंगा कि हरियाणा के नक ो पर अम्बाला जिले का महत्त्व दिया जाये। जब भी चण्डीगढ से या हिमाचल से कोई व्यक्ति हरियाणा में प्रवे ा करता है तो वह सबसे पहले अम्बाला जिले के अंदर दाखिल होता है। मैं चाहता हूं कि सरकार अम्बाला जिले को इंडस्ट्रीज के मामले में अधिक से अधिक डिवैल्प करे। अम्बाला जिले का जो हाईव0 है उसके दोनों तरफ इंडस्ट्रीज लगनी चाहिये। उसके बाद पिपली, करनाल, और देहली तक ले जाइए ताकि बाहर से आने वालों को पता लग सके कि अम्बाला जिला भी इंडस्ट्रीज में डिवैल्प कर रहा है, हरियाणा इंडस्ट्रीज में डिवैल्प कर रहा है। धमीजा जी ने जो प्रस्ताव अम्बाला तहसील का रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अम्बाला जिले के जो कस्बे हैं जैसे छछरौली, कालका, सढौरा तथा नारायणगढ इनमें भी इंडस्ट्री को बढावा दिया जायें यमुनानगर के अंदर तो थोडी बहुत इंडस्ट्रीज हैं लेकिन वहां पर इंडस्ट्रीज को और भी बढाया जा सकता है। यहां पर अम्बाला जिले के चार मिनिस्टर बैठे हैं। इन्होंने अभी तक अम्बाला जिले को इंडस्ट्रीज के लिहाज से बैकवर्ड डिक्लेयर नहीं करवाया है। भाायद इनका ध्यान न गया हो। लेकिन अब इनको इस ओर वि ोश ध्यान देकर इसे इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिकलेयर कराने की कोि ा ा करनी चाहिए। चेयरमैन साहब यहां पर कहा जाता है कि रोहतक ि ाक्षा का सैंटर है। मैं यह बात ध्यान में

लाना चाहूंगा कि ि ाक्षा के मामले में अम्बाला जिला भी कम नहीं है। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। यदि ध्यान दिया जाये तो काफी फिजूल खर्चों को बचाया जा सकता है। वहां पर एक गवर्नमैंट हजायर सैकण्डरी गर्ल्ज स्कूल है। उसके अंदर सिर्फ 200 लडकियां पढती है। जबकि स्टाफ 40 से भी ज्याद है। उस स्कूल के कमरे खाली पडे हैं। छत्तें खराब हो रही हैं। अम्बाला के अंदर कोई भी गवर्नमैंट कालेज नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस गवर्नमैंट हायर सैकेन्डरी स्कूल को गवर्नमैंअ गर्न्ज कालेज बना दिया जाये। आपने भी सभापति महोदय अम्बाला के अंदर बलदेव नगर को देखा होगा। वहां पर एक गवर्नमैंट को एजुके ान हाई स्कूल है। उस स्कूल के अंदर 1800 से भी ज्यादा बच्चे पढते हैं बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। गर्मियों में बच्चे दरखतों के नीचे बैठते हैं और सर्दियों में धूप में बैठते हैं। उस स्कूल का बरामदा भी बहुत छोटा है। उसके अंदर भी बच्चे बैठ नहीं सकते। वैसे भी वह स्कूल सडक से जुडा हुआ हैं पिछले दिनों जब एक लडका सडक क्रोस कर रहा था तो वह किसी वाहन के नीचे आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस बारे में मेरा सुझाव है कि उसको एजुके ान हाई स्कूल को गर्ल्ज हाई स्कूल बना दिया जाये। उस स्कूल के अंदर और बिल्डिंग भी बनाई जा सकती है जिससे समस्या का हल हो सकता है। अम्बाला जिले में काफी कालेजे हैं। चेयरमैन साहब, वहां पर एक मैडीकल कालेज भी बनाये जाने की जरूरत है। जिस प्रकार से रोहतक के अंदर मैडीकल कालेज हैं उसी प्रकार से यदि अम्बाला जिले में भी

मैडीकल कालेज बना दिया जाता है तो अम्बाला के बच्चों को भी मैडीकल कालेज में एडमि ान लेने में सुविधा हो सकती है। मैं तो यह भी कहूंगा कि जो अमैंडमैंट भागमल जी ने रखी है, उसको भी इसमें भाामिल कर लिया जाये। अन्त में मैं सरकार से पुरजोर प्रार्थना करता हूं कि अम्बाला जिले को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया जाये। सरकार में बैठने वाले भाईयों से भी मेरी प्रार्थना है कि वे इस प्रस्ताव का समर्थन करें।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। चेयरमैन साहब सेठ रामदास धमीजा की तरफ से जो प्रस्ताव आया है, उसको हम सभी समर्थन करते हैं कि इस प्रस्ताव को पास किया जाना चाहिए।

श्री सभापतिः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री अमीर चंद मक्कड़ (हांसी): चेयरमैन साहब, सेठ रामदास धमीजा ही की तरफ से जो प्रस्ताव अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीज के लिहाज से बैकवर्ड घोशित करने के लिए आया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। चेयरमैन साहब, मेरा हल्का हांसी है। हांसी इंडस्ट्रीज के लिहाज से काफी पिछडा हुआ है। आप सभी को मालूम होगा कि हांसी भाहर बहुत पुराना भाहर है। हांसी कपास और अनाज के मामले में भारत के आजाद होने से पहले एक मानी हुई तहसील थी लेकिन आज 35 साल हो गए हैं। उसको डिवैल्पमैंट के लिहाज से छुआ तक नहीं गया है जिस

कारण इंडस्ट्रीज की भी हालत खराब हो गई है। पहले हांसी के अंदर कपास के 18 कारखाने थें यहां पर पे ाावर तक की कपास आती थी लेकिन आजादी क बाद इन कारखानों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया जिसके कारण मु कल से इन 18 कारखानों में से 4–5 कारखाने ही कपास के बचे हैं अब हांसी के अंदर एक स्पीनिंग मिल हैं अब भी हांसी कपास का एक सैंटर है। वहां पर अनाज भी बहुत पैदा होता है। यदि सरकार वहां पर कोई फ्लौर मिल लगा दे तो उससे काफी लाभ हो सकता है। इतना ही नहीं बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल सकता है।

जहां तक सूखे और औलों की बात है। हांसी के अंदर भी सूखा पडा है और ओले भी पडे हैं। इसलिए सरकार को अम्बाला के साथ साथ हांसी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सेम की वजह से वहां की जमीन खराब होती जा रही है। हांसी तहसील के अंदर किसानों का मुख्य काम खेती करना है। अब जमीन भी उतनी नहीं रही जिससे वे अपना पेट भर सकें। यदि वे जमीन को अपने परिवार के हिस्सों में बांटने लग जायें तो किसी को भी एक एक किल्ले से ज्यादा जमीन हिस्से में नहीं आएगी। इसलिए सरकारको मेरा सुझाव है कि हांसी के अंदर भी अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज लगाई जायें। यदि इंडस्ट्रीज लग जाती हैं तो जमींदारों के लडके उनमें काम करने लग जाएंगे और जमीन का बंटवारा होने से बच जाएगा।

वहां पर किसी भी स्कूल की बिल्डिंग ठीक नहीं है। वह सारे हरियाणा में एक अच्छा भाहर है उसकी तरफ वि ोश ध्यान दिया जाना चाहिए। न वहां पर कोई पार्क है और न ही कोई इंडस्ट्रीज लगी हुई है। चेयरमैन साहब, यदि वहां पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लग जाये तो उससे सारे संसार में उसका नाम होगा क्योंकि हांसी पहले भी काफी म ाहूर तहसील है। जापान की मिसाल हमारे सामने है। जापान में छोटी इंडस्ओी घर घर में चल रही हैं। और आज यह दे ा दुनिया के नक्ो पर है। यही कारण है कि आर्थिक दृश्टि से यह दे ा सबसे ज्यादा मजबूत है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जहां बडी बडी इंडस्ट्रीज को एड दी जाती है वहां छोटी इंडस्ट्रीज को भी प्रोत्साहन दिया जाए। मेरे कुछ साथी सदन में बोलते हुए कह रहे थे कि जूती का काम चमार को दिया जाये। कपडे का काम हाथ्स से कपडा बनाने वालों को दिया जाये ताकि ये लोग अपने पांवों पर खडे हो सके। मैं भी इनकी बात का समर्थन करता हूं पानीपत में खड्डिया चलती है। यह कारण है कि पानीपत दस्तकारी के लिहाज से आगे है, सब भाहरों से आगे बढा हुआ भाहर है। इसी तरह से हांसी में भी एक स्पिनिंग मिल लगनी चाहिए और कपडा बुनने की खड्डिया लगाई जानी चाहिए क्योंकि वहां पर कपास की पैदावार अधिक होने के कारण यह काम बहुत अच्छी तरह से चल सकता है जिससे हरियाणा सरकार को भी टैक्स के रूप में आमदनी हो सकती है और काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है। इंडस्ट्रीज को तभी फायदा हो सकता है अगर कच्चा माल काफी मात्रा में

मिल सके और यहां पर कच्चा माल मिलता है इसलिए हांसी में यह काम अच्छी तरह से कामकाज हो सकता है। यहां हाउस में फ्लोर मिल और कपडे की मिल लगाने की बात आई थी। हांसी में भी ये मिले खोली जा सकती हैं। इस ढंग सें हांसी इंडस्ट्रीज का एक सैंटर बन सकता है। जिस प्रकार जींद में फ्लोर मिल लगा है उसी तरह का मिल यहां भी लग सकता है जिसके कारण काफी लोग व्यापार का काम कर सकते हैं।

जहां तक एजुके ान का ताल्लुक है, हांसी के अंदर एक कालेज है जो हांसी भाहर से बाहर पडता है। आज ि ाक्षा बहुत जरूरी चीज है और बच्चाों को ि ाक्षा देना निहायत जरूरी है जिसके लिए हांसी में गवर्नमैंट स्कूल और कालेज होने जरूरी हैं ताकि बच्चे ि ाक्षा ग्राहण करके इंडस्ट्रीज चलाने का काम अच्छी तरह से कर सकें। आज हांसी के आई0टी0आई0 पास लडकें बिना रोजगाचर से बेकार बैठे हैं। आई0टी0आई0 की ट्रेनिंग की साथ साथ अगर ये लडके अच्छे पढे लिखें हों गे तो ये अच्छा काम कर सकते हैं। अन्त मैं मेरी सरकार से यही गुजारि ा है कि जो प्रस्ताव धमीजा साहब ने पे ा किया है, इसके साथ हांसी का नाम भी जोड दें ताकि यहां पर भी इंडस्ट्रीज की डिवैल्पमैंट हो सके। इतना कह कर मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने बोलने के लिए टाईम दिया है।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): स्पीकर साहब, जो प्रस्ताव श्री धमीजा साहब ने सदन में रखा है, उसको स्वीकार करना

चाहिए और अगर सरकार के दिल में धमीजा साहब की थोड़ी बहुत इज्जत होती हो पहले ही स्वीकार करके मुख्य मंत्री जी इसकी स्वीकृति की घोशणा कर देते, लेकिन प्रस्ताव ही ऐसा है जिसको मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर सकते। आजकल मुख्यमंत्री जी चण्डीगढ़ को 50:50 के रे ाों में बांटने की बात कर रहे हैं। ठाकुर बहादुर सिंह कह रहे थे कि हिसार और सिरसा जिले का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। हिसार जिले में एक भानू इंडस्ट्री हैं वहां इन्होंने अपने जिले में अपने नजदीकी रि तेदरारों को पौने पांच लाख की सबसिडी दिलवाई है और 63 ऐसे आदमी हैं जिनको पिछले चार साल में एक एक लाख से ज्यादा सबसिडी दी है। (व्यवधान) जिस तरह से चण्डीगढ को 50:50 की रे ाों से बांटने की बात कर रहे हैं ऐसे ही सबसिडी भी अपने जिले में 50:50 के आधार पर दे रहे हैं। 50:50 का जो फारमूला इन्होंने एडोप्ट किया हुआ है, यह ठीक नहीं है। यह सबसिडी दो करोड रूपये की बनती है। (व्यवधान) जो प्रस्ताव सदन में रखा है, मुख्य मंत्री जी इस प्रस्ताव को मानते ही नहीं हैं। हम तो पिछले हफ्ते ही कह रहे थे, हम सारे अपोजी ान के भाई कह रहे थे कि इस प्रस्ताव को मान लो और अम्बाला तहसील को बैकवर्ड डिक्लयेर कर दो, लेकिन ये मानते ही नहीं। जब हम सर्व सम्मति से कह रहे हैं तो मुख्य मंत्री को मानने में क्या हर्ज है, क्या यह ताना ाही नहीं है ? इससे ज्यादा ताना ाही का रवैया और क्या हो सकता है, क्या यह अप्रजान्त्रिक रवैया नहीं है ? (व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री अमर सिंह): आन ए प्वायंट आफ आर्डर। आनरेबल मैम्बर ताना ाही की बात कह रहे हैं हाउस में तो बोलने की बात आती है, ताना ाही की बात नहीं आती। 25 तारीख तक सै ान रखा है, अगर नहीं बोलना चाहते तो हाउस छोड कर चले जाओ। (व्यवधान)

श्री सभापतिः यह प्वांयट आफ आर्डर नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्यः चेयरमैन साहब, सरदार लछमन सिंह जी बैठे बैठे कुछ कह रहे हैं। ये कालका में जंगलात के ठेके का काम करते हैं। अगर जंगलात के मामले में ये अपना स्पश्टीकरण दें तो बहुत अच्छी बात होगी। यह जंगल इनका अपना था या किसी और का था ? (व्यवधान) इन्होंन और इनके सुपुत्र ने स्टेट बैंक आफ पटियाला के कर्मचारियों से मिल कर 10 लाख रूपये का फ्राड किया है श्री भगत सिंह और लछमन सिंह के नाम से (व्यवधान)

श्री लछमन सिंहः चेयरमैन साहब, कालका यहां से 15 मील के फासले पर है। ये जाकर बैंक से पूछ आयें। 10 लाख तो कया अगर 50 रूप्ये भी बैंक वालों के मैंने देने हों तो बता दें। ये गलत बात करते हैं ..... (व्यवधान) आप गाड़ी में बैठ कर जाओ और वहां जाकर पूछ लो। इन फजूल की बातों का मुझ पर कोंई असर नहीं होने वाला है। (व्यवधान) ....

श्री सभापतिः किसी भी मैम्बर के खिलाफ जो भी पर्सनल रिमार्क्स हों, वे रिकार्ड न किये जायें।

श्री हीरा नन्द आर्यः .....

श्री लछमन सिंह : .....

श्री हीरा नन्द आर्यः .....

Mr. Chairman: I would request the hon'ble Member to speak on the point.

श्री हीरा नन्द आर्यः चेयरमैन साहब, जो 50:50 की बात चल रही है, इसी आधार पर आज अम्बाला जिलो के पेड काटे जो रहे हैं। (व्यवधान)

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः चेयरमैन साहब, ये कौन से प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ?

श्री हीरा नन्द आर्यः यह सर्वव्यापक प्रस्ताव है। (व्यवधान) पेड तो इन्होंने इतने लगा दिये हैं, पता नहीं आने वाली नसलें कैसे काटेंगी। चेयरमैन साहब, ये कभी छोटे उद्योग धन्धों की बातें करते हैं, कभी बडे उद्योग धंधों की बातें करते हैं। बडे बडे उद्योग धंधों को 50:50 पैसा और सबसिडी देने से तो काम चल जाता है लेकिन छोटे धंधों का काम कैसे चलेगा ?

श्री लछमन सिंहः चेयरमैन साहब, ये बार बार 50:50 की बात कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है कृपया इन्हें चैक किया जाए।

Mr. Chairman: Please address the Chair and speak on the point (Interruptions).

श्री हीरा नन्द आर्यः .....

श्री सभापतिः ये रिमार्क्स भी रिकार्ड न किये जाएं।

श्री हीरा नन्द आर्यः सभापति जी मैं इस सरकार के बारे में क्या कहूं। अगर मैं फिफटी फिफटी वाली बात करूंगा तो फिर ये नाराज हो जायेंगे। इन्होंनें भिवानी और लोहारू को वैसे तो बैकवर्ड डिक्लेयर किया हुआ है। परन्तु वहां पर कोई भी इंडस्ट्री आदि नहीं लगायी जा रही है। मुख्य मंत्री महोदय ने लोहारू में हैफ्ड का वूल्न मिल लगाने के बारे में अनाउनसमैंट की थी लेकिन आज तक वह चालू नहीं हुआ। यह इलाका राजस्थान के साथ लगता हुआ है। बार्डर एरिया होने के कारण से राजस्थान से रा मैटीरियल आसानी से आ सकता है। इसलिए वहां पर वूल्न मिल आसानी से चल सकता है। लेकिन पता नहीं वह कहां गया। अगर यह सरकार ईमानदार होती तो वहां पर मिल लगाती परन्तु उस एरिया की और कोई ध्यान नहीं दिया। सरदार लछमन सिंठ जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। अगर वे इन्ट्रैस्ट लें तो राजस्थान से रा मैटीरियल मिल सकता है और काफी मात्रा में मिल सकता है। वहां पर मिल लग जाये तो बडा अच्छा चलेगा। हरियाणा के लोगों को रोजगार मिलेगा और एक नयी प्रकार की इंडस्ट्री डिवैल्प होगी। वहां पर ऊनी कम्बल बन सकते हैं और दूसरा सामान भी बन सकता है।

श्री लछमन सिंहः भिवानी में टी0आई0टी0 स्पीनिंग मिल पहले ही लगा हुआ है।

श्री हरि चन्द हुड्डाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। इन्होंने गलत बात कही है कि वहां पर कम्बल बन सकते हैं। ....

श्री सभापतिः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री लछमन सिंहः यह एक्पंज होना चाहिए।

श्री सभापतिः यह एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री हीरा नन्द आर्यः सभापति जी, मैं लोहारू में हैफ्ड द्वारा वूलन मिल लगाये जानै के बारे में जिक्र कर रहा था। इन्होंनें योजना बनायी थी लेकिन पता नहीं किस कारण से वह सिरे नहीं चढी। मुख्य मंत्री महोदय ने एलान भी किया था। लोहारू और पास के इलाके राजस्थान में काफी मात्रा में ऊन होती है। वहां पर रा मैटीरियल मिल सकता है। जहां तक टी0आई0टी0 मिल का संबंध है। वहां पर पहले 640 लूम्ज लगे हुए थे अब वहां 640 में से 160 और 150 लूम्ज रह गये हैं। सारे बंद हो गये हैं उन लूम्ज के बंद होने के कारण 2500 मजदूर बेकार हो गये हैं। वे आज घर बार से बेघर हो गये हैं। हरियाणा सरकार ने उस मिल को केन्द्रीय सरकार को कह कर 13 लाख रूपये की सबसिडी भी दिलायी है। उन्होंने पुरानी म ाीनरी को बेचल दिया है और नयी म ाीनरी खरीदी नहीं है तो फिर उन्हें

13 लाख की सबसिडी किसी बात के लिए दी गई। इस बारे में जांच करायी जानी चाहिये। कागजात में ठीक हो सकते हैं लेकिन मोके पर आप जा कर देखें तो सिस्टर कन्सर्न को सारी म ाीनरी बेच दी है। और 13 लाख रूपये की सबसिडी ले ली है। मेरे ख्याल में तो वहां पर भी फिफटी–फिफटी का फार्मूला चल गया है। इसलिए इस बारे में जांच होनी चाहिय। यह फार्मूला हरियाणा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

चेयरमैन साहब मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि धमीजा साहब का प्रस्ताव तो पास कर दिया जाए और जो अगला प्रस्ताव है उस पर विचार कर लिया जाये। अगला प्रस्ताव न ाबंदी के बारे में है, उससे लोगों की बरबादी हो रही है। आज कितने ही परिवारों का विना ा हो रहा है। दूसरा प्रस्ताव कर्जा और तकाबी के बारे में है। इस बारे में सरकार सुनने के लिए तैयार ही नहीं है।

इसलिए सरकार इसी रैज्योलू ान पर मैम्बरान का टाईम वेस्ट करवा रही है। यह अच्छा होता कि अगला रैजयोलू ान ले लेते और उस पर मैम्बरान को बोलने का समय देते ताकि हरियाणा के लोगों को सही मायने मे ंसेवा हो सके।

मास्टर राम सिंह (रादौर– अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब जो प्रस्ताव हाउस के सामने है उसको समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। धमीजा साहब ने प्रस्ताव रखा है और हाउस

से निवेदन किया है कि अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड करार दिया जाये। जहां हरियाणा हिन्दुस्तान में उपज के लिहाज से सबसे आगे हैं वहां इंडस्ट्री में भी सबसे आगे आना चाहिए। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

स्पीकर साहब रादौर हलका सन 1946 से रिजर्व ही चलता आ रहा है। वहां पर कोई वि ोश डिवैल्पमैंट के कार्य नहीं हुए। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जहां अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड घोशित किया जा रहा है। वहां पर रादौर को भी बैकवर्ड घोशित किया जाना चाहिए। रादौर के लिए इंडस्ट्री कम्पलैक्स पहले ही मंजूर हुआ है। वहां के जमींदार लोग भी बडे मेहनती हैं। उस क्षेत्र में उपज बहंत ज्यादा होती है लेकिन वहां के लोगों को लिए सडकों का कोई वि ोश प्रबंध नहीं है। और इंडस्ट्री की भी बडी भारी कमी है। उसके पास ही यमुना नगर का एरिया लगता है। वहां पर इंडस्ट्री बहुत बडी मात्रा में है। सारे रादौर क्षेत्र का माल वहां पर जाता है। रादौर में भी इंडस्ट्री लगायी जानी चाहिए। अगर इंडस्ट्रीज लग जाये तो वहां के लोगों का भी फायदा हो सकता है।

स्पीकर साहब, रादौर का क्षेत्र इरीगे ान के लिहाज से बहुत पिछडा हुआ है। उस इलाके से आगमेन्टे ान कैनाल और भाखडा कैनाल गुजरती है लेकिन सिंचाई के लिहाज से इस इलाके को वंचित रखा जा रहा है और किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। अगर यहां पर भी इंडस्ट्री लगा दी जायै तो

लोगों का काफी भला हो सकता है और सिंचाई के साधन भी ठीक कर दिये जायें तो पैदावार में भी काफी इजाफा हो सकता है। मैं हाउस का ज्यादा समय न लेते हुए यही रिक्वैस्ट करूंगा कि रादौर को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड क्षेत्र घोशित किया जाये।

श्री राम बिला ा भार्मा (महेन्द्रगढ): अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने कई दिनों पूर्व रखा गया प्रस्ताव विचारार्थ पे ा है जो श्री राम दास धमीजा जी ने रखा था कि अम्बाला तहसील को औद्योगिक दृश्टि से पिछडा हुए क्षेत्र घोशित किया जाये। स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदे ा कृशि प्रधान प्रदे ा है। यहां का सबसे बडा उद्योग खेती है। जो सरकार चले चलाये उद्योग को जो सदियों से यहां पर पनपता रहा है, संभाल नहीं सकती वह नये उद्योगों को क्या लगायेगी और क्या पनपायेगी ? घोशणा करने से क्या फर्क पडेगा ? मैं विपक्ष का प्रतिनिधि होने के नाते इस बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मेरे साथी यह न समझें कि विपक्ष ने हर प्रस्ताव का विरोध ही करना है। इसलिये मैं इसका भी विरोध कर रहा हूं। मेरा उनसे कोई मौलिक मतभेद नहीं है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि केवल किसी क्षेत्र को पिछडा हुए डिक्लेयकर कर देने से उसका कल्याण नहीं हो सकता। स्पीकर साहब मैं आपके माध्यम से सरकार से कुछ बातें कहना चाहता हूं। महेन्द्रगढ जिला राजस्थान की सीमाओं से लगता हुआ एक टिब्बों का जिला है। उसके प्रमुख जो उद्योग हैं, उनकी तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहां पर सबसे बडा

उद्योग हो सकता था प ुपाल का लैकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरे काबिल दोस्त हीरा नन्द आर्य ने यह कहा कि सरकार ने कई बार घोशणा की है कि लोहारू में ऊन का कारखाना लगाया जायेगा लेकिन लगाया नहीं गया मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ऊन की दृश्टि से हमारा इलाका सबसे आगे है। वहां पर नांगल चौधरी और नारनौल में इतनी ऊन पैदा होती है कि हमारे से 10 किलोमीटर दूरी पर खेतड़ी, सिंघाना, अलवर और कोटपुतली वगैरा के बडे बडे उद्योगपति यहां से लेकर जाते हैं अगर मेरा इम्प्रै ान सही है तो हमारे यहां इतनी ऊन होती है जितनी अलवर जिले में होती है। मगर सरकार यह नहीं सोचती कि वहां पर कोई उद्योग स्थापित किया जाये। पिग आयरन के नाम से हमारे यहां पर नांगल चौधरी के लिए एक उद्योग सरदार प्रताप सिंह कैरों के टाईम में सैंक ान हुआ था क्योंकि कच्चा लोहा वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में मिल सकता है वहां पर इंडस्ट्री स्थापिात करने का फसला भी हो गया और करोडों रूपया उसके लिए मंजूर भी हो गया लेकिन राजनैतिक कारणौं से that industry was shited from Narnaul to Hissar. After that, there are no procedings, and that industry is closed. मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि केवल घोशणा करने से इंडस्ट्री नहीं लगती। जिनकी अब तक घोशणा कर दी गई हैं, क्या वहां पर उद्योग ले चुके हैं ? नहीं। यह सरकार इन उद्योगों के नाम पर बडी तादाद में पढे लिखे बेरोजगार नौजवान को जो टैक्नीकल ट्रैंड और आई0टी0आई0 पास वैल्डरों या फिटरों को बेवकूफ

बनाया जा रहा है। अगर हम सच्ची बात कहें तो भाायद हमारे कई साथियों कौ अच्छी न लगे। हरियाणा में उद्योग के मामले में बहुत ज्यादा स्कोप हैं। महेन्द्रगढ़ जिले में मारबल बहुत ज्यादा मिलता है। मारबल, सारे हरियाणा में भी और हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा महेन्द्रगढ जिला सारे हरियाणा प्रदे ा को ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान भर को मारबल सप्लाई कर सकता है। लेकिन सरकार महेन्द्रगढ जिले में राजनीतिक कारणों से किसी उद्योग को भी लगाने मे रूचि नहीं रखती हैं इसलिए उस जिले के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार हो रहा है। वहां पर रहने वाले हमारे भाई यह समझते हैं कि हम तो हरियाणा में बसते ही नहीं है।। मेवात विकास बोर्ड बनाया गया। हम यह मानते हैं कि वहां का विकास होना चाहिय। सरकार की दृश्टि से महेन्द्रगढ सबसे पिछडा हुआ क्षेत्र हो सकता है लेकिन औद्योगिम दृश्टि से नहीं। अगर ऐसा होता तो यह सबसे पहले उसको इंडस्ट्रयली पिछडा हुआ घोशित करवाते। इनकी दृश्टि में हो सकती है कि वह ि ाक्षा के क्षेत्र में, सरकारी कामकाज में, विकास कार्यों में या सरकार अस्पतालों की दृश्टि से महेन्द्रगढ पिछडा हुआ क्षेत्र हो लेकिन यह सरकार तो उनकी तरफ भी ध्यान नहीं देती है। हमारे बिजली के महकमे के मंत्री उस इलाके के ही हैं वहां के किसान को पास केवल कृशि का ही उद्योग है, जिसे वह ठीक ढंग से चलाने की कोि ा ा कर रहा है। उसके बाद प ाुपालन का उद्योग आता है, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार करोडों रूपये कमा सकती है अगर यह हमारे नौजवानों को इस साइड पर रोजगार

मुहैया करवा दे। हरियाणा के लाखों लोगों को इस तरफ से भी रोजगार मिल सकता है। स्पीकर साहब मैं महेन्द्रगढ जिले में महेन्द्रगढ के पास एक पाली जगह के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर एटौमिक प्लांट लगाने की बात गवर्नमैंट सोच रही है। इसके साथ ही पहाडी से लगता हुआ खुजना का भी इलाका है। वहां पर काफी पुराने जमाने से ताम्बा मिलता रहा है। वहां पर ताम्बे की इंडस्ट्री भी चलती रही है। इस बात का सबूत वहां पर पुराने खंडरात हैं। वहां पर ताम्बा काफी मात्रा में मिल सकता है परन्तु हरियाणा सरकार वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहती। केवल घोशणा मात्र करने से क्या फायदा होगा ? धमीजा साहब से मेरी गुजारि ा है कि यदि वे अपने इस रैज्योलू ान में महेन्द्रगढ जिले को भी जोड लें कि इसे भी औद्योगिक दृश्टि से पिछडा हुआ घोशित किया जाये और इसे इस बारे में प्राथमिकता दी जाये, तो मैं उनका बडा आभारी हूंगा। महेन्द्रगढ जिले में जो पत्थर उपलब्ध है उसे मारबल कहते हैं। वहां पर उसका भी कोई उद्योग लगाया जा सकता है। या फिर वहा ंपर कौपर की खाने उपलबध हैं उनका कोई न कोई उद्योग लगाया जा सकता है। कौपर खुडाना में बहुत ज्यादा कौपर उपलब्ध है। इस बारे में मेरी वैज्ञानिकों से भी बातचीज हुई है, वे भी इस बात को मानते हैं। लेकिन राजनैतिक कारणों से सत्ताधरी पक्ष वाले वहां पर कोई इंडस्ट्री न लगायें तो यह सरासर ज्यादती है। मेरे साथ ही पूसा राम जी बोलना चाहते हैं कि मैं उनसे यह आ ाा करूंगा कि जब वे बोलेंगे तो मेरी बातों को स्पोर्ट करेंगे। क्योंकि वे भी उस हल्के

का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुझे यह मालूम है कि मारबल के सिलसिले में उनको बहुत जानकारी है। मैं सकरार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि आपकों करों के रूप में वहां से करोडों रूपया मिल सकता है और लाखों करोडों नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। यदि आप वहां पर ऐसे उद्योग स्थापित करें जिनकी मैंने मांग की है। इससे लाखों कुंठित बेरोजगार लोग अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकते हैं। आनरेबल मैम्बर साहब ने यह प्रस्ताव रखा है कि अम्बाला तहसील को ही केवल औद्योगिक दृश्टि से पिछडा हुआ घोशित किया जाये। मैं यह चाहता हूं कि कि केवल घोशणा करने कि बात ही नहीं होनी चाहिये वहां पर कोई न कोई इंडस्ट्री लगाने के बारे में भी सुझाव आना चाहिये था। जैसे बिजली के सामान की या किस स्पैसिफिक इंडस्ट्री के लगाने के बारे में सुझाव आना चाहिये था। मेरे जिले में लाईम स्टोन भी बहुत मात्रा में मिलता है। मेरा ख्याल यह है कि वह काफी हद तक हरियाणा की इस रिक्वायरमैंट को पूरा कर सकता है। सीमेंट की रिक्वायरमैंट उसकी प्रोडक ान से कहीं ज्यादा है। लेकिन हरियाणा सरकार दादरी सीमैंट फैक्टरी को चला नहीं सकी। हमारें मजदूर जो वहां पर काम करते थे वे बेकार हो गये थे। दादरी का सीमेंट उद्योग काफी लम्बे समय तक बंद रहा। आखिर में जब हरियाणा सरकार फेल हो गयी तो केन्द्रीय सरकार को उसको अपने हाथों में लेना पडा। महेन्द्रगढ जिले में जो पत्थर जमीन में मिलता है, उससे सीमेंट का काम बडी आसानी से लिया जा सकता है। वह इमारत बनाने के काम भी आ सकता है

और उसमें सीमेंट की कमी को भी दूर किया जा सकता है। मेरा विचार है कि वह काफी हद तक हिन्दुस्तान की सीमेंट की जरूरत को पूरा कर सकता हैं एक तरफ तो सरकार उद्योग नहीं लगा रही है लेकिन दूसरी तरफ कच्चा माल सरकार को चुनौती दे रहा है। महेन्द्रगढ़ जिले में कच्चा माल हरियाणा सरकार को चैलेंज दे रहा है कि मुझे यूज किजिये। मैं इतनी बडी मात्रा में यहां पर अवेलेबल हूं लेकिन सरकार जानकारी होते हुए भी वहां पर कोई उद्योग धंधे नहीं लगा रही हैं। सरकार इस बारे में सो रही है या सियासी आधार की वजह से वहां पर कोई उद्योग स्थापित नहीं करना चाहती। हरियाणा सरकार की चार इकाईयां थीं जो इसवने लगायीं थीं, एक चमडा का उद्योग था। वह भी ठीक नहीं चल रहा है। एक माचिस का कारखाना सरकार ने लगाया था करोडों रूपये की इन्वैस्टमैंट की हुई थी लेकिन उसमें भी घाटा हुआ जिस कारण से वह बंद करना पडा। एक इस्पात का उद्योग था जो कि पूंजीपति का है। I visited Anand Dairy in Khera Distt. of Gujarat. वहां पर लोग कितने खु ाहाल हैं जबकि वहां पर कैटल एवरेज सिर्फ 4 लीटर दूध की हैं गुजरातमें लाखों बेरोजगार लोग इस तरफ लगे हुए हैं। वहां पर यह काम फायदे में चल रहा है। वहां का छोटा जमींदार भी खु ाहाल हैं और आराम से जिंदगी जी रहा है। हरियाणा की वर्ल्ड बैंक की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा दूध हरियाणा में पैदा होता है। वहां केवल दूध ही पैदा नहीं होता बल्कि उस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा फैट भिवानी नारनौल और महेन्द्रगढ के दूध में होता है।

स्पीकर साहब, हरियाणा में जो दूध का उद्योग चल रहा हैं वह घाटे में जा रहा है। हरियाणा में कोई ऐसा मिल्क प्लांट नहीं है जो घाटे में न जा रहा हो। हमारा वीटा घी का प्लांट भी घाटे में जा रहा है लेकिन मधु वालों का प्रोफिट में जा रहा है क्योंकि वह प्राईवेट हाथों में है। The same milk is processed in Madhu concern. They are showing profits. They are running in lacs. We are losing in lacs. It is a contradiction. एक जिले की सीमा में दो कन्सर्न हैं एक मुनाफा देता हैं और दूसरा घाटे में जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने कौन सी ऐसी बात रखी हैं जिससे यह पता लगता हों कि यह सरकार लोगों की भलाई के लिए कुछ करना चाहती है। जिस सरकार पर लोगौं की तकलीफ दूर करने की जिम्मेदारी है, आज ऐसा लगता है कि वह सो रही है। जो बजट मेरे साथियों ने पे ा किया है उससे लगता है कि यह सरकार हरियाणा को किसी दि ाा में बढाना नहीं चाहती। ऐसा लगता है कि हरियाणा में किसी उद्योग की गुंजाइ ा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हरियाणा के अंदर दूध का उद्योग इतना बडा उद्योग हो सकता है कि it can be developed to Denmark of India. यहां से आफिसर्ज की टीम जाती है और मुझे पता है कि हरियाणा में बहुत से काबिल औफिसर्ज हैं लेकिन उनको राजनैतिक कारणों से काम नहीं करने दिया जाता। उनको पता है कि अगर उन्होंने कुछ काम किया तो दूसरे दिन उनका स्थानान्तरण कर दिया जाएगा इसलिए वे काबिल आफिसर्ज बेचारे चुप हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में इतने बडे

उद्योग लग सकते हैं और पनप सकते हैं जिनसे करोडों रूपये की कमाई हो सकती हैं, लाखों नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है परन्तु सरकार उनको लगाना नहीं चाहती। हरियाणा के लोगों को इस सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं है। लोग इस व्यवस्था से निरा ा हो चुके हैं। हरियाणा के लोगों का इस सरकार से वि वास उठता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में किसी चीज की दिक्कत नहीं है। यहा ंपर रा–मैटीरियल भी है, मजदूर भी हैं परन्तु इस सरकार की कोई काम करने की नियत नहीं है। In Haryana everthing is available in huge quantity and quality but nothing is being done in this direction. अध्यक्ष महोदय, इस बजट में उद्योगों के लिये जो रूपया रखा गया है वह सबके सामने हैं। मैं तो धमीजा साहब के प्रस्ताव पर यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा में जो उद्योग भाताब्दियों से चल रहा है और जिस उद्योग पर सौ में से पचास आदमी रोटी खा रहे हैं उस उद्योग की क्या हालत है ? अध्यक्ष महोदय, आज किसान की क्या हालत है ? आप भी किसान को रिप्रेजैन्ट करते हैं। आपको सब कुछ पता है। आपको यह भी पता है कि उस उद्योग की क्या हालत है ? आज उसको रा–मैटीरियल नहीं मिलता किसाने को जो खाद मिलता है और जिसको वह खेत में डालता है वह महंगा मिलता है और जो वह पैदा करता है वह सस्ता बिकता है। आज पैदावार और लागत का कोई तालमेल नहीं है। किसान की कास्ट आफ प्रोडक ान उसको नहीं दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा में उद्योग की बात कर रहा था। जब तक हमारे दिमाग में सरकार चलाने वालों के दिमाग में यह बात नहीं आएगी कि हरियाणा में जो भाताब्दियों से चलने वाले उद्योग है, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उनको प्रायरिटी दी जानी चाहिए, पहला स्थन दिया जाना चाहिए तब तक हरियाणा में उद्योग नहीं पनप सकते। अध्यक्ष महोदय, आज खेतों में उद्योग पनप सकते हैं। जैसे किसान टमाटर पैदा करता है और वह सड जाते हैं क्योंकि जब किसान उनको मार्किट में लेकर जाता है तो उसको बहुत ही कम भाव दिया जाता है। मण्डी में आढ़ती जानता है कि किसान को तो यह टमाटर बेचना ही पडेगा। वह किसान की मजबूरी का फायदा उठाता है। सरकार को चाहिए कि जहां टमाटर पैदा होता है। वहां पर सौस की फैक्टरी लगाएं जिससे किसान का टमाटर ठीक तरह से इस्तेमाल हो सके और उसको उचित भाव मिल सके। सरकार को किसान की पैदावार के लिए गोदाम बनाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, किसान आलू पैदा करता है और जब किसान आलू को लेकर मंडी में जाता है तो कौड़ियों के भाव बिकता है। आढती के दिमाग में यह बात होती है कि किसान को आलू मंडी में लाना ही पडेगा क्योंकि उसको पैसा चाहिए। किसान को अपनी लडकी की भाादी करनी है, अपने बच्चों की फीस देनी है, अपना कर्जा चुकाना है, अपने तथा बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं तो पैसे की आव यकता होती है। आढ़ती किसान की मनमर्जी का भाव देता है और ऐसा करके उसकी मजदूरी का फायदा उठाता है। सरकार को चाहिए कि जहां

आलू पैदा होता है वहां पर गोदाम बनाए और इसको ही इंडस्ट्री मानकर किसान को फैसिलिटी दें। अध्यक्ष महोदय, जींद में चमडे का उद्योग फिर से पनप सकता है। मुझे पता है कि हरियाणा में बहुत काबिल आफिसर हैं। सरकार को उनकी काबलियत का फायदा उठाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं भूगर मिल्ज के बारे में कहना चाहता हूं। हरियाणा में काफी गन्ना पैदा होता है और यहां पर कई कोआप्रेटिव सैक्टर में भूगर मिल्ज हैं लेकिन वे सब घाटे में जा रही हैं। यमुनानगर में एक प्राईवेट सरस्वती मिल है जिसका मालिक डी0डी0 पुरी हैं वह फायदे में चल रही है और बाकी जितनी सरकारी मिल्ज हैं वे घाटे में चल रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब प्रोईवे आदमी मुनाफा कमा सकता है तो इस सरकार को क्या हो गया है कि इसकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वे घाटे में चल रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब प्राईवेट आदमी मुनाफा कमा सकता है तो इस सरकार को क्या हो गया है कि इसकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वे घाटे में चल रही है। अध्यक्ष महोदय, आप सरकार की चाहे कोई इण्डस्ट्री ले लें, चाहे दूध का प्लांट हैं, चाहे चीनी उद्योग है और चाहे कोई और इण्डस्ट्री है, सब घाटे में चल रही हैं। धमीजा साहब के दिमाग में भाायद यह बात होगी कि अम्बाला को इण्डस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर कर देने से बहुत बडी बात हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार उद्योगों के प्रति लापरवाह है और इस सरकार को इस लापरवाही को दूर कना

चाहिए। जहां पर भी जो रा–मैटीरियल उपलब्ध है, जहां जो चीज पैदा हो सकती है, जिस चीज को जहां डिवैल्प किया जा सकता है उसकी तरफ सरकार को प्रायरिटी देनी चाहिए और उसी तरह की इंडस्ट्री उस जगह पर लगानी चाहिए। इस समय सरकार की जो परफोरमैंस हैं उससे कहीं यह पता नहीं लगता कि सरकार की उद्योग लगाने में रूचि है क्योंकि मुझे पता है कि लगे लगाए उद्योग ही घाटे में जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 12 तारीख को नारनौल में एक सरकार दरबार लगाया गया था और वहां पर आ वासन दिया गया था कि चौदह घंटे बिजली दी जाएगी लेकिन वह वादा पूरा नहीं किया गया है।

श्री लछमन सिंहः अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मैं अपने फाजिल दोस्त को बताना चाहता हूं कि जब हरियाणा बना था उस वक्त हरियाणा में साढे चार हजार उद्योग थे और आज अडतीस हजार उद्योग लग चुके हैं।

श्री राम बिलास भार्माः आप यह भी बता दीजिये कि उनमें से कितने चल रहे हैं और कितने बंद हो गए हैं ?

श्री लछमन सिंहः अध्यक्ष महोदय, उस वक्त हमारी इंडस्ट्री की प्रौडक ान की ऐक्सपोर्ट सिर्फ चार करोड की थी और आज एक सौ पचालस करोड रूपये से अधिक की ऐक्सपोर्ट है। अगर इंडस्ट्री नहीं चल रही हैं तो ऐक्सपोट्र केसे बढ सकती है ?

Sh. Ram Bilas Sharma: Fortunately, I know the data. Fortunately, I know the industries particularly established by them with the help of Haryana Government. Sir. अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि जब हरियाणा बना था उस वक्त साढे चार हजार उद्योग थे और आज अडतीस हजार उद्योग हरियाणा में हैं। अध्यक्ष महोदय, ये फिगर्ज कागजों में हैं। इनको पता होना चाहिए कि जो दस बीस हजार या एक लाख रूपये से उद्योग लगाए गए हैं वे तो चल ही नहीं रहे हैं वे तो बंद पडें हैं लेकिन फिगर इनके कागजों में है। मैं बताना चाहता हूं कि महेन्द्रगढ में एक पौटरीज की इंडस्ट्री लगी। हरियाणा पौटरीज के नाम से। एक नौजवान ने चार लाख रूपया इंवैस्ट किया। रा–मैटीरियल भी मिल गया, पाउडर भी मिल गया, पत्थर भी मिल गया लेकिन सरकार की तरफ से कोयला नहीं मिला। उस बेचारे को यह इंडस्ट्री बंद करनी पडी और उसको लाखों रूपये का नुकसान उठाना पडा। नारनौल में एक और इंडस्ट्री यादव इंडस्ट्री के नाम से लगाई गई उसको भी सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली और उसे भी बंद करना पडा। वे बेचारा बरबाद हो गया और मजबूर होकर उसको नौकरी करनी पडी। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की बहुत सारी मिसालें बताई जा सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा और आपका पौलिटीकल डिफरैंस हो सकता है लेकिन हमारे दिल में भी हरियाणा के लोगों के कल्याण की भावना है और आपके दिल में भी है। यह ठीक है कि हमारी

और आपकी राजनैतिक रूचि एक नहीं है लेकिन लोगों का कल्याण करने की भावना तो हमारे दिल में भी हैं। हरियाणा के लोगों का कल्याण तो हम भी कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हरियाणा में उद्योग पनप सकते हैं अगर सरकार के दिल में हरियाणा के लोगों के कल्याण की जरा भी बात हो। हरियाणा में खनिज पदार्थ हैं, वे बनाने नहीं पडते और न ही दूर से लाने पडते हैं। ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी नहीं पडता है। महेन्द्रगढ में जो पिग आयरन के नाम से इंडस्ट्री थी, जिसके लिये करोडों रूपया लगा हुआ है, उसको फिर से क्यों न चालू किया जाए। क्यों न महेन्दगढ को एक मारबल का क्षेत्र घोशित किया जाए जो कि सारे भारत को मारबल सप्लाई कर सकता है। स्पीकर साहब, इसी इलाके को हम रिप्रजैन्ट करते हैं, हम वहां के लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमें अपनी बात कहने का अपने हल्के के बारे में पूरा पूरा अधिकार है। भाायद सरकार उस इलाके को किसी और च में से देख रही हैं। महेन्द्रगढ का इलाका जहां के लोगों का जीवन प ा पालन पर निभ्रर करता है, वहां पर लोग ऊन का धंधा ज्यादा करते है और अपने बाल बच्चों का पालन पोशण करते हैं। वहां का किसान अपनी ऊन बेचने के लिये खेतरी ले जाता है क्योंकि यहां पर उसकी ऊन खरीदने वाला कोई नहीं है। अब सरकार वहां पर मछली पालन का काम करना चाहती है। स्पीकर साहब, आपको पता ही है कि वइ इलाका जहां पर पीने का पानी नहीं मिलता, वहां पर मछलियों के पानी का प्रबंध सरकार कैसे करेगी ? सरकार को वहां पर ऊन की इंडस्ट्री की तरफ ध्यान

देना चाहिये ताकि वहां के लोगों को भी फायदा हो सके लेकिन सरकार मछली पालन का धंधा खोलने का सोच रही हैं। It is the practica knowledge of our Haryana Government. It is the efficeincy of the Industries Department, Sir.

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, अगर वहां पर पानी नहीं है तो मछली कर जाएंगी और फिर यह उद्योग वहा ंपर क्या खुलेगा ?

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, मैं अपने दोस्त लछमन सिंह जी को कहूंगा कि वे मेरे जेल के साथी हैं, मैं उनको पूरा पूरा सम्मान करता हूं। वे मेरी इस बात से अपनी इन–ऐफीि ाएंसी न समझ लें। हमने तो अपने मन की बात कहनी ही है, हमने तो अपने इलाके के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर हर बात को सरकार तक पहुंचाना है। मेरा एक सुझाव उनको है कि मछली पालन का धंधा महेन्द्रगढ के सूखे रेतीले टिब्बों में कैसे चलेगा ? वहां के तालाबों में यह काम कैसे हो सकता है ? वहां पर तो अगर कोई उद्योग पनप सकता है तो वह ऊन का ही पनत सकता है। वहां से सरकार को काफी आमदनी हो सकती है और चरवाहे भी अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सकते हैं। ऊन का उद्योग वहां पर चालू किया जाए और चरवाहों को यह कहा जाए कि आपको ऊन बेचने के लिये खेतड़ी वगैरह नहीं जाना पड़ेगा। पानीपत सारे भारत का एक बडा भारी औद्योगिक केन्द्र है, वहां पर इस ऊन का काफी मात्रा में इस्तेमाल

हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि पहले हमारे हरियाणा से राजस्थान में ऊन जाती है और फिर जयपुर के जरिये ऊन हरियाणा में लायी जाती है, कितनी बुरी बात है। हरियाणा में ऊन पैदा करने वालों को इसका कोई खास लाभ नहीं हो रहा है। दूसरे राज्य इसका फायदा उठा रहे हैं। इसी तरह से स्पीकर साहब, दादरी में एक भारी सीमैंट फैटरी थी जो कि किन्हीं राजनीतिक कारणों से बंद करवा दी गई थी क्यौंकि सरकार का कोई खास आदमी श्री डालमिया से नाराज हो गया था। मैं उनका नाम नहीं लूंगा ..... इसलिये सरकार ने उस फैक्टरी को बिजली इररैगुलर करवा दी। मजबूर होकर उस उद्योगपति को अपना दिवालिया दिखाना पडा और फैक्टरी को बंद करना पड़ा। वह फैक्टरी अढाई साल के लगभग बंद रही जबकि स्पीकर साहब, आपको पता है कि सीमैंट की आज कितनी जरूरत है और दूसरी तरफ धमीजा साहब किसी एक खास क्षेत्र को इंडस्ट्रीयल टाऊन घोशित करवाने के लिये यहां पर रैजौल्यू ान लाये हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः मेरे लायक दोस्त ने दादरी की सीमैंट फैक्टरी के बारे में यह कह दिया कि किन्हीं राजनीतिक कारणों से वह फैक्टरी बंद करा दी गयी और बिजली को बंद कर दिया गया जिसके कारण से वह फैक्टरी बंद हो गयी। यह बात गलत है। इन कारणों से वह फैक्टरी बंद नहीं हुई। पूंजीपति की मिस मैनेजमैंट के कारण वह फैक्टरी बंद हुई

थी और दूसरे फाइनैंसियल बंगलिग की वजह भरी हो सकती है और अब हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की मंजूरी से उसको टेक ओवर कर लिया है और अब वहां पर रिकार्ड प्रोडक ान है। दूसरी बात इन्होंने यह कह दी ..... इस बात को कार्यवाही में से निकलवा दिया जाए, यह बात बिल्कुल गलत है।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, अभी सुरजेवाला साहब ने खडे होकर जो सफाई दी है और बताया है कि अब सरकार ने उस फ ैक्टरी की टेक ओवर कर लिया है, चलो अच्छी बात है। स्पीकर साहब, आपको भी पता है कि किन कारणों से वह उद्योग बंद हुआ था। (ाोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: You know and I also know as to why that factory was closed. Please come to the point now. (Interruptions)

श्री राम बिलास भार्मा: मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हरियाणा सरकार उद्योग को प्रायोरिटी दे। उद्योग लगाने के बारे में सोचें। हरियाणा में जो उद्योग जाए या जो लग सकता हो, उसको पहले प्राथमिकता दी जाएं ताकि बेकारी को दूर किया जा सके और लोगों को भी अपने काम धंधों में राहत महसूस हो।

स्पीकर साहब, सुरजेवाला साहब ने यह कहा कि पूंजीपति की मिस मैनेजमैंअ की वजह से वह फैक्टरी बंद हुई। कितने अफसोस के साथ कहना पडता है कि सालों से वे पूंजीपति

उस फैक्टरी को चला रहे थे और अब उनकी मैनेजमैंट में खराबी आ गयी। हो सकता है कि इनको अपने च में में हरा दिखायी देता हो लेकिन मुझे तो अपने च मे से कुछ और ही दिखायी देता है। Is it the criteria to see the thing, Sir ? मैं फिर आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि जो उद्योग पहले हरियाणा में चले आ रहे हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनकी जरूरत की तरफ ध्यान दिया जाए और राजनीतिक कारणों से किसी उद्योग को बंद न किया जाये। धमीजा साहब ने जो यह प्रस्ताव इस हाउस के सामने रखा है कि केवल अम्बाला तहसील को औद्योगिक क्षेत्र घोशित किया जाए, इससे तो केवल एक ही इलाके का कल्याण होगा न कि सारे हरियाणा का कल्याण होगा। इससे यह समस्या हल नहीं होगी जब तक कि सारे हरियाणा प्रान्त को औद्योगिक क्षेत्र घोशित न किया जाएगा और खास तौर पर जिन इलाकौं में उद्योग लगने जरूरी है। और संभावनाएं भी हैं जैसा कि महेन्द्रगढ उन इलाकों में भी इस नजरिये से सरकार को देखना चाहिये ताकि वहां पर भी इंडस्ट्रीज को बढावा मिल सके और इंडस्ट्रीज पूरी तरह से पनप सके। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः यह जो बेटा भाब्द का यहां पर इस्तेमाल किया गया है, चाहे यह क्लीयर नहीं है लेकिन बडा ससपिि ायस है इसलिये कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया जाये।

उद्योग मंत्री (श्री लछमन सिंह): स्पीकर हाउस श्री राम बिलास जी ने दो तीन सुझाव बडे अच्छे दिये हैं मैं उनको आपकी मार्फत इंवाइट करता हूं कि वे साढे चार बजे मेरे दफ्तर में आ जाएं क्योंकि हम इकट्ठे देख लेंगे कि कौन कौन से काम करने हैं मैं भी अपने संबंधित अधिकारियों को वहा ंपर बुला लूंगा। वहां पर हम सारी बात कर लेंगे।

सहकारिता मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, मैं केवल एक दो मिनट ही लूंगा क्योंकि यहा ंपर बोलते हुए भूगर मिल्ज के बारे में कहा गया है कि भूगर मिल्ज घाटे में गई हैं मैं यहां हाउस की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान की भूगर मिल्ज इस बार 500 करोड रूपये के लौस में हैं। हमने इतना घाटा होते हुए भी किसान को जो एग्रीकल्चर प्राइस कमी ान ने साढे 13 रूपये गन्ने की कीमत फिक्स की थी, उससे ऊपर जाकर 20 रूपये क्विंटल गन्ने की कीमत किसानों को दी है। हम चाहें घाटे में जायें लेकिन किसानों को घाटे में नहीं जाने देंगें। (तालियां)

श्री कंवल सिंह: मिनिस्टर साहब ने बताया कि तमाम हिन्दुस्तान में सभी भूगर मिल्ज में 500 करोड रूपये का घाटा हुआ है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि केवल को आप्रेटिव भूगर मिल्ज में घाटा है, प्राईवेट में घाटा नहीं है। यमुनानगर वाली भूगर मिल्ज फायदे में जा रही हैं।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः मैं इन के नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि इसमें दोनों मिल्ज भाामिल हैं। को आप्रेटिव भी और प्राईवेट भी। (ाोर एवं व्यवधान) मुझे इस बार पूरा वि वास है कि हम चार भाूगर मिल्ज में से दो में प्रौफिट दिखायेंगे।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आड्डर है कि सरदार प्यारा सिंह जी काफी जोर भाोर से मेज को थपथपा रहे हैं। ये एम0आई0टी0सी0 के चेयरमैन हैं, इनके विभाग में पहले 45 पटवारी रिट्रेन्च कर दिये गये और अब कुछ और कर्मचारी निकालने जा रहे हैं। बाई फरके ान करके जींद को जुलाना और सफीदों को हिसार के साथ मिलाया जा रहा है और इस तरह से यह डिवीजन का डिविजन तोडा जा रहा है यह कोई अच्छी बात सरकार नहीं करने जा रही है।

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

चौधरी हुकम सिंह (सालहावास): माननीय अध्यक्ष महोदय, सेठ राम दास धमीजा जी ने सिर्फ अम्बाला तहसील को इंडस्ट्री के तौर पर बैकवर्ड घोशित करने का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करते हुए साथ में मैं अपने इलाके बारे में भी इस सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

1.00 बजे।

हमारे देहात में एक बहुत पुरानी मिसाल है कि किसी आदमी ने किसी गरीब आदमी से पूछा कि दो और दो कितने होते

हैं तो वह कहने लगा चार रोटियां। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मेरे आदरणीय भाई राम बिलास जी ने कुछ सुझाव दिये वे बहुत ही अच्छे सुझााव थें अध्यक्ष महोदय, रोहतक जिले की तहसील कोसली तथा हलका सालहावास महेन्द्रगढ जिले के साथ लगता है। वह इलाकाच पहले से ही बहुत सूखाग्रस्त है परन्तु तहसील कोसली में किसी भी प्रकार को कोई फैक्टरी नहीं है। मैं आपके माध्यस से सदन से निवेदन करूंगा कि तहसील कोसली को भी इंडस्ट्रियली बैकवर्ड करार दिया जाये ताकि वहां के किसानों को और जो बेरोजगार नौजवान फिर रहे हैं उनको भी कुछ राहत मिल सके। तहसील कोसली में इस समय दो ही मुख्य काम हैं। एक तो खेती का काम और दूसरा प ाुपालन का काम। इन दोनों कामों के लिये भी बहुत सी स्कीमें हैं जो वहां खोली जा सकती हैं। अगर ऐसी स्कीमें चालू की जाएं तो बेरोजगारों को रोजगार मिल जाचएगा। दूसरे वहां प0र एक आई0टी0आई0 खाने का यह भी फायदा होगा कि अगर कोई अपना काम खोलना चाहता है और उसके पास पैसा न हो तो वह सरकार से लोन लेकर भी काम खोल सकता हे। इसके सथ साथ हलका साहलावास में भी किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्री नहीं है जो कि खोली जानी चाहिए। उस हलके के लोग हमे ाा चार पांच सौ एकड जमीन फ्री देने के लिये तैयार हैं फिर भी बडे दु:ख की बात है कि उस इलाके में आज तक भी कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। वहां का चुना हुआ एम0एल0ए0 भी हमे ाा सरकार में रहा है लेकिन फिर भी उस इलाके की यह हालत है। सेठ राम दास जी के प्रस्ताव से मुझे

कोई आपत्ति नहीं लेकिन मैं तो यह चाहता हूं कि साहलावास और तहसील कोसली को भी इंडस्ट्री बैकवर्ड घोशित यिका जाए ताकि वहां के लोगों को भी सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल सके। इन भाब्दों के साथ मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। स्पीकर साहब, इंडस्ट्री की तो जरूरत ही नहीं क्योंकि डिफैक्टर्ज की ही बहुत बडी इंडस्ट्री लगी हुई हैं। एक साथी मेरे पडोस में बैठा करते थे, जो अब कांग्रेस में चले गये हैं मैंने उनसे पूछा कि मुंह लटकाये क्यों बैठे हो, अब क्या कमी है ... ...

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। आप बैठिये।

चौधरी कुन्दल लाल (सफीदों): अध्यक्ष महोदय, धमीजा साहब ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं अपने इलाके की कुछ कमियां भी आपके सामने रखूंगा। एक बात मैं अपने अपोजी ान के भाईयों से कहना चाहता हूं कि ये जो आज बातें कर रहें हैं, इनको अपना समय याद नहीं। अढाई साल ये क्या करते रहे ? अभी एक भाई ने टेनरी और मिल्क प्लांट जींद का जिकर किया। मिल्क प्लांट में नुकसान होने का कारण इनकी मेहरबानी थी क्योंकि इन्होंने वहां स्ट्राइक करवाई थी। दूसरे

उद्योग में भी यही कारण था। आज आप दोनों उद्योगों को जाकर देख लो, कितना अच्छा काम चल रहा है और कितनी अच्छी चीजें वहां तैयार हो रही हैं। मैं अपने इन भाईयों को ज्यादा कुछ न कहता हुआ इतना जरूर कहूंगा कि ठीक बात को ठीक कहो और गलत को गलत कहो। मैं मानता हूं कि डैमोक्रैसी में अपोजी ान का होना बहुत जरूरी है। (ाोर) अब आपको तकलीफ इसलिए हो रही है कि मैंने आपकी चलती हुई नब्ज को पकड लिया है। स्पीकर साहब, अब मैं अपने हलकै के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे हल्के सफीदों के अंदर भी इंडस्ट्रीज की कमी है। मैं आपके द्वारा सरकार से कहूंगा कि वह उधर भी ध्यान दें। हमारी सरकार ने अब वैसी ही दो निगम और कायम की हैं। हमारे अपोजी ान के भाई किसान मजदूरों की बात करते हैं और अभी एक भाई ने फरमाया था कि बीस सूत्री कार्यक्रम बोगस है और फ्राड है। मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि अगर यह फ्राड है तो इससे अच्छा काम और कौन सा है। गरीबौं और बैकवर्ड क्लासिज के लिये कभी अलग से निगम नहीं बना था। पिछले साल इस निगम को दो करोड रूपया दिया गया और वह सारे हरियाणा के अंदर तकसीम हुआ। वह पैसा लोगों को छोटे उद्योग लगाने के लिये मिला और सारे हरियाणा में आज छोटे उद्योग चल रहे हैं इन्होंने कहा कि बडे उद्योग बंद हैं, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं हैं जो दो करोड रूपया दिया गया था उसकी 98 प्रति ात वसूली भी हो चुकी है। आज इससे अंदाजा लगापएं कि अगर सरकार यह सहायता न देती और उनकी इंडस्ट्रीज ठीक प्रकार से न चली

होती तो 98 प्रति ात वसूली नहीं हो सकती थी। इस बार हरियाणा सरकार ने इस निगम को चार करोड रूपये देना है। जब यह रूपया बंट जाएगा तो उससे हर तरह की दस्तकारी लगेगी और सारे हरियाणा के अंदर चार चांद लगेगा। इसी तरह से सरकार ने एक वीकर सैक ान के लिये भी निगम कायम की है। स्पीकर साहब, हरियाणा इकानोमिकली वीकर सैक ान कल्याण निगम के जरिए चाहे कोई बनिया है, चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे कोई जाट है और चाहे कोई गुजर है, स्वर्ण जाति में चाहे कोई भी जाति कमजोर है इस निगम के जरिए उनकी पूरी सहायता की जा रही है। इस निगम के चेयरमैन हुड्डा साहब हैं। इस निगम को बने अभी बहुत थोडा अर्सा हुआ है। वह निगम पूरे जोर से काम कर रही है। उस निगम द्वारा हर जिले में लोगों को लोन दिया जा रहा है और गरीब लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। हरियाणा के स्वर्ण जाति के गरीब लोग उस निगम से लोन लेकर अपने छोटे मोटे धंधे लगा रहे हैं इसके अलावा उस निगम द्वारा गरीब लोगों को लोन देने से दस्तकारी के काम ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। स्पीकर साहब, जिस वक्त अपोजी ान की सरकार थी उस समय उस सरकार ने यह कहा था कि हम बैकवर्ड क्लासिज को 26 परसेंट रिजर्वे ान देंगे लेकिन कोई रिजर्वे ान नहीं दी गई। जिस वक्त हरियाणा में चौधरी भजन लाल जी की सरकार नबी उस वक्त उस सरकार ने बैकवर्ड क्लासिज की 5 परसैंट रिजर्वे ान को बढा कर 10 परसैंट कर दिया था। चौधरी भजन लाल जी ने हर जगह बैकवर्ड क्लासिज के लिए रिजर्वे ान रखी

है। मैं भी उसका सबूत हूं। मैं खुद बैकवर्ड क्लास से संबंध रखता हूं। मुझे इलैक ान के दौरान कांग्रेस पार्टी का जो टिकट मिला था वह रिजर्वे ान के हिसाब से मिला था। स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा और एक मिसाल दूंगा कि मेरे लोकदल के भाईयों को पार्टी में एक मेरी बिरादरी का भाई जय नारायण वर्मा था उसको ये भाई लीडर भी मानते थे। इन्होंने उसका बेडा गर्क करके छोड दिया। वह न घर का रहा और न घाट का रहा। मेरी भी उनसे बात हुआ करती थी। उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी कांग्रेस पार्टी वाले बैकवर्ड क्लास के कितने आदमियों को टिकट देंगे। मैंने उनसे कहा कि रिजर्वे ान के हिसाब से जितनी टिकट मिलेगी उतनी ही देंगे लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी पार्टी वाले कितनी टिकट देंगे तो उन्होंने कहा कि मैं 12 टिकटें बैकवर्ड क्लास कि आदमियों को दिलाऊंगा, 11 टिकटें नहीं होने दूंगा, पूरी 12 टिकटें दिलवाऊंगा। लेकिन स्पीकर साहब, उनको खुद को टिकट लेने के लाले पड गए। उनको टिकट तो मिल गया लेकिन बेचारे हार गए और आज उनके साथ जो कुछ हो रहा है उस बारे में उनसे पूछ लिया जाए। स्पीकर साहब, मैं विरोधी पक्ष के भाईयों से यह बात कहना चाहता हूं कि श्री जय नारायण वर्मा के साथ तो टिकट लेने में यह बात हुई जैसे सिक्खों की बाणी में एक बात कही गई है "कि चिड़िया नाल बाज लड़ाऊं"। (ाोर एवं विघ्न)

श्री फतेह चन्द विजः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्ड है कि श्री कुन्दन लाल जी रैजोल्यू ान पर बोल रहे हैं या अपने को बैकवर्ड डिक्लेयर करवाने के बारे में बोल रहे हैं। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी कुन्दन लालः स्पीकर साहब, मैं विधान सभा की अ योरैंस कमेटी का मैम्बर हूं और श्री फतेह चंद विज उसके चेयरमैन हैं। उस कमेटी में तीन सदस्य अपोजी ान पार्टी के हैं और हम कांग्रेस पार्टी के चार सदस्य हैं। पिछले दिनों हमारी कमेटी दूसरी स्टेटों के दौर पर गई थी। जब हम महाराश्ट्र की राजधानी बम्बई गए और वहां की कमेटी के साथ मीटिंग की तो उस समय वहां के सदस्यों ने हरियाणा की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में बहुत इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं और हरियाणा में बिजली की भी कोई कमी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा प्रांत सारे हिन्दुस्तन में नम्बर एक पर है। (ाोर एवं विघ्न) स्पीकर साहब, मैं किसी पार्टी के या किसी आदमी की काट नहीं कर रहा। मैं सच्ची बातें कर रहा हूं। इसी तरह से प्रोफैसर परमानन्द डिस्ट्रिक्ट जींद का लोकदल का प्रेजीडैंट है। वह बैकवर्ड क्लास से संबंध रखता है उसको लोकदल की तरफ से टिकट दिया गया था लेकिन लोकदल वालों ने उससे टिकट छीन कर श्री सतबीर सिंह मलिक को दे दीं उस गरीब आदमी ने इन लोकदल के भाईयोंने ने टिकट देने के बाद छीन ली। फिर ये यहां पर बात करते हैं कि हमने हमारी पार्टी से बहुत

से गरीब लोगों को टिकट दी है। स्पीकर साहब, जिला जीन्द में कांग्रेस पार्टी ने एक बनिए को टिकट दिया, एक पंडित को टिकट दिया और कलायत से एक हरिजन भाई को टिकट दिया। इसके अलावा सफीदों से मुझे टिकट दिया। इसी प्रकार से जींद जिलें में तीन जाटों को कांग्रेस की टिकट दी गई थी। मेरे अपोजी ान भाईयों ने मेरा हलका देखा होगा और उनका पता होगा कि चौधरी भजन लाल जी की सरकार आने के बाद मेरे हल्के के किसानों की हालत बहुत अच्छी है। मेरे हल्के में चौधरी भजन लाल जी की सरकार आने के बाद छोटे मोटे खड्डी के सिलाई के सैंटर खुल हैं और जुराबे, बनियान वगैरह बनाने का सैंटर भी मेरे हल्के में है। इसके अलावा वहां पर आंगनवाडी का सैंटर सरकार खोलने जा रही है। इसके साथ साथ मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि जींद में भी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए सरकार लोगों को प्रोत्साहन दे रही है ताकि वहाचं हर छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाने से बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। स्पीकर साहब, सेठ राम दास धमीजा ने जो अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर करने के लिए जो रैजोल्यू ान पे ा किया है मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर किया जाए ताकि हरियाणा प्रान्त के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। यदि अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया जाए तो वहां पर लोग अपने छोटे उद्योग भी

लगा सकेंगे। इसके अलावा स्पीकर साहब मैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में कहना चाहता हूं।

स्पीकर साहब 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में यहां पर इन्होंने बहुत कुछ कहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब इनका अढाई साल या तीन साल का समय था इन्होंने कौन सा सूत्र चलाया था। जिस किसान की आवाज ये आज लगाते हैं उसी किसान के सम्बंध में मैं पूछना चाहता हूं कि जब इनका राज था तो इन्होंने किसान के लिए क्या किया था। ये वे दिन भूल गए हैं। ..... यदि वे 20 सूत्री कार्यक्रम को नहीं मानते तो फिर मैं यही समझता हूं कि कोई सूत्र है ही नहीं जिसके अधीन कोई काम किया जा सकता है। जिस समय हमारी सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम चालू किया था तो हरिजनों को प्लाट दिये गये थे लेकिन जब आपकी सरकार आई तो आपने उन लोगों से वे प्लाट छीन लिए। आज गांव के अंदर जब भी बडे बडे अधिकारी जाते हैं या सी0एम0 साहब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारी से प्लाट छीन लिए गए हैं। वे हमें वापिस करवाए जायें। स्पीकर साहब जो धमीजा साहब की तरफ से प्रस्ताव आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस सरकार ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है इसलिए मैं सरकार का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री कंवल सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। .... के बारे में बात कही है। हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब हमारी तरफ से ..... का नाम लिया

जाता है तो इनको एतराज होता है। यहां पर जो ..... का नाम लिया गया है, कार्यवाही पर उसको भी रहने दिया जाए और ..... जी का भी नाम रहने दिया जाये हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्षः (दोनों) नाम एक्सपंज कर दिये जायें।

श्री कंवल सिंहः हमें कोई ऐतराज नहीं है, दोनों का नाम रहने दिया जाये।

श्री अध्यक्षः यह तो मैंने देखना है कि कार्यवाही में क्या रहना है और क्या नहीं।

चौधरी साहब सिंह सैनीः स्पीकर साहब इन्होंने .... जी का नाम लेते हुए उनके संबंध में कहा है .....। इसलिए मेरी आपसे रिकवैस्ट है कि उस को भी कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री अध्यक्षः चौधरी चरण सिंह जी ने संबंध में जो कुछ कहा गया है वह एक्सपंज कर दिया जाये।

डा0 औम प्रका ा भार्माः स्पीकर साहब, सदन में श्री राम दास धमीजा की तरह से प्रस्ताव आया है कि जिला अम्बाला की तहसील को इंडस्ट्रीज के लिहाज से बैकवर्ड घोशि किया जाये। उस पर इस सदन में चर्चा चल रही है। स्पीकर साहब, मैं

अपनी बात भुरू करूं उससे पहले मुझे एक भोर याद आ गया है –

चन्द वो भी हैं देते हैं जो तस्वीर बिगाड़,

एक वह है जिन्हें तस्वीर बना आती है।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः मुझे भी एक भोर याद आ गया है–

एक ही उल्लू काफी है बरबाद गुलिस्तां करने को,

हर भााख पै उल्लू बैठा है, अन्जामें गुलिस्तां क्या होगा।

श्री राजे ा भार्माः स्पीकर साहब, इसी के साथ साथ एक भोर और हो जाये।

हम तो अन्धेरे में चिराग जलाते फिरते हैं,

उनकी यह साजि ा कि यह सूरज भी गुल हो जाये।

डा0 ओम प्रका ा भार्मा (जगाधरी): स्पीकर साहब मैं जगाधरी कांस्टीच्यूऐंसी की नुमायंदगी करता हूं। मेरा हल्का इंडस्ट्रीयल टाउन है। वहां पर छोटी बडी कई इन्डस्ट्री लगी हुई हैं वहां पर बर्तन बहुत बनाये जाते हैं। बर्तनों की वजह से सारे भारत में नाम कमाया हुआ है। मगर आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड रहा है कि सरकार की तरफ से उनकी और कोई ध्यान

नहीं दिया जा रहा जिसके कारण उनकी हालत दिन व दिन बिगडती जा रही है। (ाोर) विपक्ष के भाई सांप निकल जाने के बाद लकीर को पीट रहे हैं

मास्टर ि ाव प्रसादः हम विपक्षीय हो गए और आप पक्षीय हो गए। (ाोर)

डा0 ओम प्रका ा भार्माः स्पीकर साहब, मेरे हल्के की बद किस्मती कहिए या कुछ और कहिए आज वहां की इंडस्ट्रीज की हालत बिगडती जा रही है और यह वही इंडस्ट्री है जिसने सारे भारत वर्श में नाम कमाया हुआ है। आज वहां इंडस्ट्रीज तबाही की तरफ जा रही हैं। उसका अगर कुछ कारण है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। (ाोर) मैं उसी हल्के की नुमायंदगी करता हूं (ाोर)

श्री अध्यक्षः देखिए जब आप लोग बोलते हैं तो इनकी तरफ से कोई भाोर भाराब नहीं होता। आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। जब ये बोल रहे हैं तो आप बीच में कुछ न बोले। इनको भी अपनी बात कह लेने दीजिये।

डा0 ओम प्रका ा भार्माः स्पीकर साहब, इंडस्ट्रीज और उद्योग धंधे की हमारे इस भाहर में काफी रूकावट पड गई है और उसका मेन कारण है सेल्ज टैक्स। सेल्ज टैक्स की चोरी के लिये मेरे विपक्षीय भाई हमारी सरकार को दोशी ठहराते हैं लेकिन मैं इस बात को उल्टा कर यह दोश विपक्षी भाईयों पर डालता हूं

क्योंकि टैक्स की चोरी के लिये ये ही लोग जिम्मेवार हैं। जब टैक्स लगता है तो वह कंज्यूमर्ज पर ही पडता हैं (व्यवधान)

Sh. Mangal Sein: How is it relevant to allege the opposition party ?

डा0 औम प्रका ा भार्मा: डा0 साहब आप सुन तो लें मैं आपकी ही बात का जवाब दे रहा हूं जो लोग चोरी करते हैं, अगर आप समझते हैं ..... तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। (व्यवधान)

श्री मंगल सैन: ..... (व्यवधान)

डा0 औम प्रका ा भार्मा: ..... (व्यवधान) स्पीकर साहब, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पडना चाहता। .... (व्यवधान)

श्री मंगल सैन: .... (व्यवधान)

डा0 औम प्रका ा भार्मा: स्पीकर साहब, इस बार भी मैं इन्हीं लोगों को हरा कर आया हूं, इन लोगों को इसी बात का दुख है।

Mr. Speaker: Please take your seat now. You will continue on the next day.

The House stands adjourned* till 9.30 a.m. tomorrow the 18th March, 1983

***13.30 hrs.**

(The Sabha then adjourned* till 9.30 a.m. on Friday, the 18th March, 1983)

ANNEXURE

Construction of water works in Adampur and Gohana Constituencies

***106. Sh. Kitab Singh:** Will the Minister of State for Public Health be pleased to state-

(a) the number of water works constructed in Adampur and Gohana Contituencies separately during the period from 1-7-1979 to 30-10-1982 together with the expenditure incurred thereon separately;

(b) whether there is any proposal under considertaion of the Government to supply drinking water to such villages where the same is not available in the State if so, the time by which the water is likely to be supplied; and

(c) whether the Government proposes to provide flush system in the Rural Areas in the State ?

Chief Minister (ch. Bhajan Lal):

(a)	No. of water works construected during 1-7-1979 to 30-10-1982 Expenditure incurred (Rs. in lacs)	Adampur - 7	Gohana – 4 (under executiaton)

(b)	Yes, a Master Plan has been has been formulated for the entire State with the object of providing water facilities to all villages by March 1981 subject to availablility of funds.
(c)	No.